हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 मार्च, 2008

खण्ड-1, अंक-9

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 19 मार्च, 2008

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)1
वाक-आऊट	(9)12
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(9)14
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(9)21
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)22
अनुपस्थिति सम्बन्धी सूचना	(9)23
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट	(9)23
विधान कार्य—	
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2008	(9)25
वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा	(9)27
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) द्वारा	(9)32
वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)32
सदस्य का नाम लेना	(9)66
वाक-आऊट	(9)67
वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)68
बैठक का समय बढ़ाना	(9)70
वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)70

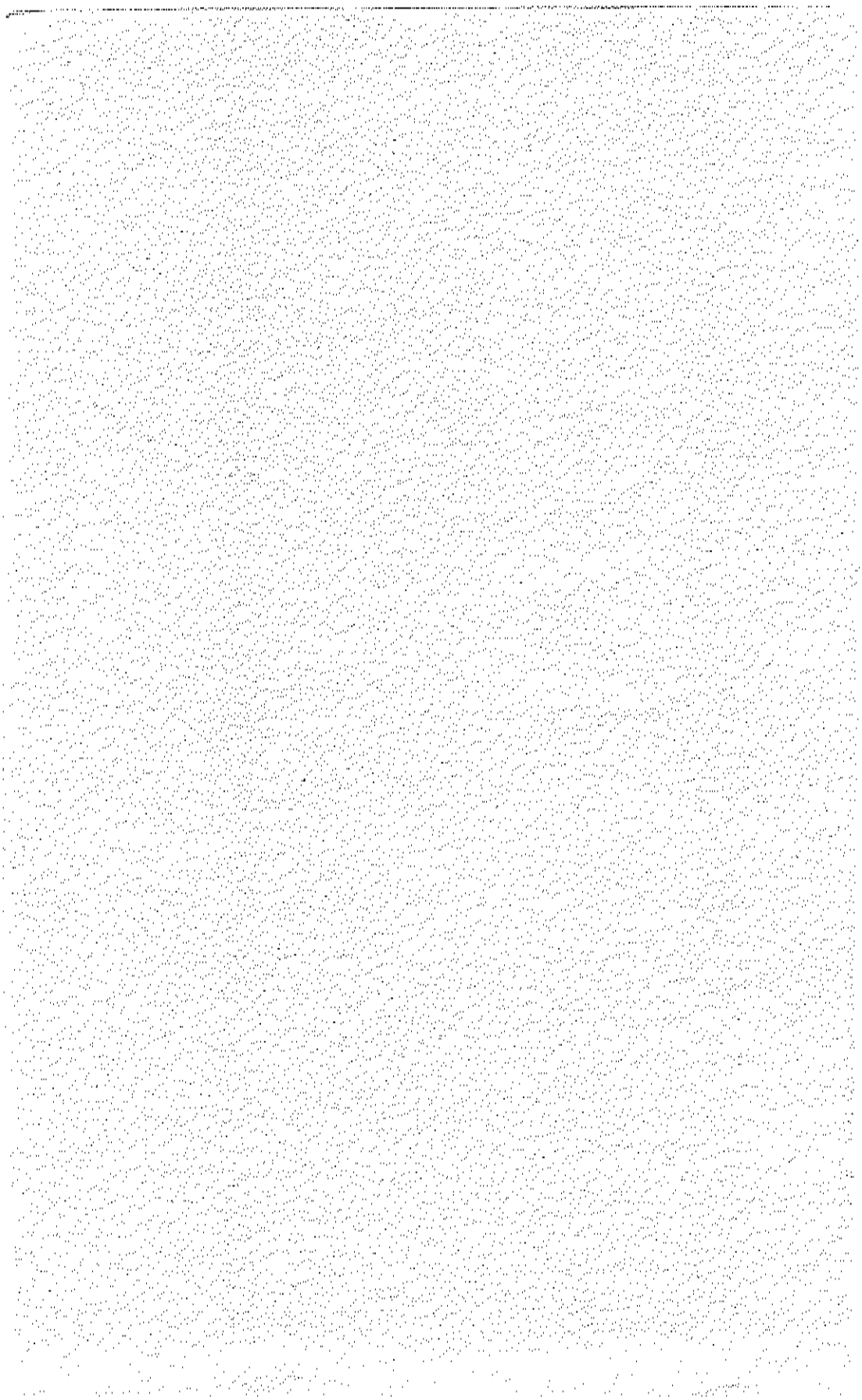

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 19 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 949

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती राज रानी पूनम सदन में उपस्थित नहीं थीं।)

Repair of Roads

***875. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair following roads in Bhiwani which were earlier built by HSAMB :—

(i) Jitu Wala Johar, Shyam Bagh to Dinod By-pass ;

(ii) Jitu Wala Phatak (Railway Crossing) to New Grain Market ; and

(iii) Meham road to Village Paluwas and Nathuwas ?

Urban Development Minister (Sh. A.C. Chaudhry) : No, Sir.

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, भिवानी में जीतू वाला जोहड़, श्याम बाग से दिनोद बाई पास तक, जीतू वाला फाटक से नई अनाज मंडी तक और महम रोड का थोड़ा-सा पोरशन ये तीनों सड़क एक-एक किलोमीटर से भी कम हैं जिनकी रिपेयर होनी है। इन रोड्स के खराब होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर इन तीनों सड़कों की रिपेयर हो जाए तो इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी और सरकार के द्वारा जो अच्छे काम हो रहे हैं उनमें एक और अच्छा काम यह भी हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि क्या वे इस बारे में विचार करेंगे?

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर साहब, जनरल डिवैल्पमैंट के मेजर प्रोजैक्टस स्टेट के द्वारा सुपरवाइज और डायरैक्ट होते हैं। इन सड़कों की तीन हिस्सों में माईनर रिपेयर मेरे आदरणीय सदस्य ने कही है। इन्होंने कहा है कि यह एक-एक किलोमीटर की रिपेयर है लेकिन इसकी जानकारी सरकार के पास तो नहीं हो सकती लेकिन फिर भी यदि माननीय सदस्य ने कहा है तो मैं इनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ और सरकार की तरफ से म्यूनिसिपिल कमेटी को हिदायत कर दूँगा कि वह इन तीनों सड़कों की रिपेयर को जल्दी से जल्दी करवाए।

श्री सोमवीर सिंह : स्पीकर सर, लोहारू के अंदर जो होस्पिटल को रोड जाती है उस पर आम आदमी आता-जाता है उस सड़क की काफी समय से बहुत बुरी हालत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस सड़क की रिपेयर करवाने का आश्वासन देंगे?

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर साहब, बात तो भिवानी की खासकर पर्टीकुलर तीन रोड्स की चल रही है लेकिन हमारे आदरणीय सदस्य ने लोहारू की रोड के बारे में भी जानकारी चाही है। ये मेरे सर्वप्रिय साथी हैं इसलिए अगर ये मुझे इसके बारे में पहले से ही बता देते तो शायद इनको सवाल करने की नौबत भी न आती। मैं आज ही हिदायत कर दूँगा कि इनकी उस सड़क की फौरी तौर पर रिपेयर करवा दी जाए।

श्रीमती सुमिता सिंह : स्पीकर साहब, शहरों के अंदर बहुत सी ऐसी अनअथोराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां पर 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी है। वहां पर लोगों के घर बन चुके हैं किन्तु हम वहां पर सड़कों की, पानी की और सीवरेज की सुविधा उन लोगों को नहीं दे सके क्योंकि वे कॉलोनीज अनअथोराइज्ड हैं। संबंधित म्यूनिसिपल कमेटीज ने इस बारे में रैजोल्यूशन भी पास करके भेज दिए हैं और अब ये रैजोल्यूशन टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट के पास आ चुके हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या वे ऐसा कोई डिसीजन करने वाले हैं कि इन अन-अथोराइज्ड कॉलोनीज में भी सरकार सड़क, नालियाँ और सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाएगी?

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर साहब, बात तो रोड्स की चल रही है। लेकिन मेरी आदरणीय बहन ने अनअथोराइज्ड कॉलोनीज को लेकर भी अपना सवाल खड़ा कर दिया। ठीक है मैं इस बात की तो मान्यता दूँगा कि जब घर का मालिक न हो तो चोर चोरी भी करेगा, सेंध भी मारेगा और अगर सम्भव होगा तो वह स्प्रिटलर ग्रुप भी खड़ा करेगा। स्पीकर साहब, पिछले शासनकाल में अनअथोराइज्ड कॉलोनीज की मशरूम ग्रोथ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि फ्लोर ऑफ दी हाउस पर किसी एक केस को कोट करके पर्टीकुलर कोई जवाब देने बारे कोई कमिटमैंट करना वाजिब नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर सुनिश्चित करना चाहूँगा कि सैशन के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि जितनी भी मशरूम ग्रोथ हुई हैं, हैफेजर्ड ग्रोथ शहरों में हुई है। उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी पोलिसी डिसीजन में कहा कि जहां-जहां कम्प्लीट आबादी हो चुकी है वहां हम कोई भी सख्त कदम उठाने की नहीं सोच रहे हैं। यह जरूर है कि जब कोई रास्ता बनाएंगे, सीवरेज डालेंगे, पानी की लाइन डालनी होगी, ड्रेनेज का सिस्टम तैयार करना होगा तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो कॉलोनीज की

मशरूम ग्रोथ है, जो छोटी-छोटी सी यूनिट्स हैं उनको जरूर प्लैनआउट कर लें। फिर वहां के प्रतिनिधियों से बात करके उनको मोटीवेट करके हम कोई रास्ता निकाल पाएंगे।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि तावडू हल्के की सड़कों की हालत बहुत खराब हुई पड़ी है। अनाज मंडी के सामने से आदमी मजबूर होकर साइड में से जाता है। सोहना रोड से तावडू हल्के की एंट्री है उधर रिवाड़ी रोड भी निकलता है, बावल और पटौदी रोड भी निकलते हैं, मोहम्मदपुर अहीर रोड हैं ये सारी सड़कें खराब पड़ी हैं। मुझे रोज-रोज इस बारे में कहना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आप भी कहते हैं कि मैं रोज सड़कों की बात करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वहां के आढ़ती लोग भी सड़कों की बुरी हालत के कारण बहुत परेशान हैं। पिछली सरकार के समय में जो सड़कें बनीं थीं वे आज भी अच्छी बनी हुई हैं।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए क्योंकि आज मेवात में बहुत काम हुए हैं। आज तक तो मेवात इलाके का कोई नाम लेवा नहीं था। सिर्फ वोट लेने के अलावा वहां किसी ने कुछ नहीं किया था। पिछली सरकार के ये बहुत गुणानुवाद कर रहे हैं लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर सिविक बॉडीज में पिछली सरकार ने 230 करोड़ रुपये लगाए थे जबकि आज की कांग्रेस की सरकार ने तीन साल के अर्से में 777 करोड़ रुपये लगाए हैं। जहां तक मेवात एरिया की बात है तो इस बारे में हमारी सरकार बहुत चिंतित है। मेरे भाई खुद इस बात के गवाह हैं कि मेवात के मामले में मुख्यमंत्री जी ने मुझे खुद स्पैशल उस एरिया की ग्रीवैंसिज देखने के लिए भेजा है और मैंने उस एरिया की एक-एक सड़क को खुद देखकर अपने तौर पर ही इतने काम करवा दिये हैं। मेवात की जितनी भी सड़कें टूट गई थी उन सब को आइडैंटिफाई करके उनके बाकायदा ऐस्टीमेट्स तैयार होकर टैंडर्ज हो चुके हैं। मेरी कोशिश है कि बरसात से पहले-पहले उन सड़कों को मुकम्मल करवा दें ताकि बरसात में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मेवात में मंत्री जी ने हमें जो कुछ दिया है उसे हम छुपा नहीं सकते। नकली सोने की ईंटों के बोर्ड जरूर लगे हैं। उससे हमारे नाते रिश्ते भी बंद हो चुके हैं। यदि ऐसे ही विकास के काम करवाए जाएंगे तो हमारे मेवात के इलाके से लोगों के रिश्ते नाते बंद हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : रोड का सवाल चल रहा है और आप पता नहीं कहां-कहां की बातें कर रहे हैं। आप चेयर की परमीशन लेकर खड़े हुआ करें।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अम्बाला छावनी में 80-90 परसैंट सड़कों के काम करा दिये हैं। एक सड़क बस स्टैंड से बड़ी सब्जी मंडी बत्तरा पैलेस से निकलती है उस सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। अगर उस सड़क को मंत्री जी बनवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रान्त के अंदर हर सुविधा देना सरकार ने सुनिश्चित करने का निश्चय किया हुआ है। उसी नाते से आज न सिर्फ म्यूनिसिपल फण्ड से बल्कि स्टेट

[श्री ए०सी० चौधरी]

फण्ड से भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां-जहां भी हमने कोई काम करना है हम काम करेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से जितनी सड़कें गांव से शहर तक बना दी गई हैं वह अपने आप में रिकॉर्ड की बात हैं। मुझे नहीं पता आदरणीय साथी मार्केटिंग बोर्ड की किस सड़क का जिक्र कर रहे हैं या किस ऑटोनोमैस बॉडी का जिक्र कर रहे हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इनकी नॉलेज में है तो वे मुझे लिखकर दे दें हम जरूर विचार करेंगे। यह भी जरूरी नहीं कि यह सड़क मेरे विभाग की हो अगर सरकार के किसी भी विभाग का काम होगा तो मैं अस्सिट करूंगा और अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार कोई ऐसी प्लानिंग कर रही हैं कि पब्लिक हैल्थ विभाग के साथ अर्बन लोकल बॉडीज का कोई तालमेल हो क्योंकि म्यूनिसिपल काउंसलर हाउस में रेजोलूशन पास करके अपने वार्डों में सड़कें बनवा लेते हैं, जब वे सड़कें बन जाती हैं तो उनके नीचे न सीवर की लाईन होती है न पानी की लाईन होती है और पब्लिक हैल्थ विभाग की तरफ से तो उस सड़क को तोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से सरकार के पैसे का काफी नुकसान होता है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बगैर सीवरेज और पानी की लाईनें बिछाने के सड़कें न बने।

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर सर, हम पब्लिक के दिए हुए टैक्सिज के कस्टोडियन हैं और हमारा भरसक प्रयास है कि प्रदेश का एक-एक पैसा इस तरीके से लगे जो सीधा जनहित से जुड़ा हो। लेकिन आदरणीय बहन जी को इस बात की स्वीकारोक्ति देनी होगी कि सीवरेज की पहले मांग नहीं थी लेकिन अब ज्यों-ज्यों शहरीकरण बढ़ा है सीवरेज की भी मांग होने लगी है इसलिए जो पुरानी सड़कें पहले बनी हुई थी उनके लिए हम यथासंभव यह कोशिश कर रहे हैं कि कच्चा बर्म में ही खुदाई करके सीवरेज डाल दिए जाएं लेकिन जहां रोड की विडथ ही 10-12 फीट हो तो नेचुरली वहां के लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए सड़क को तोड़ना पड़ता है। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि जहां भी ऐसी कोई तोड़फोड़ होगी तो उसकी रिपेयर को हम प्रियोरिटी देंगे।

Repair of Pump Houses

***941. Major Nirpender Singh Sangwan :** Will the Irrigation Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair/replace the defective machinery/pump sets installed on the Loharu Lift Irrigation Canal System; if so, the time by which the defective machinery/pump sets are likely to be repaired/replaced ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the dilapidated buildings/structures of the Pump Houses constructed on the Loharu Lift Irrigation Canal System; if so, the time by which the repair of above said buildings/structures is likely to be carried out ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) जी हाँ श्रीमान् जी।

लोहारू उठान सिंचाई नहर प्रणाली पर लगी खराब मशीनरी/पम्प सैटों की मरम्मत/बदलने का कार्य पहले से ही प्रगति पर है यह कार्य एक वर्ष के अन्दर पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् जी।

पम्प हाउसों के लिए निर्मित जीर्ण-शीर्ण इमारतों/ढांचों की मरम्मत का कार्य पहले से ही शुरू किया हुआ है और यह कार्य एक वर्ष के अन्दर पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो पम्पों की रिप्लेसमैंट हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वगैरा हैं उन पर सरकार 510 लाख रुपये खर्च करेगी, इसी प्रकार से 160 लाख रुपये रिहैब्लिटेशन ऑफ बिल्डिंग और रिस्ट्रक्चर ऑफ पम्प हाउसिज पर खर्च करेगी और 85 लाख रुपये की राशि अब तक सरकार ने पम्पों की रिप्लेसमैंट पर खर्च कर ली है और 20 लाख रुपये की राशि बिल्डिंग और स्ट्रक्चर की रिहैब्लिटेशन पर खर्च कर ली है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, अभी वहां पर जो पम्पस हैं वे इतने खराब हैं कि जितना पानी उनमें आता है उस पानी को वे पम्पस उठाकर आगे नहीं फैंक सकते। जिसकी वजह से वहां पर पानी नहर की साईड से नीचे खेतों में उतर जाता है और साथ लगते जितने खेत हैं उनमें खड़ा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि एक तो वहां पर रिजरवायर का बन्दोबस्त किया जाए ताकि नहर का पानी खेतों में इकट्ठा न होकर उस रिजावायर में इकट्ठा हो जाए।

श्री अध्यक्ष : जो पम्पस हैं वे टैंक में लगे हैं क्या?

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, वहां पर खराब पम्पस के लिए कोई रिप्लेसमैंट की व्यवस्था भी विभाग ने नहीं की है। कोई न कोई रिप्लेसमैंट होना चाहिए ताकि जो पम्पस खराब हों उनको आईडैंटिफाई करके रिप्लेस कर दिए जायें। पानी की स्केरसिटी है और पानी पीने के लिए भी नहीं पहुँचता इसलिए जितने भी पम्पस खराब हैं उनको जल्द से जल्द ठीक करवाये जाने की खास जरूरत है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं सहमत हूँ कि पिछले कई सालों से लोहारू उठान सिंचाई नहर प्रणाली में पम्पस की रिप्लेसमैंट व बिल्डिंग और स्ट्रक्चर की मरम्मत नहीं हुई, इनकी यह बात वाजिब है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सिंचाई मंत्री और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर बुलाकर निर्देश दिए थे कि लोहारू कैनाल सिस्टम में 32 पम्प हाउसिज हैं और इन पर 275 के करीब पम्पस और एलाइड मशीनरी लगी हुई है। इनमें से 30 जो मुख्य पम्पस हैं उनके रिप्लेसमैंट की जरूरत है। 3 पम्पस की रिप्लेसमैंट के लिए हमने टैण्डर बुला लिए हैं और टैण्डर का प्रोसैस किसी भी दिन शुरू हो जाएगा तथा वे रिप्लेस हो जाएंगे। इसके इलावा 7 और पम्पस हैं

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

जिनके टैण्डर्ज हमने मंजूर कर दिए हैं Tenders are in the process of getting floated बाकी के जो 20 पम्पस हैं इनके एस्टीमेट्स हमारे पास जल्दी ही आ जाएंगे उसके बाद हम उनके टैण्डर बुला लेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि 5 पम्पस के एल०टी० डिस्ट्रीब्यूशन बोर्डस की, मोटर्स की और इसी प्रकार 7 और पम्पों के एल०टी० डिस्ट्रीब्यूशन बोर्डस की रिप्लेसमैंट की जरूरत है और इनमें से 7 पम्पस के एल०टी० डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मंजूर कर दिए गए हैं, उनके बहुत जल्दी ही टैण्डर कर देंगे उसके बाद उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। 5 विभिन्न पम्पों की मोटर्स मंजूर कर दी गई हैं और उनके एस्टीमेट्स तैयार होकर हमारे पास आ रहे हैं, यह काम भी जल्दी ही कर देंगे। 60 पम्पस ऐसे हैं जिनकी रिहैबिलिटेशन और रिपेयर की जरूरत है जिसमें से 25 पम्पस का मैटीरियल हमको मिल गया है और उस पर इस समय काम जारी है। अध्यक्ष महोदय, बाकी के 35 पम्पस बचे हैं उनका मैटीरियल हम मंगवा रहे हैं। इस प्रकार 60 के 60 पम्पस भी हम मरम्मत करेंगे और जो समय सीमा दी गई है इसके अंदर सारे कार्य पूरे कर दिए जाएंगे। It is elaborate exercise that the Government is undertaking, Hon'ble Chief Minister was concerned इस उठान सिंचाई परियोजना में सारा पानी लिफ्ट से जाएगा और अगर पम्पस नहीं चलेंगे तो किसानों के लिए और आम आदमी के लिए उसका महत्त्व नहीं रह जाता। 510 लाख रुपये की इतनी बड़ी राशि इन पम्पस की रिप्लेसमैंट के लिए और 160 लाख रुपये बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के लिए सिंचाई विभाग ने खर्च करने का निर्णय किया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ समय जरूर लगेगा और जैसे ही सारे काम पूरे हो जाएंगे, यह उठान सिंचाई परियोजना उसी शक्ल में आ जाएगी जैसी ओरिजनल थी।

Major Nirpender Singh Sangwan : Hon'ble Chief Minister has been kind enough to look into Loharu Canal System. It was almost gone when he took over and every time when I have requested to him, he has paid adequate attention to this. My only concern is that whatever these repairs are required they should be done on priority basis because it is the life line of Southern Haryana as well as my Constituency.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता के साथ मैं अपने आप को जोड़ते हुए इनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जैसा हमने लिखित जवाब दिया है कि यह हमारी प्राथमिकता का हिस्सा है और जो समय अवधि हमने बताई है उस अवधि में ये काम पूरे कर दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि कल हमारे सिंचाई मंत्री ने कहा था कि जो पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ था कि उस एरिये में वाटर एलाउंस घटा दिया गया था हमने उसको बढ़ाया है। रिपेयर की प्राथमिकता तो हमारी है ही। होंसी बुटाना लिंक नहर का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है और इस एरिये को अपने हक का पूरा पानी मिलेगा।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो यह वाटर एलाउंस बढ़ाया गया है मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ-साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम में जब बिजली चली जाती है तो जो पानी सप्लाई किया जाता है वह बेकार चला जाता है और आगे नहीं पहुँच पाता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय

मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकार लिफ्ट इरीगेशन के लिए कोई जनरेटर सैट्स का प्रावधान करेगी ताकि बिजली चली जाए तो इन जनरेटर सैट्स से पानी चलाया जा सके।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार का अभी हमारा कोई निर्णय नहीं है इसलिए माननीय साथी सिंचाई मंत्री को लिखकर भिजवा दें तो हम इस पर अवश्य गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, एक साल पहले मैंने लोहारू कैनाल के पम्प हाउस नं० 1 पर जाकर देखा था जिसकी हालत ठीक नहीं थी और मैंने मुख्यमंत्री जी को इस बारे पत्र लिखा था जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था और आज मंत्री जी ने जो कुछ लोहारू कैनाल के बारे में बताया बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से लोहारू कैनाल के पम्प हाउसिज की रिपेयर का काम चल रहा है उसी तरह से जूई कैनाल और निगाणा फीडर के पम्प हाउसिज की भी रिपेयर करने की आवश्यकता है। क्या इस प्रकार की कोई प्रपोजल सरकार ने जूई कैनाल और निगाणा फीडर के पम्प हाउसिज की रिपेयर करने के बारे में बनाई है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आप सभी जानते हैं कि एक समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और चौधरी बंसी लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय भिवानी लिफ्ट कैनाल इरीगेशन सिस्टम का निर्माण किया गया था। उसके बाद वर्षों तक इसकी देखभाल नहीं की गई। खासतौर पर पिछली सरकार के समय में 1999 के बाद इस सिस्टम की काफी अनदेखी की गई। मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि वे इस बारे में सिंचाई मंत्री महोदय को लिखकर भिजवा दें, मैं भी उनसे आपके काम के लिए अनुरोध करूंगा। आज सिंचाई मंत्री महोदय सदन में नहीं हैं, वे किसी कारणवश बाहर गये हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितनी भी उठान सिंचाई परियोजनाएं हैं उनकी प्रोपर देखरेख होनी चाहिए और वे सभी चालू हालत में होनी चाहिएं ताकि किसान पूरा लाभ उठा सकें। इसलिए मेरे माननीय साथी लिखित में अपना सवाल दे दें उस पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा और पैसे की जरूरत होगी तो नसैसरी सैंक्शन ले लेंगे।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि 2005 के बाद भिवानी क्षेत्र में सिंचाई की तरफ उचित ध्यान दिया गया है। मेरे हल्के में पालवास माईनर को रिपेयर किया गया है और सांगा माईनर पर बहुत अच्छा काम चल रहा है और रूपगढ़ में आर०डी० 7000 पर पम्प हाउस की मंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। He was kind enough and also visited that area लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। वह ऐसा इलाका है जहां पर 35 साल से सिंचाई ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। वहां पम्प हाउस के लिए सरकार ने मंजूरी तो दे दी है लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वहां पर कब तक काम शुरू होगा और कब तक वह माईनर बनकर तैयार हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष : भारद्वाज साहब, क्या 35 साल पहले वहां ठीक से सिंचाई होती थी?

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जो हिस्ट्री गांव वालों से मुझे मिली है उसके अनुसार वहां 35 साल से ठीक प्रकार से सिंचाई नहीं हो रही है। वहां पर काफी पैसा विभिन्न स्कीम्ज के तहत खर्च किया गया लेकिन that was a wasteful expenditure. इसका मेन कारण यह

[डॉ० शिव शंकर भारद्वाज]

है कि वह रेतीला इलाका है और नहर बहुत गहरी है जिसके कारण नहर रेत से अंट जाती है। मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है। यही कारण है कि वहां पर पम्प हाउस के द्वारा क्लोज पाईपस से पानी देने की कवायद जारी है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्रश्न है। यदि मंत्री जी वहां गये हैं और वहां पम्प हाउस के लिए मंजूरी दी गई है तो उसको बनाया भी जायेगा। इस बारे में ये सिंचाई मंत्री जी को लिखित में दे दें इनको जवाब दे दिया जायेगा कि वहां पर कब काम शुरू किया जायेगा और कब तक पम्प हाउस बनकर तैयार हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह जून : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मेरे हल्के में सोहटी माईनर के लिए मुख्यमंत्री जी ने डेढ़ साल पहले 1.82 करोड़ रुपये सैंक्शन किए थे और वे पैसे आ भी गये लेकिन न तो किसानों को मुआवजा मिला है और न ही उस पर काम शुरू हुआ है।

श्री अध्यक्ष : जून साहब, यह सवाल पम्प हाउस से रिलेटिड है। आप कैप्टन साहब को अलग से लिखकर दे देना, आपको जवाब मिल जायेगा।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पम्प हाउस पर पम्प सैट बदलने की बात है इस बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि भिवानी जिले में इस्सरवाल से मीठी गांव को पानी जाता है। वहां पर पम्प हाउस कम पानी उठा रहा था इसलिए नये पम्प लगाये गये लेकिन जो नये पम्प लगाये गये हैं वे ज्यादा पानी उठाने की बजाय पहले से भी कम पानी उठा रहे हैं। इस बारे में गांव के लोगों ने कई बार शिकायत भी की है, क्या मंत्री जी इस पर गौर करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरे माननीय साथी लिखकर सिंचाई मंत्री जी को भिजवा दें इनको जवाब दे दिया जायेगा। यदि इस पर किसी तरह की कोताही हुई है और कार्यवाही की आवश्यकता होगी तो वह भी की जायेगी।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो पुराना लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम है उसको बदलने के प्रयास किए गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम पर जो मोटरें चल रही होती हैं वे चलते-चलते जल जाती हैं जिनको ठीक कराने में दो-तीन दिन का समय लग जाता है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या मंत्री जी पम्प हाउसिज पर स्पेयर मोटर रखने का कोई प्रावधान करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम में कई बार जब लोड ज्यादा हो जाता है या बिजली की ट्रिपिंग हो जाती है तब इस प्रकार की घटनायें घट जाती हैं। जहां तक स्पेयर मोटर्ज का प्रश्न है तो यह एक बजटरी इश्यू है क्योंकि हर मोटर के ऊपर लागत आती है और इस समय हमारे पास संसाधन सीमित हैं परन्तु फिर भी माननीय सदस्य जहां पर इस प्रकार की जरूरत महसूस करें उस बारे में हमें लिखकर भिजवा दें तो हम यह इंश्योर करवा लेंगे कि जहां बिजली की सिचुएशन प्रीफेरियस है और जहां एडीशनल मोटर लगनी ही चाहिए वहां पर हम जरूर विचार करके लगवायेंगे।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि ये जो नई मोटरें लगा रहे हैं और नये पम्पिंग सैट्स

लगाये जा रहे हैं उनकी कैपेसिटी पुरानी मोटरों और पुराने पम्प सैट्स से काफी कम है। मैं यह बात विशेष तौर से पम्प हाउस नम्बर 1 जो कि दादरी में इंदिरा गांधी कैनाल पर है उसके बारे में बताना चाहता हूँ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि वे इस बारे में लिखकर मंत्री जी को भिजवा दें। जिसके बारे में इन्होंने चर्चा की है उसकी कैपेसिटी की हम जांच करवाकर उसको दुरुस्त करवाने का प्रयास करेंगे।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये जो नये पम्प हाऊसिज लगाये जा रहे हैं इनमें जब बिजली चली जाती है या कोई खराबी चल रही होती है तो जो पानी आ रहा होता है वह उतरने लग जाता है। इसमें अगर किसी रिजरवायर का दोनों तरफ अरैंजमैंट हो जाये तो इससे ग्राऊण्ड वाटर टेबल रिचार्ज होगा और अगर उसमें पानी इकट्ठा होगा तो उसे वापिस पम्प भी किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जहां पर भी नये पम्प हाऊसिज हैं वहां पर उनकी साईड में रिजरवायर का बंदोबस्त करने की कोई योजना है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उस पर हम जरूर विचार कर लेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में लिखकर मंत्री जी को भिजवा दें।

F.I.R. Registered by Deputy Director Income Tax (INV)

***916. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether any F.I.R. was got registered in Civil Lines Police Station, Gurgaon by the Deputy Director of Income Tax (Inv.) against Shri Gopal Goyal resident of 436/16, Civil Line, Gurgaon on 1.2.2008 ; and

(b) if so, the contents of the F.I.Rs. alongwith the section of IPC and action taken thereon ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) जी हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) यह सही है कि मुकदमा नं० 45 दिनांक 1.2.2008 धारा 148/149/332/186/353/356 भा०द०स० थाना सिविल लाईन, जिला पश्चिम गुड़गाँवा श्री आशुतोष वर्मा, उपनिदेशक आयकर विभाग (अनुसंधान) ईकाई-1 (1) ए०आर०ए० केन्द्र ई-2 झण्डेवालान, नई दिल्ली के कथन पर गोपाल गोयल व उसके सहयोगी श्री मोती लाल, वासी वार्ड नं० 2 संगरिया राजस्थान और श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल, मुकदमा में मोती लाल पुत्र रामेश्वर वासी वार्ड नं० 2 संगरिया थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

राजस्थान को दिनांक 1.2.2008 को गिरफ्तार किया गया। दोषी गोपाल गोयल पुत्र मुरलीधर वासी मकान नं० 436/16, सिविल लाईन गुड़गाँवा व गोविंद प्रसाद अग्रवाल पुत्र बनवारी लाल, अतिरिक्त मुख्य न्यायधीश बाड़मेर राजस्थान को दिनांक 7.2.2008 को तफ्तीश में शामिल किया गया, जो सैशन जज, गुड़गाँवा की अदालत से अन्तरिम जमानत पर है। अन्य दोषियान की पहचान की जा रही है मुकदमा अनुसंधानाधीन है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो इन्कम टैक्स की रेडिंग पार्टी थी उसके ऊपर न केवल गुड़गांव में बल्कि उसी दिन सिरसा में भी इन लोगों ने जो कि बहुत बड़े गैंगस्टर हैं अपने समर्थकों के साथ मिलकर पलटवार करके, उनके साथ झगड़ा करके, उनके खिलाफ फायर आर्म्स का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा संगीन अपराध किया है। अध्यक्ष महोदय, जिस दफा के तहत उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया उस बारे में माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया है। इसके अलावा जिस तरह की हिमाकत इन्होंने सिरसा में की और जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों को वहां पर इकट्ठा करके कानून को अपने हाथ में लेकर श्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा वहां पर छिपाकर रखे गये जमीन जायदाद के दस्तावेज, जरूरी कागजात, धन और जेवर सबको लेकर वहां से फरार हो गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इसके अलावा भी इन्होंने गुड़गांव और सिरसा में किन्हीं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। क्या मंत्री महोदय इनका सारा ब्यौरा सदन में देंगे और इसके अलावा क्या यह बात भी सही है कि वे सिरसा से जरूरी कागजात और दूसरा सामान लेकर भागने में भी सफल हो गये थे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि इसके अलावा भी दो मुकद्दमें हैं जो कि सिरसा में दर्ज हुए हैं। एक केस एफ०आई०आर० नं० 78, दिनांक 31.1.08 under section 332, 353, 186, 147, 149, 382, 294, 395 IPC श्री मुंशी राम, जनरल मैनेजर, ऑडिट इन्कम टैक्स डिपार्टमैंट ने दर्ज करवाया है। दूसरा मुकदमा एफ०आई०आर० नं० 77, दिनांक 31 जनवरी, 2008 को इंडियन पिनल कोड की विभिन्न धाराओं के तहत सुखविन्द्र सिंह, कैमरा मैन ने दर्ज करवाया था। गुड़गाँव के मुकद्दमें की चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ। माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल ठीक है कि वहां पर एक आदमी लैपटॉप लेकर भाग गया था। वहां पर जो इन्कम टैक्स की हमारी टीम आई थी वह गुड़गाँव और सिरसा दोनों जगह रेड करने के लिए गई और वे अपनी फोर्स अपने साथ लेकर आये थे। उन्होंने हमारी पुलिस को सूचित नहीं किया बल्कि जब रेड हो रही थी तब हमारी पुलिस को मालूम पड़ा। शायद इसी कारण वहां से एक आदमी लैपटॉप लेकर भाग गया था। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि वह मुकदमा दर्ज है और इस बारे में जाँच जारी है।

10.00 बजे

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये वे गुनाहगार हैं जिन्होंने हरियाणा के खून पसीने की कमाई को हमारी पिछली सरकार के मुख्य मंत्री की रहनुमाई में दोनों हाथों से लूटा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब क्लैरीफाई करें कि गुनाहगार कौन हैं? गुनाहगार उसको कहा जाता है जिस पर दोष सिद्ध हो जाये। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं

यह गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, तो क्या ये श्री गोपाल गोयल के हक में बोल रहे हैं? जिनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज होती है वे गुनाहगार ही होते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, हम हक में तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन ये हमारे नेता का नाम उसमें क्यों ले रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : दलाल साहब, आप कौन से ठेकेदार लगे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी पहले गुनाह सिद्ध करके दिखाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप जीरो ऑवर में बोल लेना। आप अपनी सीट पर जा कर बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ यही ट्रेजडी होती है कि मेरा माईक बन्द कर दिया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, गुनाह की बात हो रही थी। हमारे माननीय साथी श्री नरेश शर्मा, जो कि भोलेभाले आदमी हैं, इनको मरवा कर नाले में डाल दिया था, यह तो इनकी किस्मत अच्छी थी, ये बच गये। हमारे ये साथी तो रामचन्द्र जांगड़ा को मारने लग रहे थे, ये बेचारे किस्मत से बच गये। श्री अमीर सिंह हत्याकांड में अमीर सिंह को मार दिया था और एक घण्टे के बाद मुण्ढाल में उसकी लाश मिली थी। अध्यक्ष महोदय, यह तो अमरीशपुरी वाला रोल है यह तो आखिर में ही खत्म होता है। जब तक उसका खेल खत्म नहीं होता तब तक कोई बात नहीं होती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि और कौन-कौन सी काली करतूतों के मुकदमें इस महाशय हरियाणा के दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज हैं? अध्यक्ष महोदय, सिरसा में बिजली विभाग की जमीन थी; इनके नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में, उनके मुख्यमंत्री होते हुए, इस दाऊद इब्राहिम गोपाल गोयल ने और उसके परिवार के लोगों ने..... (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, जो बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए। (विघ्न) डॉ० साहब ऐसा है दलाल साहब सप्लीमैंट्री पूछ रहे हैं। आप प्लीज बैठें। (विघ्न) दलाल साहब, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठें। इन्दौरा साहब आप अपनी सीट पर बैठें। Please take your seats. (Interruptions) इन्दौरा साहब, यह क्वैश्चन से रिलेटिड है और क्वैश्चन में उस आदमी का नाम आया हुआ है उसके सम्बन्ध में वे सवाल पूछ रहे हैं (विघ्न एवं शोर) वे उस रिजाईम के बारे में सवाल कर रहे हैं और उसका नाम ले रहे हैं। (विघ्न एवं शोर) दलाल साहब, आप अपनी सप्लीमैंट्री में उन्हें भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहें तो इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, गोपाल गोयल ने चौटाला जी के मुख्यमंत्री होते हुए उनकी देखरेख में सिरसा की बिजली विभाग की जमीन पर कब्जा किया। उस जमीन पर बिजली विभाग के घर बने हुये थे। पुलिस की रहनुमाई में दिन-दहाड़े बिजली विभाग के अधिकारियों के घरों को बुलडोजिंग की और बच्चों समेत बिजली विभाग के उन अधिकारियों को घरों से बेघर किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि उसी गोपाल गोयल ने सिरसा के अन्दर बिजली विभाग की जमीन पर जो कब्जा किया है क्या उसके खिलाफ कोई मुकद्मा दर्ज हुआ है और यदि कोई केस दर्ज हुआ है तो उसमें कौन-कौन सी दफाएं लगाई गई हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वाजिब फरमाया है इस केस में एफ०आई०आर० नं० 416, दिनांक 14.6.2005 अण्डर सैक्शन 448, 427, 506, 148, 149, 467, 395, 420 of Indian Penal Code and Section 25, Section 54, Section 55 of Armed Act पुलिस स्टेशन, सिरसा के अन्दर दर्ज है। श्री एम०आर० रेहलान, एक्सीयन, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण लिमिटेड ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी। 4 दिसम्बर, 2004 को यह केस दर्ज नहीं होने दिया गया था। यह केस बाद में दर्ज हुआ था। बिजली विभाग की जो प्राईम मोस्ट प्रोपर्टी सिरसा शहर के अन्दर है उसमें 4 दिसम्बर, 2004 को 150 के करीब बदमाश व्यक्ति जे०सी०बी० मशीनें ले कर आए और एस०ई० के घर को गिराया। उसके बाद उस जे०सी०बी० मशीन से दूसरे इम्पलोईज के घर और कम्पलेंट सैंटरज, बिजली के बोर्डज भी गिरा दिये और इसके साथ ही रैजिडैंशियल लाईन्ज कम्पलेंट सैंटरज पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। इस मुकद्दमें में सात अलग-अलग लोगों के खिलाफ केस दर्ज हैं। उसमें गोविन्द कांण्डा ऐलिस गोविन्द गोयल सन ऑफ श्री मुरलीधर है उसको हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस केस की तफतीश में यह आ गया था कि इनका सीधा रोल नहीं पाया गया था। दिनांक 5.9.2007 को यह केस ट्रायल के लिए लगा था परन्तु हमने दरख्वास्त दी है for re-investigation of the case और रि-इन्वैस्टिगेशन की हमारी वह दरख्वास्त दिनांक 18 मार्च को लगी थी जो फरदर 4 अप्रैल के लिए ऐडजोर्न हो गई है। हमने कोर्ट से मांग की है कि इस केस में दोबारा तफतीश करने की इजाजत दी जाए। (इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे)

वाक-आऊट

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीटों पर बैठें (विघ्न एवं शोर) Nothing to be recorded. No sitting running commentary please. Mr. Indora, I warn you. No sitting running commentary at all. I warn you. Nothing to be recorded. I warn you, Mr. Indora. (Interruptions)

श्री अर्जन सिंह : स्पीकर सर, इन लोगों को भागने का कोई बहाना चाहिए। (विघ्न एवं शोर)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

श्री अध्यक्ष : डॉ० इन्दौरा, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) जो ये बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि गोपाल काण्डा .....(विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आपका सवाल आया हुआ है, नैक्सट सवाल आपका है। (विघ्न एवं शोर) किसी बदमाश आदमी के बारे में कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? (विघ्न एवं शोर)

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल के सदस्य वैल में इकट्ठे हो कर बोलने लगे)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

Mr. Speaker : Please take your seat. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, कोई मिस बिहेव नहीं हुआ है। Nothing is to be recorded. ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : * * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रामफल चिड़ाणा : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० बलवन्त सिंह : * * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, यह बहुत ही इम्पोर्टैंट प्रश्न पूछा जा रहा है और आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। आप अपनी सीटों पर बैठें। अगला सवाल आपका आ रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, आप हमारी बात सुन नहीं रहे इसलिए हम वाक-आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए।)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, ये वे लोग हैं जो एम०एल०ए० बनने के लिए एक गिरोह में शामिल हो गए हैं। इन्होंने अपनी पार्टी में दाऊद इब्राहिम तो लिया सो लिया, तैमूरलंग, मोहम्मद गजनवी, औरंगजेब, अलाऊद्दीन खिलजी भी लिए हैं। अरे ऐसी पार्टी ज्वायन करने से तो अच्छा है डूब कर मर जाओ यारो। 36 बिरादरी का गला घोंटने वाले ये लोग एस०सी० बिरादरी

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री राम कुमार गौतम]

की 10000 नौकरियां पी गए, ये ऐसी पार्टी के लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जितने जुर्म लोगों पर अपने समय में किए हैं उतने कभी किसी वक्त में नहीं हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, अजय चौटाला 1995 में डेढ़ घंटा मेरे घर पर बैठा रहा था और मुझे कहने लगा भाई गौतम मेरी पार्टी ज्वायन कर लो तो मैंने उसे कहा कि तेरी पार्टी ज्वायन करने से अच्छा है मैं कुंवारा ही कमा खा लूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी बिना वजह से सदन से वाक-आऊट करके गए हैं। आपने तो उन्हें सदन में अनुशासन रखने की बात कही थी, सदन में गरिमा बनाए रखने की बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, हम भी विपक्ष में रहे हैं। उस वक्त तो विपक्ष का नेता भी था लेकिन इनका विपक्ष का नेता भी नहीं है। हमें तो विपक्ष में बोलने नहीं दिया जाता था और जब हम बाहर जाते थे तो हाउस की अन्दर से कुण्डी लगा दी जाती थी ताकि हम अन्दर न आ सकें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये रोज बाहर भागते हैं, जब ये अन्दर आएं तो कुण्डी लगवा दी जाए ताकि ये बाहर न जा सकें। हम चाहते हैं कि ये सदन में आएं, बातें करें और कोई हैल्दी सुझाव दें ताकि हम कोई काम कर सकें। ये लोग सदन में आते हैं, हाजिरी लगाकर सदन से बाहर जाने का कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं। इनमें कोई इन्सानियत नहीं है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह गोपाल गोयल वही है जिसने दिल्ली, चण्डीगढ़ और देश के दूसरे महत्त्वपूर्ण शहरों में एम०डी०एल०आर० के नाम से हवाई यात्रा शुरू की हुई है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही गोपाल गोयल है जिसकी मात्र 10 लाख के लिए एच०एफ०सी० ने 1996 में दुकान नीलाम की थी। अगर हाँ तो अध्यक्ष महोदय, जब गोपाल गोयल ने एम०डी०एल०आर० हवाई सेवा शुरू की थी, उस बारे में भारत सरकार ने हरियाणा सरकार से इसके बारे रिपोर्ट मांगी होगी। क्या हरियाणा सरकार ने इन तथ्यों को उस रिपोर्ट में दर्शाया था?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्रश्न है। सदस्य मुझे लिखकर दे दें और मैं इस बारे में जानकारी लेकर माननीय सदस्य को लिखकर दो हफ्ते में बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आपकी कोई सप्लीमैंटरी है। (विघ्न) सुना है कि अब तो आपका उनसे सम्बन्ध भी टूट गया है। (विघ्न)

Local Area Development Tax

***891. Dr. Sushil Indora :** Will the Excise & Taxation Minister be pleased to state —

(a) whether the Govt. is collecting any tax in the name of Local Area Development ;

(b) if so, the districtwise total amount of tax collected during the period from April, 2005 to date ; and

(c) the districtwise name of the places where the amount of said tax has been utilized during the period as referred to in part(b) above ?

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) :

(क) जी हाँ, हरियाणा स्थानीय विकास कर, अधिनियम, 2000 के अनुसूची 'क' में अंकित वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में खपत हेतू प्रवेश पर उक्त कर संग्रहित किया जाता है।

(ख) स्थानीय विकास कर अधिनियम, 2000 के अधीन जिलावार व वर्षवार संग्रहित किया गया कर अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

(ग) स्थानीय विकास बोर्ड द्वारा, अनुलग्नक 'ख' में दर्शाये अनुसार एकत्रित राशि को पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों में वितरित किया गया है। लेकिन इस सम्बन्ध में यह बता पाना सम्भव नहीं है कि जिलावार किन स्थानों पर इस राशि को व्यय किया गया।

अनुलग्नक 'क'

हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर के जिलावार और वर्षवार आंकड़ों की तालिका

क्र०सं०	जिला	2005-06	2006-07	2007-08 जनवरी 2008 तक
1.	अम्बाला	2.14	3.84	2.03
2.	भिवानी	14.38	9.47	0.33
3.	फरीदाबाद (पूर्व)	1562.90	2397.38	127.26
4.	फरीदाबाद (पश्चिम)	1575.65	1047.79	212.58
5.	फतेहाबाद	2.74	1.00	0.00
6.	गुड़गांव (पूर्व)	822.71	955.74	184.98
7.	गुड़गांव (पश्चिम)	824.34	1022.06	648.12
8.	हिसार	1111.83	1321.54	11.81
9.	जगाधरी	201.24	258.24	153.38
10.	झज्जर	759.26	678.20	14.93
11.	जींद	16.39	88.27	1.08
12.	कैथल	0. 00	3.17	0.00
13.	करनाल	99.38	113.52	18.18
14.	कुरुक्षेत्र	40.89	22.02	1.94
15.	मेवात	0.00	18.33	6.95

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

क्र०सं०	जिला	2005-06	2006-07	2007-08 जनवरी 2008 तक
16.	नारनौल	0.80	3.56	2.71
17.	पंचकुला	187.62	87.65	70.52
18.	पानीपत	23709.61	21658.30	1844.10
19.	रिवाड़ी	461.11	411.78	293.20
20.	रोहतक	53.91	47.59	19.91
21.	सिरसा	2.74	2.50	1.26
22.	सोनीपत	1058.41	1175.78	261.54
23.	मुख्यालय	608.68	0.00	0.00
	जोड़	**33116.73**	**31327.73**	**3876.81**

अनुलंग्नक 'ख'

हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर के अधीन इकट्ठे किये गये कर का संग्रहण एवं आबंटन

(राशि करोड़ों में)

वर्ष	संग्रहित राशि	5 % राज्य राजस्व वसूली अधिभार	कुल शेष राशि	पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा	शहरी विकास निकायों का हिस्सा
2005-06	331.00	16.55	314.45	157.22	157.22
2006-07	313.00	15.65	297.35	148.17	148.17
जोड़	**644.00**	**32.20**	**611.80**	**305.39**	**305.39**

स्थानीय विकास कर वसूली का पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय विकास निकायों का आबंटन

(राशि करोड़ों में)

वर्ष	कुल राशि	पंचायती राज संस्थायें	शहरी विकास निकाय
2005-06 (नकद)	231.60	115.80	115.80
2006-07 (नकद)	259.28	129.64	129.64
2007-08 (नकद)	314.56	157.28	157.28
जोड़	**805.44**	**402.72**	**402.72**

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपना जवाब दिया है वह स्पष्ट सा नहीं है कि जिलावार कितना पैसा कहां-कहां से आया है। चूंकि एक व्यावहारिक नीति सरकार की है कि जब एक टैक्स प्रणाली लागू की गयी थी और जिस तरह से आर्थिक सुधार के मामलों में टैक्स लगाने की बात आयी थी तो देश भर में एक ही बात चली थी कि टैक्सों में एक समानता होनी चाहिएं। जब समानता से देश में एक टैक्स लागू किया जाएगा तो दूसरे टैक्सों को भी प्रदेश की सरकारें समान कर देंगी। स्पीकर साहब, जब हमारे यहां पर वैट लागू किया गया तो उसके लागू होने के बाद ऐसा सोचा गया था कि कोई और टैक्स का प्रावधान न हो।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, हालांकि वित्त मंत्री जी के ऊपर दबाव बहुत हैं। इन्होंने कल ही अपना बजट पेश करते हुए कहा था कि कोई नया कर नहीं लगाया और करों में भी छूट दी गयी है तो वैट भी इसके अंदर ही आता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें कोई छूट देने का भी सरकार कोई प्रावधान करेगी?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो वैट की बात ये कह रहे हैं वैट तो सैल्ज टैक्स का रिप्लेसमैंट है। जो चीजें बिकती हैं उन पर टैक्स लगाया जाता है। एल०ए०डी०टी० तो अलग चीज है। एल०ए०डी०टी० के बारे में इनकी सरकार ने ही वर्ष 2000 में एक ऐक्ट बनाया था। वह ऐक्ट इसलिए बनाया था कि जहां औद्योगिक संस्थान हमने कायम किए, इंडस्ट्रियल ऐस्टेट्स बनाए या जहां-जहां उद्योग आए उन उद्योगों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, उसके आस-पास के स्थानों पर अच्छा आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए और बेसिक सुविधाएं देने के लिए एल०ए०डी०टी० लगाया गया था इसलिए इसका वैट से कोई ताल्लुक नहीं था यह एल०ए०डी०टी० अलग चीज थी। इसके खिलाफ बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति अदालत गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह हुक्म दिया कि जो पैटीशनर्ज अदालत में गए हैं उनसे आप कलैक्शन न करें। स्पीकर सर, अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, जिस तरह से मंत्री जी ने बताया कि आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए एल०ए०डी०टी० लगाया गया था लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जिस अंदाज में यह लगाया गया था उसका मतलब यही था कि जो लोकल यूनिट्स हैं उनसे जो टैक्स कलैक्ट किया जाएगा वह उनके विकास पर ही लगाया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं था कि अम्बाला का पैसा कैथल में और कैथल का पैसा सिरसा में लगाया जाए। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कैसे इसका इंतजामात किया है? वित्त मंत्री जी ने अपनी रिप्लाई के अनैक्सचर 'ए' में बताया है कि फतेहाबाद जिले में वर्ष 2007-08 में विकास के नाम पर कोई पैसा नहीं लगाया। इसी दौरान सिरसा जिले में 1.26 लाख रुपये ही लगाए गए हैं। मंत्री जी, क्या आप ऐसा इंतजाम करेंगे कि जहां से रैवेन्यू कलैक्शन जिस मकसद के लिए हो रही है वह वहीं पर लगे और विकास के काम हों? क्या मंत्री जी इस बारे में बताने का कष्ट करेंगे?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की दोनों बातें आपस में ही विरोधाभासी हैं। एक तो इन्होंने यह कहा है कि सिरसा में कम पैसा क्यों लगाया गया है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि लोकल एरिया डिवैल्पमैंट का मतलब यही है कि जहां से टैक्स कलैक्ट किया जाए वह वहीं लगे। अगर हम इनकी बात भी मान लें तो मैं कहना चाहूँगा कि सिरसा में रैवेन्यू कलैक्शन कम हुई होगी या नाममात्र की हुई होगी। इसलिए वहां कम पैसा लगा होगा जबकि फरीदाबाद

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

या गुड़गांव में ज्यादा कलैक्शन हुई होगी इसलिए वहां विकास पर ज्यादा पैसा लगाया होगा। इसका मकसद यह नहीं है कि जहां से टैक्स कलैक्ट किया जाएगा, पैसा वहीं लगेगा बल्कि इसका मकसद यह है कि औद्योगिक आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए अगर उद्योग जगत को रॉ-मैटीरियल या कोई दूसरा सामान 100 किलोमीटर दूर से कहीं मंगाना होता है या उसका तैयार किया हुआ माल कहीं भेजना पड़ता है तो टैक्स का पैसा वहां लगेगा और इसका मतलब यह भी नहीं है कि जहां औद्योगिक क्षेत्र खत्म हो गया वहां यह कलैक्ट किया पैसा नहीं लगेगा। एल०ए०डी०टी० जो ऐक्ट था उसका मतलब ही यही था कि औद्योगिक क्षेत्र में संचार की सुविधा, बसों की सुविधा, सड़कों की सुविधा और जितना भी टैलीकम्यूनिकेशन या और आधारभूत सुविधाएं हैं उनको चुस्त-दुरुस्त बनाया जाए और उनको बढ़ाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने तो इस टैक्स को कलैक्ट करके 2003-04 में यह नीति बनाई कि 65 प्रतिशत पैसा पंचायतों के माध्यम से रूरल एरिया में लगाया जाएगा और 35 प्रतिशत पैसा अर्बन एरिया में लगाया जाएगा। अर्बन एरिया में जो आपका माईंड सैट है उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अर्बन एरियाज में जो ऑनगोइंग स्कीम्ज थीं, आपने कलैक्ट किए टैक्स के पैसे को उन स्कीमों में ऐड कर दिया लेकिन उन के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई थी। You were not creating the infrastructure. जो ऑनगोइंग स्कीम थीं या कहीं आपको पैसे की कमी पड़ी तो आप लोगों ने सोचा कि एल०ए०डी०टी० से पैसा लगा दो। आप इस भावना से पैसा खर्च करते थे। जब हमारी सरकार आई तो हमने इस राशि को अर्बन एरियाज में 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया यानि शहरों में भी 50 प्रतिशत खर्च हो और आस-पास के गांवों में भी 50 प्रतिशत खर्च हो। इस योजना के तहत आपने 2003-04 में 99 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठा की उसमें से 80 करोड़ रुपया पी०आर०आईज को दिया और जैसा मैंने बताया कि 19 crore Rs. U.L.B. was adjusted यानि उस ऑनगोइंग स्कीम के अगेंस्ट आपने ऐडजस्ट करवाया था और शहरों को दिया नहीं। (विघ्न)

श्री एस०एस० सुरजेवाला : ये तो ऐडवांस में पैसा लेते थे और दिखाते बहुत कम थे। यह तो सारा मामला जगजाहिर है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, 2005-06 में इस टैक्स के माध्यम से हमने अपने अर्बन एरियाज को एक बार 163 करोड़ रुपया दिया और दूसरी बार हमने उनको 157 करोड़ रुपया दिया और बराबर-बराबर बांटा। हमने उसको रैशनेलाइज करने की कोशिश की। अब जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अब हमें टैक्स इकट्ठा न करने के आदेश दिये गये हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि जो फैक्ट्रीज कोर्ट में नहीं गई, उनसे हम टैक्स वसूल कर सकते हैं। इस साल हमारी 350 करोड़ रुपये के लगभग टैक्स की वसूली होनी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्ज को देखते हुए अब हमें मात्र 36-37 करोड़ रुपये मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि इस टैक्स से हमने करीब 400 करोड़ रुपये की रेवेन्यू आने का अंदाजा लगाया था जो कि अब कोर्ट के आदेश के बाद हमें यह पैसा नहीं मिल सकेगा। उस राशि का प्रान्त की प्रगति में भारी योगदान था इसलिए उसकी जगह अब हम नया ऐक्ट लेकर आ रहे हैं वह ऐन्ट्री टैक्स के नाम से है और उसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और विकास की योजनाओं का जैसे हमने कल बड़ा खुलासा किया है, ये राशि उन विकास कार्यों पर लगाएंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि क्षेत्रीय सख्ती और आवश्यकता के अनुरूप और इंफ्रास्ट्रक्चर व विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह टैक्स लगाया है। जो तालिका है, जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स की जो पोजीशन है वह यह है कि फरीदाबाद से लगभग 1562 लाख और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लगभग 1575 लाख रुपये की राशि कलैक्ट होगी। इस प्रकार लगभग तीन हजार करोड़ रुपये के लगभग राशि है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो ऐक्ट की भावना थी जो इसके कलैक्शन की भावना थी उसके अनुरूप इसका वितरण सारे जिले में किया गया है या नहीं किया गया है और अगर नहीं किया गया तो भविष्य में उस भावना के अनुरूप उसका वितरण जिलावाइज उसी मद में उसी एरिया के लिए किया जाएगा?

श्री बीरेन्द्र सिंह : सर, भविष्य में वितरण की जो बात है, मैंने बताया है कि जब तक इस केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं होगा, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर ऐक्ट को खत्म कर दिया गया तो कोई कलैक्शन नहीं होगी। लेकिन जैसा कि मैंने इन्दौरा जी के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि जो हमारे इण्डस्ट्रियल गुड्ज हैं इनके मूवमैंट को स्मूथ रखने के लिए ताकि उनको कोई विघ्न न आये और उनकी जो प्रोडक्शन है वह डैस्टिनेशन पर आराम से पहुँच जाये और रॉ मैटीरियल भी आराम से पहुँच सके। स्टेट में इण्डस्ट्रियल एटमोसफियर बने उसके लिए यह पैसा था, मैं इस बात के लिए सहमत नहीं हूँ कि सारा पैसा सिर्फ फरीदाबाद और गुड़गांव में ही इकट्ठा हो और हरियाणा के दूसरे हिस्से में न लगे क्योंकि हरियाणा स्टेट एक है जिसमें सवा दो करोड़ लोग बसते हैं। एक एरिया में यह जरूरी है कि जहां इण्डस्ट्रीज की इंटैंसिटी ज्यादा होगी, उद्योग ज्यादा होंगें तो पैसा तो ज्यादा वहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी जगह भी विकास की प्रक्रिया से न जुड़े इसलिए हमने यह विचार किया है कि हम एन्ट्री टैक्स बिल लेकर आ रहे हैं, शायद इसी सैशन में लेकर आयें।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हम एन्ट्री टैक्स बिल लेकर आ रहे हैं तो क्या एन्ट्री टैक्स बिल आने के बाद यह जो एल०ए०डी०टी० टैक्स ले रहे हैं इसको खत्म कर देंगे?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्तजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इस बारे में जो अदालत में गये हैं जिन्होंने पेटीशन डाली है उनसे अब टैक्स वसूल नहीं करोगे और दूसरों से टैक्स वसूल कर सकते हैं। हमने 38 लाख रुपये इस साल वसूल किए हैं। जबकि हमारी वसूली इस साल 350-400 करोड़ रुपये के बीच में होनी चाहिये थी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने बताया कि नया बिल हम आपके सामने ला रहे हैं और आपकी सहमति से वह पास करायेंगे।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो यह एल०ए०डी०टी० का पैसा वितरित किया गया है पंचायती राज में और शहरी विकास निकायों में उसका क्राईटेरिया क्या बनाया है या उसमें पिक एण्ड चूज किया है? क्योंकि मेरे हल्के में एक भी पैसा एल०ए०डी०टी० का नहीं गया है। मैं यह जानना चाहूँगा कि इस पैसे का वितरण का क्राईटेरिया क्या है। किस तरह से यह पैसा आवंटित होगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने इस बारे में विस्तार से इसका क्राईटेरिया बताया है, जहां इण्डस्ट्रियल ग्रौथ होगा वहां ज्यादा पैसा दिया जायेगा।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो रूरल एरिया है लेकिन पंचायती राज के तहत मेरे हल्के में एक भी पैसा नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष : उदयभान जी अब आप बैठ जायें मंत्री जी ने इस बारे में पहले ही बता दिया है।

Construction of Multi-Speciality Hospital at Kaithal

***840. Sh. Shamsher Singh Surjewala :** Will the Health Minister be pleased to state —

(a) the time by which the construction work of the building/wards residence of doctors and staff/other facilities of Multi-Speciality Hospital at Kaithal are likely to be completed ; and

(b) the total cost of the said project and the details of the amount allocated/released upto 31.01.2008 ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) :

(क) मल्टी स्पैशिलिटी अस्पताल कैथल के भवन/वार्डस/अन्य सुविधाओं का निर्माण अक्तूबर 2009 तक पूरा होने की सम्भावना है।

डॉक्टरों व स्टॉफ के रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का कार्य प्रगति पर है और यह कार्य 12 महीने की समय सीमा के साथ धन की उपलब्धता पर मई 2009 तक आबंटित किए जाने की सम्भावना है।

(ख) परियोजना की कुल लागत 1369.91 लाख रुपए है। 80.00 लाख रुपए का कार्य किया जा चुका है। निर्माण कार्यों की सारी राशि लोक निर्माण विभाग के पास जमा करवा दी जाती है और जिसे वे जहां चाहें, जब चाहें अपने आप खर्च करते हैं। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि इस काम के लिए कुल 11,06,85,000 रुपये की ऐडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल जारी हो चुकी है इन्होंने अगला प्रश्न यह पूछा है कि रिहायशी वार्डों का काम कब तक पूरा हो जायेगा तो मैं बताना चाहूँगी कि उनके लिए दो करोड़ 63 लाख रुपये की ऐडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल जारी हो गई है। लेकिन यह पैसा नये बजट में अलॉट होगा। जो टैण्डर किये गये हैं उसके हिसाब से इस कार्य को पूरा करने की तारीख 12.05.2009 थी लेकिन पैसे की उपलब्धता न होने के कारण अब यह काम अक्तूबर 2009 तक पूरा हो जायेगा।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, यह बहुत अच्छा प्रोजैक्ट है और इस मल्टी स्पैशिलिटी होस्पिटल की आधारशिला वर्ष 2006 में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी

ने हैल्थ मिनिस्टर की अध्यक्षता में रखी थी और इस पर काम शुरू हो गया था। लेकिन पिछले दिनों से इसका काम बन्द है। मंत्री महोदया ने अपने प्रश्न के 'भाग बी' के जवाब में बताया है कि इस प्रोजैक्ट के लिए 13.69 करोड़ रुपये पी०डब्ल्यू०डी० विभाग के पास जमा करवा दिया है। या तो यह पैसा पी० डब्ल्यू०डी० के पास है या नीचे नहीं गया है क्योंकि इस वक्त काम बन्द हो गया है और इसका असर काफी बुरा है मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि पी०डब्ल्यू०डी० से आग्रह करके वह रुपया भिजवा दें ताकि इस प्रोजैक्ट का काम शुरू हो जाये। अभी 60 लाख रुपये पिछले भी देने हैं और आगे उन्होंने काम बन्द कर दिया है।

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि यह जो रिहायशी क्वाटर्ज बनाने का काम है इसके लिए केवल ऐडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल जारी हुई है पैसा अभी नहीं दिया गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का भी कि इस साल जो हैल्थ का बजट रखा गया है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी और आपका होस्पिटल का काम पूरा करवा दिया जायेगा।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Question Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Status of Ponds in Bhiwani

*876. **Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether the following ponds in Bhiwani are still existing ---

(i) Noonsar Talab

(ii) Mallu Wala Talab ;

(iii) Mool Chand Talab ;

(iv) Dhobi Talab ;

(v) Neemri Wala Talab ; and

(vi) Bichhwara Talab ; if so, the present status thereof ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी) : नहीं श्रीमान्, उपरोक्त वर्णित 6 तालाबों में से केवल 4 तालाब नामत: नूनसर तालाब, मूल चन्द तालाब, धोबी तालाब तथा बिछवाड़ा तालाब ही विद्यमान हैं। इन तालाबों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

1. नूनसर तालाब भिवानी में जोन पॉल भिवानी की आबादी देह में खसरा नं० 326 के अन्तर्गत स्थित है। इस तालाब का क्षेत्र 8 कनाल 3 मरला है तथा यह तालाब के रूप में नगरपरिषद भिवानी के कब्जे में है।

2. मल्लू वाला तालाब अस्तित्व में नहीं है। यह तालाब श्री मल्लु सिंह राजपूत की शामलात मलकीयत है। यह सम्पत्ति पहले ही श्री मल्लु सिंह राजपूत के उत्तराधिकारियों में बंट चुकी है।

[श्री ए०सी० चौधरी]

3. मूल चन्द तालाब भिवानी में भिवानी जोन पॉल की आबादी देह के खसरा नं० 326 में स्थित है। इस तालाब का क्षेत्र 37 कनाल 19 मरला है तथा यह तालाब के रूप में नगरपरिषद् भिवानी के कब्जे में है।

4. धोबी तालाब भिवानी लोहर भिवानी की आबादी देह के खसरा नं० 285 में स्थित है। इस तालाब का क्षेत्र 20 कनाल 08 मरला है तथा यह तालाब के रूप में नगरपरिषद् भिवानी के कब्जे में है।

5. नीमड़ी वाला तालाब अस्तित्व में नहीं है। यह तालाब नगर सुधार मण्डल भिवानी द्वारा नेहरू पार्क के तौर पर विकसित किया जा चुका है।

6. बिछवाड़ा तालाब भिवानी, जोन पॉल भिवानी की आबादी देह के खसरा नं० 326 में स्थित है। इस तालाब का क्षेत्र 35 कनाल 18 मरला है।

MOU for Providing Employment to the Affected Persons by Reliance Industries Limited

***812. Dr. Shita Ram :** Will the Industries Minister be pleased to state —

(a) whether any MOU has been signed by the Reliance Industries Limited for setting up proposed SEZ with the State Government in respect of providing employment to the affected persons in particular and to the domicile of the rural area of the State ; and

(b) if so, the details thereof ?

उद्योग मंत्री (श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा) :

(क एवं ख) नहीं श्रीमान्। ऐसा कोई एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। यद्यपि, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम तथा रिलायन्स वैन्चर लिमिटेड (रिलायन्स उद्योग लिमिटेड की 100% स्वामित्व की सहायक कम्पनी) के मध्य एक ज्वायंट वैन्चर एग्रीमैंट हस्ताक्षरित हुआ है जिसमें सरकार की नीति अनुसार उन्हें अभिग्रहीत भूमि से विस्थापित व्यक्तियों और व्यवसायों का पुर्नवास करना है। भूमि अभिग्रहण से विस्थापित भूस्वामियों के पुर्नवास तथा पुनः स्थापना के लिए हरियाणा सरकार ने 7 दिसम्बर 2007 को नीति भी अधिसूचित की है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Development of Madlauda as Model Village

114. Smt. Raj Rani Poonam : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that village Madlauda has been selected as

model village and about 5.85 crore rupees have been earmarked for its development ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a park in place of dirty pond of village Madlauda ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हाँ श्रीमान् जी, मॉडल गांव मडलौडा में विकास कार्यों का क्रियान्वन करवाने के लिए 4,19,08,500 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ख) नहीं श्रीमान् जी, स्वीकृत राशि 4.19 करोड़ रुपये गलियों को पक्का करने, गन्दे पानी की निकासी के लिए नालियों/नाले के निर्माण तथा जलाश्यों आदि के निर्माण पर खर्च की जाएगी।

अनुपस्थिति सम्बन्धी सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a Letter from Radhey Shyam Sharma, M.L.A. dated 17th March, 2008 in which he has stated that he is unable to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha on 19th and 20th March, 2008 due to some religious function of his family.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, I report the time table of various Business fixed by the Business Advisory Committee in its second meeting.

"The Committee met at 9.00 A.M. on Wednesday, the 19th March, 2008 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday will meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

On Thursday, 27th March, 2008, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. and will again meet at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put.

On Friday, the 28th March, 2008, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business.

The Committee, after some discussion, further recommends that the business on 20th and 24th to 28th March, 2008 be transacted by the Sabha as under :—

Thursday, the 20th March, 2008 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour.

[Mr. Speaker]

Friday, the 21st March, 2008	Holiday
Saturday, the 22nd March, 2008	Holiday.
Sunday, the 23rd March, 2008	Holiday.
Monday, the 24th March, 2008 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of discussion on Budget Estimates for the year 2008-2009. 3. Legislative Business.
Tuesday, the 25th March, 2008 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of discussion on Budget Estimates for the year 2008-2009. 3. Legislative Business.
Wednesday, the 26th March, 2008 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of discussion on Budget Estimates for the year 2008-2009 and reply by the Finance Minister thereon.
Thursday, the 27th March, 2008 (9.30 A.M.) (Ist Sitting)	1. Questions Hour. 2. Non-official Business.
Thursday, the 27th March, 2008 (2.00 P.M.) (IInd Sitting)	1. Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2008-2009. 2. Legislative Business.
Friday, the 28th March, 2008 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting. 3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die. 4. Presentation of the Reports of Assembly Committees. 5. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2008-2009. 6. Legislative Business. 7. Any other Business.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move —

> That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved —

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is —

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

विधान कार्य

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2008

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is —

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the general discussion on the Budget Estimates for the year 2008-2009 will take place.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं जीरो आवर में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह राजनैतिक पार्टी से ऊपर उठकर कहना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं विपक्ष में बैठा हूँ। मैं तो मुख्यमंत्री जी से और सरकार से सामाजिक न्याय की बात कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें चेयर भी मदद करे और सभी माननीय सदस्य भी मेरी मदद करें। पिछले दिनों रोहतक में अनुसूचित जाति के लोग रिजर्वेशन के लिए अपने न्याय की मांग कर रहे थे। * * *

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, ऐसी कौन सी अरजैंसी आ गई। यदि कोई अरजैंसी थी तो आप लिखकर देते उस पर हाउस में चर्चा हो जाती। You have not sent any calling attention motion, प्लीज आप बैठें। Nothing is to be recorded.

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप जिस समय बजट पर बोलें उस समय अपनी बात कह लेना। प्लीज, अब आप बैठें। आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय इन्दौरा जी ने जो चर्चा की है वह क्लास-ए और बी का पोस्टों में रिजर्वेशन से संबंधित चर्चा की है। मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि क्लास-ए और बी में रिजर्वेशन की प्रणाली सभी वर्गों को लाभ देने के लिए हरियाणा प्रान्त में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू की थी लेकिन कुछ विशिष्ट तत्वों ने उस रिजर्वेशन को कोर्ट में चुनौती दे दी है जिसको कोर्ट ने क्वैश कर दिया है इसलिए यह मामला अभी कोर्ट में सब-ज्यूडिश है। The Government has already gone to the higher Court. जहां तक सामाजिक समरसता की बात है तो अध्यक्ष महोदय, जिस समय इनके नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी उस समय माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं थे तब इनके नेता मुख्यमंत्री होते थे। उस समय श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने दलित उत्पीड़न के सारे रिकार्ड तोड़ दिये थे, चाहे वह गांव हरसौला, जिला कैथल के अन्दर हमारे हरिजन भाईयों को घर से निकालने की बात थी, चाहे दुलीना में हरिजन और बाल्मिकि भाईयों की हत्या की बात थी और चाहे वह निसिंग और दूसरी जगहों पर उनके घर तक जलाने की बात थी। इसलिए यह एक बिल्कुल भिन्न बात है परन्तु क्योंकि अब यह मामला सब-ज्युडिश है। सरकार कोर्ट में गई है और इस केस में जो भी कोर्ट का निर्णय आयेगा वह सरकार को मान्य होगा। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी की कोई बात रिकार्ड न की जाये। डॉ० इन्दौरा आप बजट पर डिस्कशन के समय इस बारे में बोल लेना। हम आपको पूरा समय देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * * * * * * *

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, जहां तक भूख हड़ताल का सम्बन्ध है जिसका यह जिक्र कर रहे हैं तो इस बारे में उस समय अखबारों में यह खबर छपी थी कि जो लोग दिन में भूख हड़ताल पर बैठते हैं वे रात को होटलों में खाना खाते हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० इन्दौरा यह बात तो सच है कि उस समय अखबारों में फोटो के साथ इस प्रकार की खबरें छपी थी कि भूख हड़ताल पर बैठने वाले लोग रोटी खा रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी जो सवाल उठा रहे हैं इसके माध्यम से ये सिर्फ राजनीतिक बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको यह मालूम होना चाहिए कि हमारी कांग्रेस पार्टी सदा से ही सामाजिक न्याय की बात करती रही है और इसके विपरीत इन्होंने सदा ही सामाजिक अन्याय की बात की है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जहां तक इन्होंने रिजर्वेशन का सवाल उठाया है तो इस बारे में मैं यह बताना चाहूँगा कि इस समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस बारे में हरियाणा सरकार ने अपना व्यू सुप्रीम कोर्ट में बता रखा है। हरियाणा गवर्नमैंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड ले रखा है कि जो हमने पहले पॉलिसी चलाई थी हम उसके हक में है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, हम भी यही चाहते हैं कि इस बारे में जो कोर्ट का निर्णय आये उसे मान लिया जाये। हमारा अपनी न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास है।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से बजट पर जनरल डिस्कशन शुरू हो रही है। मैं एक बात सदन में कहना चाहता हूँ कि इस सदन में यह परम्परा रही है कि बजट डिस्कशन को लीडर ऑफ अपोजीशन इनएगोरेट करता है। लेकिन अगर लीडर ऑफ दि अपोजीशन न भी हो तो भी जो विपक्ष में सबसे बड़ा ग्रुप है उसके नेता को चाहिए कि वह बजट पर होने वाली डिस्कशन की शुरुआत करे। विपक्ष को यह चाहिए था कि वह इसकी शुरुआत करता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि श्री चौटाला जी आये और चले गये। इसका मतलब तो यह हुआ कि उन्होंने बजट को गम्भीरता से नहीं लिया और बजट में उनका जो योगदान होना चाहिए वह इसमें कितना कन्ट्रीब्यूट कर सकते थे इससे वे बच रहे हैं। मुझे इसकी वजह तो पता नहीं लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि विपक्ष को चाहिए था कि बजट पर होने वाली डिस्कशन की शुरुआत करते और जब प्रमुख विपक्षी ग्रुप की तरफ से बजट पर बोलने की शुरुआत करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तभी हमने यह निर्णय लिया कि सरकारी पक्ष के लोग बजट पर डिस्कशन की शुरुआत करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपने कहा ही नहीं है कि आप बजट पर बोलना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, इस समय बड़ा विपक्षी ग्रुप तो हमारा निर्दलीयों

का है इसलिए हमें पहले बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपने टाईम तो मांगा ही नहीं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप रिकॉर्ड देखें 2006-07 में जो बात आपने कही थी वही बात मैंने भी आन रिकॉर्ड कही थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो भी हो उसको पहले बोलने का मौका दिया जाए। पिछली बार भी मैंने कहा था और अब की बार भी मैं कह रहा हूँ कि परम्पराओं का निर्वाह करते हुए हमें पहले बोलने का मौका दिया जाये। परम्पराओं का पालन करना तो सरकार का काम है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, श्री मांगे राम गुप्ता जी ने लोन वेवर की फीगर्स को लेकर आज कमेटी की बैठक बुलाई है। वहाँ पर कहीं कलई न खुल जाये इसलिए इनके नेता तो आते ही चले गए। (विघ्न) वे गए ही क्यों हैं, वे यह कह कर चले गये कि मुझे जरूरी काम है लेकिन यहाँ आकर हाजिरी भी लगा गये। उनको मीटिंग में न जाना पड़ जाए इसलिए आते ही दौड़ गये। काम है तो चले जायें लेकिन वापिस तो आना ही चाहिए। (विघ्न)

Mr. Speaker : Now Doctor Indora please start the discussion on the budget estimates.

डॉ० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, परम्पराओं का निर्वाह करते हुए आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी के बजट अभिभाषण पर शुरुआत करने का मौका दिया और परम्पराओं का भी ध्यान रखा उसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के बारे में कहना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, वित्त मंत्री के बारे में नहीं बजट के बारे में चर्चा कीजिए।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, हम तो एक शरीफ शहरी होने के नाते आपकी बात मान जाते हैं लेकिन ये चिल्लाते रहते हैं फिर भी आप इन लाण्डे-पाण्डों को बोलने का मौका दे देते हो। (हंसी) (शोर एवं विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी परम्पराओं के निर्वहन में जितना योगदान दे रहे हैं इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ व उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुझे उम्मीद भी थी कि वित्तीय प्रबन्धन के बारे में बताते हुए ये जिस मजबूती के साथ यहाँ सदन में खड़े होते हैं अगर उसी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ भी खड़े दिखाई देते तो मुझे ही नहीं सारे प्रदेश के लोगों को बहुत खुशी होती। माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्तीय प्रबन्धन को ठीक करने के अच्छे प्रयास किये हैं और उन प्रयासों की झलक बजट में कहीं-कहीं पर दिखाई भी देती है लेकिन इसमें सच्चाई एक बात की फिर उभरकर आती है, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आर्थिक सुधारों की शुरुआत कहाँ से हुई? इस बारे में इन्होंने दबी जुबान में जिक्र किया है, खुले मन से नहीं स्वीकारा। अगर ये पिछली सरकार के वित्तीय प्रबन्धन को खुले मन से स्वीकार करते तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होती और मैं इनकी ज्यादा सराहना करता। इन्होंने अपने अभिभाषण की शुरुआत कौटिल्य के मुहावरे से की है जो कि एक अर्थशास्त्री था। जो बात मेरी समझ में आई है मैं उस बारे में जिक्र करना चाहूँगा। इस बजट में कहीं-कहीं अच्छाई है और कहीं-कहीं कमियाँ हैं, मैं उनका विस्तार से वर्णन

करूंगा लेकिन मैं कई देर से लड़ता आ रहा हूँ इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक गिलास पानी मंगवा लूं।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप पानी तो मांग लें लेकिन घी ना मांग लेना।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, ये जिम्मेदारी से बोलने के लिए क़तरा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वैसे इन्दौरा जी, आपकी इतनी हिम्मत तो है कि आप बोल लेते हैं वर्ना इतने ठाडे खागड़ के पास तो कोई कुछ खा भी नहीं सकता।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है प्रदेश के लोगों की जो जरूरतें होती हैं उसको आप अच्छे वित्तीय प्रबन्धन से पूरा करें। चाहे वह बिजली हो, चाहे सड़क हो और चाहे नहरें हों उनका निर्माण करवाएं। इसके साथ ही साथ हमारा जो प्लान का खर्चा है उसमें इस तरीके से कार्यवाही की जाए कि लक्ष्यों पर आधारित जो स्कीमें हैं वे समय पर पूरी हो जाएं और जो गैर योजनागत खर्चा है उसमें बढ़ोत्तरी न हो। साथ ही साथ हमारा जो राजा होता है वह प्रजा के लिए होता है और राजा का यह देखना फर्ज होता है कि प्रजा पर कर का कोई बोझ न पड़े। स्पीकर सर, रैवेन्यू रिसीटस इस अन्दाज में आएं कि उनमें बढ़ोत्तरी हो। इस खर्च को ठीक करते करते जो हमारा राजकोषीय घाटा है वह भी न बढ़े यह भी देखना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब है कि प्रदेश में अच्छा वित्तीय प्रबन्धन होना चाहिए और अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए सलाह मशविरा किया जाता है। केन्द्र सरकार में सरदार मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री होते थे तब आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उस समय यह डिसाइड हुआ था कि करों में समानता आ जाए। आर्थिक सुधारों में आज बड़े दबंग दावे करने वाली कांग्रेस की जो सरकारें उस समय प्रदेशों में होती थी उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया था। आज ये लोग सत्ता में बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता ने इनको बहुमत दिया। (विघ्न) इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका दो तिहाई बहुमत पूरा हुआ। दो तिहाई तो क्या ये बाकी के मैम्बर्ज भी सारे आपके ही हैं हम तो बेचारे ही हैं। उस दो तिहाई बहुमत के आधार पर आज सरकार जो फैसले लेती है उनका तो विवरण मेरे पास नहीं है लेकिन जिस तरह से विपक्ष पर बात होती है वह उचित नहीं है। हमारे एक साथी ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ हमारे खिलाफ प्रस्ताव लाना है उनका और कोई काम ही नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, क्या आप बोलने के लिए तैयारी करके आए हैं?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, अगर आप तैयार हैं तो क्वालिटी डिस्कशन होनी चाहिए। यहां पर प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं। (विघ्न) आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी तरफ से ठीक मैसेज लोगों में जाए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप भूमिका बनाने के लिए भी पांच मिनट का समय नहीं दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डॉ० इन्दौरा

साहब से निवेदन करूंगा कि अगर ये बोलने के लिए तैयारी करके नहीं आए हैं तो यह बाद में बोल लें। इन्दौरा साहब जब तैयारी करके आएं और जब भी ये बोलना चाहें आप इन्हें बुलवा लें। स्पीकर सर, अभी इनकी पार्टी के और सदस्य हैं जो बजट पर बोलने के लिए तैयार हैं आप उनसे बुलवा लें। श्री बलवन्त सिंह जी हैं, डॉ० सीता राम जी हैं, साहिदा खान जी हैं इनमें से जो भी बजट पर बोलने के लिए तैयार हो, उनको आप बोलने का मौका दें और डॉ० इन्दौरा साहब जब तैयारी कर लें उसके बाद उनको बुलवा लें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता की भावना का सम्मान करता हूँ। (विघ्न)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, क्या ये अपनी पार्टी के डिप्टी लीडर हैं?

डॉ० सुशील इन्दौरा : क्या इसमें भी कोई शक है और कोई शक है तो बता दें कल इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया जायेगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अगर ये डिप्टी लीडर हैं तो इसकी सीट पीछे क्यों है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी का डिप्टी लीडर हूँ और इस बारे में सरकार को भी पता है। यह सरकार की नाकामयाबी है क्योंकि इनको पता नहीं है कि डिप्टी लीडर की सीट कहाँ होनी चाहिए। पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर जो हैं उनकी यह ड्यूटी होती है कि वे सिटिंग अरेंजमैंट ठीक करें।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आपके लीडर ने सिटिंग अरेंजमैंट के लिए कभी भी सलाह-मशविरा या सुझाव नहीं दिया है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : हमारे लीडर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने लिखकर दिया है कि हमारी पार्टी के डिप्टी लीडर ये होंगे और बाकी के लोग ये होंगे, उन्होंने पूरा ब्यौरा लिखकर दे रखा है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य ने सिटिंग अरेंजमैंट के बारे में प्रश्न उठाया है तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि नॉर्मली पार्टी के जो लीडर होते हैं वे लिखकर देते हैं कि उनकी पार्टी के पदाधिकारी कौन-कौन होंगे, वे सिटिंग अरेंजमैंट के लिए सुझाव देने के लिए स्वतन्त्र होते हैं। मैं माननीय सदस्य इन्दौरा जी से अनुरोध करूंगा कि यदि इन लोगों को कोई आपत्ति न हो तो डॉ० सीताराम जी की जगह पर इन्दौरा साहब को बिठा दिया जाए और इन्दौरा साहब की जगह पर डॉ० सीता राम जी बैठ जाएं। यह व्यवस्था कल से करवा देंगे और यदि दोनों सहमत हों तो चाहे इसे अभी से ही लागू कर दें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, इस समय तो मैं बोल रहा हूँ और अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो हम उसके मुताबिक कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, फिर आप कहेंगे कि मेरा टाईम जा रहा है, अब आप बोल लें। आप पार्लियामैंट में रहे हो और सारी बात को समझते हो। अब आप बोलें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि अच्छे वित्तीय प्रबन्धन के लिए रैवेन्यू रिसीट का होना जरूरी है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Indoraji, Please continue your speech on budget estimates.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्तीय प्रबन्धन की बात की और उसमें अहम रोल वैट का रहा है। हमारी जो रैवेन्यू रिसीट बढ़ी है उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल वैट का है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, वह वैट किस ने लागू किया था। उस वक्त केन्द्र में वैट के बारे में चर्चा चली थी तो बहुत से प्रदेशों ने इसको लागू करने से मना कर दिया था। आज जो हमारे साथी सत्ता पक्ष में बैठे हैं इन्होंने भी उस समय कहा था कि हम वैट का विरोध करते हैं।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) द्वारा

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब उस समय विधान सभा के सदस्य नहीं थे जब यह बात हुई थी। जब यह वैट आया था तो उस समय हमने यह कहा था कि यह इन्आईसोलेशन में नहीं लगना चाहिए, यह सब जगहों पर इकट्ठा लागू होना चाहिए। उस वक्त जो किसान जीरी पैदा करते थे,उनको डेढ़ से 2 हजार करोड़ रुपए का नुकसान वैट को इन्आईसोलेशन लगाने की वजह से हुआ था, हमने उसका विरोध किया था। आप रिकॉर्ड देखें, हमने वैट का समर्थन किया था। अध्यक्ष महोदय, ये पूरी जानकारी लें फिर सदन में बात करें।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, इसका मतलब यह था कि पूरे देश में वैट यूनिफार्मली लागू हो।

वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

डॉ० सुशील इन्दौरा : यह बात ठीक है कि पूरे देश में वैट यूनिफार्मली लागू होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, लेकिन किसी न किसी को तो उसकी पहल करनी थी। अध्यक्ष महोदय, क्या कोई काम बिना पहल किए हो सकता है? लेकिन हमने उस की पहल की और उस पहल करने का हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। उसका दुष्प्रचार इतना ज्यादा किया गया, जिसकी वजह से हमें आज विपक्ष में बैठना पड़ा है। उसी वैट की वजह से आज ये वाह वाही लूट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, केवल वैट ही नहीं, आपने कुंए तो बहुत खोद रखे हैं। पता नहीं कितने कारण हैं जिनके कारण सत्ता का स्थानान्तरण हुआ है।

श्री खैरती लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी जो बात कह रहे हैं इस विषय में इन्होंने पिछली दफा भी कहा था और सरकार

ने बजट की स्पीच में इस बारे में पूरी तरह से खोल कर बता दिया था। यह जो वैट की बात करते हैं यह बिल्कुल गलत है। वैट जिस वक्त लगाया गया था उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने यह बात कही थी कि अगर हम इस वैट को लगाते हैं तो गरीब आदमी पर बोझ पड़ेगा। इसको यूनिफार्मली थ्रू आऊट दी कंट्री लगाना चाहिए। हमारी पार्टी ने इस बारे में सुजैशन दिया था कि जो असैंशियल कोमोडिटीज हैं उनको इसमें छोड़ दिया जाए या उनके ऊपर इसकी दर कम की जाए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात हमने यह कही थी कि अगर यह वैट हरियाणा में लागू कर दिया जाता है और साथ वाले स्टेट में लागू नहीं होता है तो कोई भी आदमी हरियाणा में कोई चीज प्रोड्यूस करता है और उसके ऊपर टैक्स लगा कर मार्किट में भेजता है। अगर उसकी प्रोडक्शन पर वैट लगेगा तो उस पर टैक्स बढ़ता चला जाएगा। जब तक हमारी प्रोडक्शन जनता तक पहुँचेगी उस पर टैक्स लगते लगते वह बहुत महंगी हो जाएगी। इसकी वजह से हमारी जो इन्डस्ट्रीज होंगी वह लोस में चली जाएंगी और मार्किट में उसके समान को कोई नहीं खरीदेगा। अध्यक्ष महोदय, इस वजह से हमने उस समय यह कहा था कि यह वैट तब लागू किया जाए जब यह सारे हिन्दुस्तान में इक्ट्ठा लगे। ये जो बात कह रहे हैं, इस बारे में उस वक्त भली भांति जवाब दे दिया गया था।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी इन्दौरा जी को बताना चाहूँगा कि ये उस वक्त हाउस में नहीं थे। हमने जो विरोध किया था वह वैट टैक्स का विरोध नहीं किया था। सैन्टर गवर्नमैंट ने वैट को सभी स्टेट्स में यूनिफार्मली लागू करने की बात की थी, इसकी सभी ने तारीफ की थी और सभी इससे सहमत थे। चौटाला साहब ने हरियाणा में सबसे पहले वैट लगाया जिसकी वजह से उस वक्त हमारा व्यापारी बहुत परेशान रहा था और इस बारे में हमने एजिटेशन भी किए थे।

11.00 बजे

वैट के लागू होने से किसानों का भी बड़ा भारी नुकसान हुआ। उस समय हमने इनको मनाने की कोशिश की थी और कहा था कि जब सारी स्टेट्स में वैट लागू होगा तभी इसका फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, उस समय अकेली हमारी स्टेट में वैट लगाने से व्यापारी और किसानों को इसका बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इन्होंने जिद्द की और ये नहीं माने। उस समय हमने यह कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी और यदि यह टैक्स रहा तथा यदि सब स्टेट्स में यह लागू नहीं हुआ तो हम इसको बंद करेंगे और अगर सारी स्टेट्स में वैट लागू हो जाएगा तब हम भी इसको लगाएंगे। अब यह वैट सारी स्टेट्स और सैंटर में भी लागू हो गया है इसलिए अब इसका फायदा हुआ है। लेकिन उस वक्त वैट को लगाने से फायदा नहीं था।

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, जो स्ट्रैंथनिंग स्टैप्स होते हैं वे लेने ही पड़ते हैं। आज अगर हरियाणा की स्थिति और स्टेट्स से बेहतर है तो यह उस समय लगे वैट की वजह से ही है। आज ये किन्तु परन्तु करते हैं लेकिन इन्होंने उस समय लोगों के बीच में जाकर बताया था कि ये वैट का विरोध करेंगे। यहां पर भी ये उस समय कहा करते थे कि वैट लागू नहीं होना चाहिए। स्पीकर साहब, अगर आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो यह उस समय लगे वैट की वजह से ही है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के और भी कई कारण हैं। (विघ्न) इन्दौरा साहब, आप कंट्रोवर्सी में न उलझा करो। आप कंटीन्यू बोलते रहें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कल बजट पेश करते समय अपने भाषण की शुरुआत किसानों के प्रति हमदर्दी जताते हुए और किसानों के सबसे ज्यादा हितैषी होने का दावा करते हुए की थी। यहाँ तक कि इन्होंने केन्द्रीय बजट का भी जिक्र किया कि केन्द्रीय बजट में किसान तथा छोटे सीमान्त किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे केन्द्रीय सरकार माफ करेगी और वाहवाही लूटने की कोशिश की। स्पीकर साहब, केन्द्रीय बजट पेश होने के पांच सात दिन बाद अपने युवराज से भी लोकसभा में यह कहलवा दिया कि यह 60 हजार करोड़ रुपये के जो कर्जे माफ करने की घोषणा की गयी है वह अपर्याप्त है क्योंकि इससे किसानों को ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, कह दिया या कहलवा दिया, कहलवा दिया कोई वर्ड नहीं है। आप तो पार्लियामैंट में भी रहे हैं आप इस तरह की बात न करें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, कहलवा दिया या कह दिया, एक ही बात है लेकिन मैं तो इसका विरोध नहीं करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक सलाहकार समिति के श्री रंगराजन अध्यक्ष हैं उनको यह जिम्मेवारी दी गयी थी कि वे किसानों की समस्याओं के बारे में पता लगाएं तथा कैसे उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, इसका भी पता लगाएं। स्पीकर साहब, जब उन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार की उसमें उन्होंने किसानों के कर्जे के बारे में और जो छोटे और लघु किसान हैं जो गैर सरकारी संस्थाओं से कर्जे ज्यादा लेते हैं तथा सरकारी संस्थाओं से कम कर्जे लेते हैं, के बारे में बताया तो मैंने इसके बारे में पढ़ते हुए देखा कि उन्होंने अंदाजा लगाया था कि इस तरह से जो किसान कर्जा लेते हैं वह तकरीबन 11 हजार करोड़ रुपये बनता है। स्पीकर साहब, जब यह सवाल उठा और केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से जब इस बारे में पूछा गया कि आप बताएं कि यह पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा तब वित्त मंत्री जी उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने कहा कि पहले इस बारे में क्रिया को क्रियान्वित होने दीजिए। इसके बाद जब उनसे फिर पूछा गया कि आप बताएं कि जो बैंकों का यह पैसा कर्जे का है उसका आप कैसे इन्तजाम करेंगे तो वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा कहना नहीं है बल्कि यह तो जनता की तरफ से बात आ रही है कि चूंकि अब लोक सभा के चुनाव सिर पर हैं इसलिए उसकी तरफ से केन्द्रीय बजट को चुनावी बजट कहा जा रहा है। इससे किसानों को फायदा नहीं होगा।

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर साहब, कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये के किसानों के कर्जे माफ किए लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा क्योंकि उस समय इन्दौरा जी हाउस के सदस्य नहीं होते थे बलवन्त सिंह हमारे साथ उस समय भी हाउस के सदस्य होते थे, इनको पता होगा कि उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा में कैसीनो जिसमें जुआ खेलते हैं, का बिल विधान सभा में लेकर आए थे। वे उस समय कैसीनो हरियाणा में खोलना चाहते थे। स्पीकर साहब, कैसीनो प्रदेश में खोलना ठीक था या अब जो हमारी सरकार ने किसानों के कर्जे माफ किए हैं यह ठीक है?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है। जो समाचार इस बारे में आ रहे हैं उसके आधार पर अगर हम यह देखें कि इससे हरियाणा प्रदेश के कितने किसानों का फायदा होगा, यह तो मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में बतायेंगे क्योंकि अब

तक तो इन्होंने इसके बारे में सारा रिकॉर्ड मंगा लिया होगा कि कहां से कितने किसानों को कितना फायदा होना है इस बारे में मेरे कहने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में हरियाणा प्रदेश के ओवरड्यू के मामले में बता दें। वित्त मंत्री जी ने शुरू में कहा कि यह बजट आंकड़ों पर आधारित है। यह आंकड़ों पर आधारित बजट नहीं है। दूसरी बात मंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि खेती के क्षेत्र में विकास की दर धीमी पड़ती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पूरे देश में और प्रदेशों में खेती का जो लागत मूल्य है वह बढ़ता जा रहा है उस लागत मूल्य को कम करने की क्या कोई परियोजना सरकार की है। मेरे पास हरियाणा प्रदेश की आर्थिक इकोनोमिक सर्वे रिपोर्ट है उसमें स्वयं माना गया है कि जो एग्रीकल्चर सैक्टर का स्टेट जी०डी०पी० का शेयर है वह वर्ष 2006-2007 में 21.1 प्रतिशत, वर्ष 2005 में 21.4 प्रतिशत रहा है यानि यह लगातार कम होता जा रहा है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश में कृषि को बढ़ावा मिले और कृषि से हमें आमदनी हो और उसमें जो हमारा शेयर है वह बढ़े। प्राईमरी और दूसरे सैक्टर से नहीं बल्कि कृषि सैक्टर से हमारी स्टेट के जी०डी०पी० में इजाफा हो, यह हमारी सोच होनी चाहिए। इसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया और न ही हमने बजट में दिखाया है।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब ने जो चिन्ता जाहिर की है इस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूँ कि कल माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन में इस बारे में आंकड़े दिए थे कि हरियाणा प्रदेश में बारिश न होने के बावजूद भी मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद तीन साल से लगातार खेती को प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। ये आंकड़े सदन के रिकॉर्ड पर हैं। जहां तक इन्होंने कहा है कि आर्थिक ग्रोथ जी०डी०पी० के बारे में एग्रीकल्चर सैक्टर में शेयर कम हुआ है मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि that is because economy is booming in all other sectors also. There is rapid industriaization, there is rapid increase in the service sector. That does not mean कि एग्रीकल्चर सैक्टर हमारा नीचे जा रहा है। खेती की प्रोडक्शन ऊपर जा रही है। परन्तु दूसरे सैक्टर भी और स्पीड से बढ़ रहे हैं, तथ्य व आंकड़े सदन के पटल पर आ गये हैं। मैं डॉक्टर साहब को एक और बात बताना चाहूँगा कि वर्ष 1999-2000 से लेकर वर्ष 2003-2004 तक मौजूदा यू०पी०ए० की सरकार आने के बाद पैदावार की दर बढ़ी है। आप सबके पास आंकड़े मौजूद हैं पहली बार देश में 30 वर्ष में खेती के उत्पादन की दर वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2002-2003 के बीच में 1 प्रतिशत से कम हुई है और अब फिर ऊपर उठी है और अब और ऊपर उठाने की जरूरत है। उस समय देश में एन०डी०ए० की सरकार थी जिसको विपक्ष के सदस्य समर्थन दे रहे थे। यह बात मैं नहीं कहता बल्कि ये भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : कृषि उत्पाद लागत कम करने का कोई भी उपाय इस सरकार ने तीन साल में नहीं किया है। पहले साल में तो सरकार ने यह कहा कि हम योजनाएं बनायेंगे फिर उनको क्रियान्वित करेंगे। हमने मान लिया और उस वक्त भी मैंने खुद इस सभा में कहा था कि चाहे हम विरोधी पक्ष के लोग हैं लेकिन हम इसका विरोध नहीं करेंगे। सरकार अच्छे काम करेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। सरकार हाईकोर्ट के मसले पर प्रस्ताव लेकर आई हमने उसका समर्थन किया लेकिन प्रदेश में उस के बाद आज तक क्या कार्यवाही हुई यह मुख्यमंत्री जी बतायेंगे। जहां तक किसानों की लागत मूल्य की बात है हमने यह कहा कि कृषि के लिए 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने का काम सरकार करे। स्पीकर सर, मैंने तो गवर्नर के अभिभाषण पर एक एमैंडमैंट भी दी थी। वह किन कारणों से रिजैक्ट कर दिया गया उसका फेट क्या रहा मुझे

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

नहीं पता। मैं यह कह रहा था कि किसान को लाभ मिले। कर्जा माफी अच्छी बात है किसानों को राहत देने की चेष्टा की गई है जिसमें सरकार सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन किसानों से जुड़े और मुद्दे बहुत हैं जिस तरह से एस०वाई०एल० कैनाल की अगर हम बात ले लें। पिछले अभिभाषण में वित्त मंत्री जी ने बड़े जोर शोर से कहा था कि एस०वाई०एल० हमारी जीवन रेखा है और इसका निर्माण कार्य होना चाहिए। मैंने उस समय भी कहा था कि एस०वाई०एल० के निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी केस न्यायालय में नहीं है। इंटर स्टेट ट्रीटी वाटर के बारे में जो पंजाब विधान सभा में बिल पास किया गया था, उसका मामला कोर्ट में है। सरकार एस०वाई०एल० का निर्माण तो कराए। अपने बजट में उसके लिए बजट्री प्रोविजन तो करे। आज हमारा जो पानी का हिस्सा है वह हमें पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। इसमें कोई राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बात नहीं है। इसी तरह से हरियाणा के किसान को पानी के समान बंटवारे के लिए हांसी बुटाना लिंक नहर का बड़ा जिक्र किया गया। इस बारे में हमारे नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी यह कहा था कि इससे हमारा कोई विरोध नहीं है। प्रदेश में नहरें बनें, इस बात में हमारा कोई विरोध नहीं है लेकिन पानी की उपलब्धता हो, यह हमारा सवाल है। प्रदेश में जितना पानी उपलब्ध है उसके अलावा पानी आएगा, तभी किसान को फायदा होगा। वह पानी कहां से आएगा। यह भी सोचना चाहिए। सरकार डैम बना रही है बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मैं सरकार की तारीफ भी करता हूँ लेकिन किसान को फायदा तो दें। अगर इसी तरह से देखें तो समाजसेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य यह तो हमारा फर्ज बनता ही है। हम प्रदेश के लोगों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें। आज हमारे साथियों ने चर्चा करते हुए कहा कि स्कूलों में टीचर नहीं है जो गैस्ट टीचर्ज लगाए हुए हैं उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि कब ऑर्डर आ जाएं और कह दिया जाए कि घर बैठ जाओ। ऐसे लोग कैसे पढ़ा पाएंगे? शिक्षा में नैतिकता भी होनी चाहिए।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को क्लीयर करना चाहूँगा कि गैस्ट टीचर रैगुलर नहीं होते। गैस्ट का मतलब यह नहीं है कि किसी के घर में आ गया तो कब्जा करके बैठ जाए। आप लोगों ने रैगुलर टीचर्ज की नियुक्ति का केस हाईकोर्ट में स्टे करवा दिया, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए हमने गैस्ट टीचर लगा दिये।

डॉ० सुशील इन्दौरा : मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि स्कूलों में परमानैंट टीचर्ज भर्ती किए जाएं ताकि शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से चल सके। आज हालत यह हैं कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य कमजोर हालत में हैं। अभिभाषण में कहा गया है कि हम समुन्नत समाज की कल्पना करते हैं। समुन्नत समाज कैसे बनेगा जब तक कि लोगों को मूलभूत सुविधायें नहीं मिलेंगी। आज शिक्षा के स्तर को देखते हुए गरीब आदमी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या उच्च अधिकारी बनाना चाहे तो उसको अपनी आजीविका चलाने के अलावा लगभग 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख का इन्तजाम करना पड़ेगा। वह इन्तजाम इस महंगाई के जमाने में कैसे कर पाएगा। केन्द्रीय बजट की तारीफ की गई है कि केन्द्र सरकार बहुत अच्छा बजट लेकर आई है लेकिन अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो केन्द्रीय बजट आने के बाद तेल जिससे आम आदमी रोटी खाता है उसके भाव कितने बढ़ गए हैं, दालों के भाव कितने बढ़ गए हैं। (विघ्न)

वन एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : वह रेट तो इंटरनैशनल मार्किट

से बढ़ते हैं। हमारी स्टेट का उसमें रोल नहीं है बल्कि हमने तो सब्सिडी भी दी है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : केन्द्रीय बजट के 5–7 दिन बाद महंगाई इतनी बढ़ गई कि जीवनयापन आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी बजट लेकर आए लेकिन इन्होंने अपने बजट में कहीं कोई प्रावधान या कोई प्रयास ऐसा नहीं किया कि आम आदमी आराम से जिन्दगी बसर कर सके। ये अपने बजट में कोई ऐसा प्रयास कर सकते थे जिससे प्रदेश में जो कालाबाजारी हो रही है उसको रोका जा सके। इस कालाबाजारी को रोकने का कहीं कोई प्रयास नहीं किया जा रहा।

श्री नरेश कुमार प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन्दौरा जी से पूछना चाहता हूँ कि आप जो रोटी खाते हो, मिट्टी के तेल से खाते हो या सरसों के तेल से खाते हो। यो जो भाव बता रहे हैं कि दाल के रेट बढ़ गए, सरसों के तेल के रेट बढ़ गए। मैं इनको कहना चाहूँगा कि यह भाव तो किसान के हित में बढ़े हैं, ये बताएं कि जिन्स खेत में पैदा होती है या जहाज में पैदा होती है। अध्यक्ष महोदय, इनको तो किसान की बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए। ये किसान के नाम पर वोट हासिल करते थे और निहत्थे किसानों पर गोलियां चलवाते थे। इनके समय में पूरे हरियाणा प्रदेश में त्राहि त्राहि मची हुई थी, पूरे प्रदेश में हा–हाकार मचा हुआ था और कोई आदमी उस समय सुरक्षित नहीं था। इनको ये दादागिरी करनी है तो ये दादागिरी अपने घर जाकर कर लें, कम से कम इस सदन में यह दादागिरी नहीं चलेगी। ये कुछ तो शर्म करें। (शोर एवं व्यवधान) ये तो किसी अनट्रेंड ड्राइवर की बस में लटक रहे हैं, कोई घसट रहा है और कोई छात पर बैठा है। (शोर एवं व्यवधान) आप तो पढ़े लिखे हो। आप अपने नेता की एजूकेशन बता दो, मेरी तो उस दिन पूछ कर भाग गए थे। (शोर एवं व्यवधान) कुछ तो शर्माओ, हमारे से न शर्माओ पब्लिक के जो आदमी यहां बैठे हैं इनसे तो शर्माओ और थोड़ा तो इस प्रदेश के भले के बारे में सोचो।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब अपने नेता की क्वालिफिकेशन बता दें तो माननीय सदस्य की सैटिसफैक्शन हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : आप Who's who में देख लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हो जाऊं तो ये भागने के लिए कुलमिलाणे लग जाते हैं। पता नहीं मैं क्या तलवार मारता हूँ। जब मैं खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे अहसास हो जाता है कि ये कुलमिलाण लग गए और ये भागेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हद है कि जब किसान का बेटा आसन पर बैठा हो और हम किसान की बात, मजदूर की बात कहें तो ऐसी हालत पैदा कर दी जाती है कि किसान की बात को गोल माल करके दबा दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा ऐसा ही किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने लोगों को गुमराह करके हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है।

वन राज्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं, इनकी सरकार ने तो हमेशा किसानों को गुमराह किया है। किसान की अगर किसी

[श्रीमती किरण चौधरी]

सरकार ने सुध बुध ली है तो वह कांग्रेस की सरकार ने ही ली है। किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के जो कर्जे माफ किए गए हैं ये कांग्रेस सरकार ने ही किए हैं। कांग्रेस की सरकार ने तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया अब ये बताएं कि इनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या-क्या किया। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह तो रिकॉर्ड की बात है और मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी माना है कि चौधरी देवी लाल जी ने 10-10 हजार रुपये तक के कर्जे उस वक्त माफ किए जब रुपये की वैल्यू होती थी।

श्रीमती किरण चौधरी : उस समय केवल बोलने के लिए कर्जे माफ किए गए थे, पेपर्ज में ही माफ किए गए थे और असलियत में कहीं माफ नहीं हुए थे।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, यह मिस प्रिंट हो रहा है, आप बार-बार दिखा रहे हो। इस बारे में गुप्ता जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है और आज उसकी मीटिंग है लेकिन आज आपका नेता यहां नहीं है उसको उस मीटिंग में हाजिर होना चाहिए था। आपके नेता जो तथ्य बताकर गए थे उस बारे में बताते।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगेराम गुप्ता) : वह नेता कहां गया। उनको तो आज मीटिंग में रिकॉर्ड देना था। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उस कमेटी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : नियमानुसार विधान सभा की कार्यवाही को प्रिंट किया जाता है और उससे पहले उसको कौरेक्शन के लिए भेजा जाता है और उस कौरेक्शन में सरकार का काम होता है। सरकार की यह नाकामयाबी होगी कि वह बोल तो देती है लेकिन पढ़ नहीं पाती, वह अपनी बात कह तो देती है लेकिन समझ नहीं पाती। यह रिकॉर्ड की बात है और मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं हांसी बुटाना लिंक नहर के बारे में कहना चाहूँगा कि हमने इसका विरोध नहीं किया।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये विरोध नहीं कर रहे लेकिन इनके नेता ने कभी हाँ भी नहीं की कि ये हांसी बुटाना लिंक नहर के पक्षधर हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार कोई स्कीम बनाये और वह स्कीम समय पर क्रियान्वयन हो यह अच्छी बात है। हांसी बुटाना लिंक नहर के लिए शुरुआत में वित्त मंत्री जी ने 265 करोड़ रुपये रखे थे और आज कितना पैसा खर्च कर रहे हैं यह सबको मालूम है। यह सोचने वाली बात है कि पैसा कहां से आयेगा, पैसा लोगों की जेब से आयेगा जो सरकार के गलत निर्णयों की वजह से खराब हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित नहीं होता कि हांसी बुटाना लिंक नहर की शुरुआत करने से पहले अन्तर्राज्य विवादों को सुलझाया जाता। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये लोग पंजाब के हित की बात कर रहे हैं

क्योंकि ये पंजाब के साथ मिले हुए हैं। ये हरियाणा में बैठे हैं इसलिए इन्हें हरियाणा के हित की बात करनी चाहिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अच्छे वित्तीय प्रबन्धन के बारे में बात कर रहा हूँ ताकि हांसी बुटाना लिंक नहर पर कम पैसा खर्च हो। हांसी बुटाना लिंक नहर के लिए 265 करोड़ रुपये योजनागत तरीके से रखे गये थे, मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ये अन्तर्राज्य विवाद को सुलझा लेते ताकि नहर बनने के बाद बी०एम०एल० में पेंचर करके हम पानी ले सकते और हरियाणा के किसानों को उनके हक का पानी मिलता। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वे प्रदेश में कई स्थानों पर गैस बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट लगाने जा रहे हैं और थर्मल पॉवर प्लांट लगाकर वे हमारी हवा निकालेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि हमारी हवा निकले या न निकले लेकिन आने वाले समय में इनकी हवा जरूर निकल जायेगी।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, फिर वह हवा कहां जाकर भरेगी?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं पावर की बात कर रहा हूँ कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वे प्रदेश में बड़े-बड़े और अच्छे-अच्छे नये थर्मल पॉवर प्लांट लगा रहे हैं तथा आज जो हमारी बिजली की मांग है वह आने वाले वर्षों में दुगुनी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपने 10 बजकर 46 मिनट पर बोलना शुरू किया था। आपको बोलते हुए 37 मिनट हो गये हैं। आप बहुत धीरे-धीरे बोल रहे हैं। आप बोलते-बोलते बीच में ही रुक जाते हैं और पता नहीं क्या ढूंढने लग जाते हैं। I have handed over the House in your hand please address the House about the Budget Estimates.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े देख रहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं पॉवर की बात कर रहा था कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि खेदड़ और झाड़ली में गैस बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट लगाये जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी अपने जवाब में सदन को बतायें कि इन्होंने पॉवर के पिछले जो खर्च हैं उनमें कमी की है। इसी प्रकार वित्त मंत्री जी पॉवर में 2007-08 का जो प्लान खर्च है जो रिवाईज्ड एस्टीमेट्स हैं उसमें और 2008-09 का जो बजटरी एस्टीमेट हैं उसमें आप देखिए कितना अन्तर है। वह घटा है। आज आप नये-नये पॉवर प्लांट लगाने जा रहे हैं। आप यह भी कहते हैं कि हम दुगुनी बिजली दे देंगे।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि शायद इन्होंने बजट का अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं किया। उसमें हमने यह कहा है कि हम सरकार की तरफ से 20 प्रतिशत इक्विटिटी देंगे और बाकी का पैसा बाहर से अरैंज किया जायेगा। अब अगर इस बात को माननीय सदस्य न समझें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें अगर हम 10 हजार करोड़ का प्रोजैक्ट लगायेंगे तो उसमें 2 हजार करोड़ हम इक्विटी देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि वे पहले बजट को अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ लें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के लोगों को जो बिजली मिलनी चाहिए क्या ये स्पष्ट बतायेंगे

कि वह सस्ती मिलेगी या नहीं। क्या कांग्रेस की सरकार ने बिजली का व्यापारीकरण नहीं किया है? आज अगर हम अपने हरियाणा में जल पर आधारित बिजली परियोजनाओं की स्थापना करते तो उनसे हमें सस्ती और ज्यादा बिजली मिलती और हमें बाहर से भी बिजली खरीदने की जरूरत न पड़ती। जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार को आढ़तियों और साहूकारों से किसानों और गरीबों द्वारा लिए गए कर्जों को माफ करने का सुझाव दिया है उसी प्रकार से क्या इस प्रकार का भी सुझाव हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं दिया जा सकता था, क्या यह जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की नहीं बनती थी कि वह केन्द्र सरकार को यह सुझाव देती कि हरियाणा में जल आधारित बिजली परियोजनाओं की स्थापना की जाये।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से केवल दो तथ्य माननीय सदन और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। एक तो डॉ० इन्दौरा को शायद यह मालूम नहीं है वैसे तो मालूम होना चाहिए कि हरियाणा राज्य में पन बिजली परियोजनों के माध्यम से बिजली नहीं बन सकती क्योंकि यहां पर पन बिजली की परियोजनायें लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। एक छोटी सी परियोजना लग सकती थी जिसे हमने लगा दिया है लेकिन उसमें से भी केवल 4-5 मेगावाट बिजली ही उत्पादित हो सकेगी क्योंकि हमारे यहां पर नहरों की ग्रेडीएंट नहीं है। शायद इन्होंने पूरे हरियाणा राज्य को अभी घूम कर देखा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि जहां तक सस्ती बिजली का प्रश्न है, इसके लिए केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ही चिन्तित हैं और इसीलिए हमने जो परमाणु करार है उसका प्रावधान किया है। इनके नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला तो जयपुर में जाकर यह कहकर आये हैं कि परमाणु करार देश के हित में नहीं है। इससे हमें सस्ती, टिकाऊ और ज्यादा से ज्यादा बिजली कम से कम संसाधनों से मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहूँगा कि वे यह स्पष्ट करें कि देश आज जो परमाणु संधि कर रहा है वे उसके हक में हैं या खिलाफ हैं। जयपुर के स्टेडियम में इनके नेता ने कहा है कि परमाणु संधि देश के हित में नहीं है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के साथियों से कहना चाहता हूँ कि पावर प्लांट लगाने की जैसी बात चल रही है जैसे पन बिजली की भी बात कही गई है या जो यह अणु बिजली समझौता है यह राष्ट्रीय बहस का मुद्दा है और राष्ट्रीय बहस के मुद्दे पर ये अपनी सरकार को क्या देना चाहते हैं। चर्चाएं तो ये भी हैं कि ऐसे हालात रहे तो कांग्रेस देश को ****** कर खा जायेगी, ****** रख देगी। अमेरिका को ****** रख देगी। इसके साथ ही मुझे किसान हितैषी होने की बात भी याद आई कि 60 हजार करोड़ रुपये के जो कर्जे माफ किये गये उस पर किसानों ने दिल्ली जाकर आभार व्यक्त किया। इन्होंने एक ****** के कन्धों पर हल रखा। ये एक ****** के कन्धों पर हल रखकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं। हल रखना ही था तो किसी किसान के बेटे के कन्धों पर रखते तब तो कोई बात थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी ने जिन अनपार्लियामैंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया है वे रिकॉर्ड न किये जायें। डॉ० इन्दौरा आप कन्टीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि प्रदेश में ऐसी चर्चाएं हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, डॉ० इन्दौरा जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं यह बिल्कुल अनुचित है। श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में एक असहाय औरत कहने की जो बात है यह सदन की कार्यवाही से एक्सपंज की जाये क्योंकि वे न तो इस सदन की सदस्या हैं और जिसको ये असहाय औरत कह रहे हैं उन्होंने ही इनकी सरकार को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया था। वे एक बार हरियाणा में आईं थी एक कोने से दूसरे कोने में और उसी से इनकी सरकार की धज्जियां उड़ गई थीं।

श्रीमती किरण चौधरी : इन्दौरा जी, औरतों को असहाय मत कहिए। औरतें आपसे तो ज्यादा सक्षम हैं। (शोर एवं व्यवधान)

संसदीय सचिव (कुमारी शारदा राठौर) : ये, इस असहाय शब्द के लिए माफी मांगे। असहाय कहने का क्या मतलब है? औरतें आदमियों से कई गुणा सक्षम हैं। सहारे की जरूरत तो आपके नेता चौटाला जी को है (शोर एवं व्यवधान) उन्हें सहारा दीजिए। (विघ्न)

Mr. Speaker : Indora Ji, before reflecting on the character of others, you should be worried about your own character.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात बार-बार कहते आये हैं कि पिछली सरकार ने बिजली के मामले में कुछ नहीं किया जबकि मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करने की बात कही थी और यह भी कहा था कि 3 साल के अन्दर हरियाणा प्रदेश में बिजली की कमी नहीं रहेगी। अब सरकार को बने हुए तीन साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं जो लांछन लगाते रहते हैं कि पिछली सरकार की पॉवर एवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं थी आप इन आँकड़ों में देखिए 1999-2000 में 2768.5 मैगावाट बिजली हमारे पास उपलब्ध थी और 2004-05 में 4033.3 मैगावाट थी और आज के दिन 2007-08 में 4368.3 मैगावाट एवेलेबिलिटी है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इंस्टाल्ड कैपेसिटी और एवेलेबिलिटी में क्या फर्क है यह बात इनको पता ही नहीं है। इन्दौरा जी, आपको कुछ समय चौधरी सम्पत सिंह जी के पास लगाना चाहिए, वे आपको इस अन्तर के बारे में अच्छी तरह से समझा देंगे कि इंस्टाल्ड कैपेसिटी और एवेलेबिलिटी ऑफ पॉवर में क्या फर्क है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : आपने जो यमुनानगर थर्मल पॉवर प्लांट को चालू किया है उसमें भी किसी व्यक्तिगत को फायदा पहुँचाने के लिए इस प्लांट को तेल से चालू किया गया है। क्या आप बतायेंगे कि कमर्शियल यूनिट के रूप में यह प्लांट कब से शुरू होने जा रहा है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, थर्मल पॉवर प्लांट शुरू में तेल से ही फायर किये जाते हैं। Power plants are fired first by oil then these are switched to coal. अब इन्हें यह बात समझ में ही नहीं आती तो क्या किया जा सकता है, इनकी अलग से क्लास लगानी पड़ेगी।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मुद्दे तो बहुत हैं, कल के ही एक मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। कुण्डली-मानेसर एक्सप्रैस हाई-वे के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों को 500 करोड़ रुपये का ज्यादा मुआवजा दिलवा दिया। यह अच्छी बात है। हम मान लेते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ी, जमीन के भाव बढ़ गये, उसी हिसाब से आपने फ्लोर रेट तय किये हैं और उसी का फायदा किसानों को हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों की जो जमीन एक्वायर की जायेगी उनको 33 साल तक 15000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे और 500 रुपये सालाना की दर से बढ़ौतरी भी होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से सरकार ने जो जमीन एक्वायर की है अगर आज के दिन उसको मार्किट में बेचा जाये तो वह एक-एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बिके। उस पैसे को बैंक में जमा करवा कर आप हिसाब लगा कर देखें?

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, 2005 में इन्होंने सरकार छोड़ी थी। उस समय 2 लाख और सवा दो लाख रुपये प्रति एकड़ के भाव से किसानों की जमीन एक्वायर की जाती थी। बताईये इन्दौरा जी, क्या उस समय दो या सवा दो लाख से ज्यादा के रेट थे, अगर हों तो बता दो? उसके बाद हमारी सरकार आई और हमने जमीन के फ्लोर रेट तय किये, उसके बाद जमीन के भाव बढ़े हैं। अगर आज उस जमीन के रेट एक-एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ हो गया है तो वह हमारे फ्लोर रेट तय करने के कारण ही बढ़ रहे हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई)

डॉ० सुशील इन्दौरा : यह बात सरासर गलत है कि फ्लोर रेट फिक्स होने के बाद रेट बढ़े हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनकी इतनी बात तो सही है कि फ्लोर रेट निर्धारित करना तो केवल एक फैक्टर है। इनको हरियाणा प्रदेश की जनता ने यहां से निकाला यह सबसे बड़ा फैक्टर है। इनके जाते ही जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार आई वह इकॉनॉमिक इंफ्लूंसी, के कारण आई है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह तो एक आर्थिक उफान आया था!

श्री बीरेन्द्र सिंह : यह आर्थिक उफान आपकी सरकार के टाईम में क्यों नहीं आया?

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आप एनसथीसिया के डॉक्टर हो। आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज के भाव बढ़ने के कारण होते हैं। जब कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होती है तो इन्वैस्टर वहां पर अट्रैक्ट होते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है तब भाव भी बढ़ते हैं। भाव वैसे थोड़े ही बढ़ जाते हैं। दो लाख रुपये में भी जमीन का किल्ला कोई नहीं खरीदता था। डॉक्टर साहब, आप समझदार हो और सारी बात को समझते हो। Now you may please continue.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कानून-व्यवस्था पर ही आ जाता हूँ। वित्तीय प्रबन्धन में ये अपने आंकड़े देखें। वर्ष 2003-04 में जो बजट हम लेकर आए थे उसका फायदा आहिस्ता-आहिस्ता जरूर आगे की सरकार को मिला और उसमें भी वैट का अहम रोल रहा है।

वर्ष 2004-05 में जो योजना खर्च था वह मैं आपको बता देता हूँ। वर्ष 2004-05, 2006-07, 2007-08 और इस वर्ष 2008-09 में दिए गए आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो विकास दर 36.99% थी यानि योजनागत तरीके से अगर आप काम करेंगे तो विकास होगा इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि वित्तीय प्रबन्धन ठीक किया जाएगा तो विकास होगा लेकिन अगर आज हम विकास दर को देखें तो यह घटते-घटते आज वर्ष 2008-09 में 15.18% हो गई है। योजनागत खर्च योजनागत तरीके से खर्च करने का हमारा तरीका था। हमारा जो प्लान एक्सपैंडिचर था वह ये कहते हैं कि हमारे समय में ठीक नहीं रहा। प्लान एक्सपैंडिचर 2004 से लेकर आज तक आहिस्ता-आहिस्ता हमारे सरकार के समय में जिस तरीके से होता था आज घटते-घटते यह नीचे आ गया है। स्पीकर सर, सीधी सी बात है कि प्लान एक्सपैंडिचर का मैनेजमैंट सही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका वित्तीय प्रबन्धन ठीक नहीं है, वरना आपके हिसाब से तो यह नीचे जाएगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने ऑनरेबल मैम्बर को बताना चाहूँगा कि जब इनका राज था तो उस समय जो टोटल प्लान एक्सपैंडिचर 2004-05 का था वह 21.62% था और अब 2008-09 में 31.49% है। इन्दौरा साहब इसको देख लें और यदि ये कहें तो मैं यह फिगर्ज इनको भिजवा देता हूँ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने फिगर्ज माननीय वित्त मंत्री जी को भिजवा दूँगा।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप अपनी बात को कॉन्टीन्यू करें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, योजनागत नॉन प्लान एक्सपैंडिचर की बात मैं कर रहा था। नॉन प्लान में कोई भी सरकार यह देखे जिस तरह से किसी घर में पैसा आ गया है और उस पैसे को यदि सही ढंग से खर्च न किया जाए तो उस घर को नुकसान होता है। इसी तरह से योजनागत तरीके से पैसा न खर्च किया जाए तो उस सरकार का ही नुकसान होता है। उस पैसे की वेस्टेज होती है। अध्यक्ष महोदय, पैसा प्रदेश के लोगों से ही इकट्ठा किया जाता है और उसको तरीके से खर्च करके प्रदेश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन इसके लिए इन्होंने ऐसा प्रबन्ध नहीं किया है। जहां तक 2006-07 में हमारा गैर योजनागत खर्च जो 13999.05 करोड़ था वह 2007-08 में 14991.28 करोड़ हुआ है, यह बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। यह तो सामने है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर मैं इस बात को क्लीयर करना चाहता हूँ। ऑनरेबल मैम्बर अपने आंकड़ों से अपने आप को ही झुठला रहे हैं। इनकी बात को अगर मैं इस तरह से पेश करूं कि यह कह रहे हैं कि वर्ष 2006-07 में 13999 करोड़ था, इसका मतलब यह हुआ है कि 73.78% का नॉन प्लान एक्सपैंडिचर था। इन्दौरा साहब, जो दूसरे आंकड़े दे रहे हैं कि 14991.28 करोड़ रुपये का नॉन प्लान एक्सपैंडिचर 2007-08 में हुआ है। मतलब नॉन प्लान एक्सपैंडिचर का परसैंटेज घटकर 69.47% रह गया। स्पीकर सर, यह तो ऐफिशियैंसी की बात है कि जो गैर प्लान एक्सपैंडिचर था उसकी परसैंटेज घटी है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, ये एक बात और देखें कि रुपया कंसोलिडेट फंड में कहां से आया और कहां पर खर्च हो रहा है। ये कहते हैं कि पब्लिक सैक्टर में और योजनाओं

[डॉ० सुशील इन्दौरा]
पर हम पैसा खर्च करेंगे। इन्होंने कंसोलीडेटिड फंड में दिया हुआ है कि पॉवर में ये टोटल बजट के रुपए में से 2007-08 में 13.36 पैसे खर्च करेंगे जबकि यह पिछले साल 14.34 पैसे थे। आपने यह पैसा तो घटा दिया है, अब कहां से खर्च करेंगे?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अब आपकी समझ में न आए तो मैं क्या कर सकता हूँ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट का इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसमें 3.22 पैसे दिखाया है, जबकि पिछले साल इस पर 3.59 पैसे खर्च किए गए थे। इरीगेशन में 5.59 पैसे का खर्च दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, अब ये इस तरह से हरियाणा में विकास की बात करते हैं? अध्यक्ष महोदय, सर्विस सैक्टर और योजनाओं पर ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। इन्होंने एजूकेशन और सोशल वैल्फेयर, हैल्थ और पुलिस में भी पैसे को कम किया है। जबकि पुलिस का काम प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना होता है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : आप यह बताएं कि शिड्यूल्ड कास्ट कम्पोनैंटस में क्या हुआ है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : इसमें किसी को थोड़ा बहुत लालच देने के लिए बढ़ा दिया होगा, उसका क्या है। आजकल सभी सरकारें शिड्यूल्ड कास्टस की ठेकेदारी करने में लगी हुई हैं क्योंकि सरकारें तो यही बदलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने किसानों की ठेकेदारी ली हुई है। (विघ्न) चलो ठीक है, आप बजट पर कन्टीन्यू करें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके रैवेन्यू रिसीट की बात करना चाहता हूँ। वर्ष 2005-06 में कुल रैवेन्यू रिसीट 13853.31 करोड़ रुपए थी जबकि 2006-07 में बढ़कर कुल रैवेन्यू रिसीट 17952.3 हो गई है यानि की 30 प्रतिशत इन्क्रीज हुई है। यह बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं या पता नहीं अपने आप हो गए हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि इन्होंने प्रयास किए हैं, मुझे लगता है कि हो गए हैं। मैंने कोई नोट नहीं करने के लिए नहीं कहा है। स्पीकर सर, यह हो गया है और होने का कारण जो था वह मैं बताता हूँ। यह वैट की वजह से हुआ। इसको लागू हमने किया इसलिए उसका खामियाजा हमें मिला है और वाह-वाही ये लूट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वैट की वजह से 30 प्रतिशत तक की रैवेन्यू रिसीट बढ़ी है। यह आप चाहें तो देख लें।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब तो यह हुआ कि आपका पोलिटिकल मैनेजमैंट पुअर था।

डॉ० सुशील इन्दौरा : हमारा पोलिटिकल मैनेजमैंट पुअर नहीं था। यह तो हरियाणा प्रदेश की भोली भाली जनता कांग्रेसियों के बहकावे में आ गई जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, 30 प्रतिशत रैवेन्यू रिसीट बढ़ी है यह मैंने माना है। 2006-07 में सभी प्रदेशों में वैट लागू हो गया। जब सैन्टर में बी०जे०पी० की सरकार थी और कांग्रेस विपक्ष में थी तो उस समय वह विरोध करती थी और अब बी०जे०पी० वाले विरोध करने में लगे हुए हैं। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : इन्दौरा जी, आप यह बताएं कि हमारा वित्तीय

प्रबन्धन ठीक है कि नहीं है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : मुख्यमंत्री जी, यह हमारा किया हुआ है इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे चूल्हे पर आप रोटियां सेक रहे हैं। (विघ्न) 2007-08 में राजस्व प्राप्तियां 19,629 करोड़ रुपये है जो कि गत वर्ष 30% इन्क्रीज हुई थी उस से 9 प्रतिशत कम है। यह जो आपने 2008-09 में राजस्व प्राप्तियां प्रस्तावित की हैं, उसकी भी रैवेन्यू रिसीट 9 प्रतिशत ही होगी यानि कि जो वैट का इफैक्ट था वह अब न्यूट्रीलाईज होने लग रहा है। अगर इस तरह से राजस्व प्राप्तियां घटती रहीं तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश को सही दिशा देंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि हमने बढ़िया वित्तीय प्रबन्धन किया है। नुकसान तो लोगों का होगा। इस बारे में आपको दो साल बाद पता चल जाएगा। नुकसान तो लोगों का होगा। दो साल बाद आप तो चले जाओगे उसके बाद हमें फिर वही माथापच्ची करनी पड़ेगी जो पहले की थी। (विघ्न) स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले वैट का जिक्र किया उसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि रैवेन्यू रिसीटस में सबसे ज्यादा अहम् रोल अगर किसी बात का रहा है तो वह स्टाम्प ड्यूटी का रहा है। हालांकि महिलाओं के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि रजिस्ट्री करवाने में एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी वे घटाएंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : हमने तो सबकी स्टाम्प ड्यूटी घटायी है। स्पीकर साहब, अगर इनको इसका फायदा उठाना हो तो जितनी भी जमीन जायदाद इनके नाम है उसको ये अपनी वाईफ के नाम करवा दें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ इसलिए मेरे पास जमीन जायदाद कहां है। (विघ्न) सर, जो सही बात है वह मैं कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आपको बोलते हुए एक घंटा हो गया है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, आप उस वक्त को याद करें जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्टाम्प ड्यूटी को 16 से घटाकर आठ प्रतिशत कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप 10.46 बजे बोलना शुरू हुए थे और अब 11.46 बज रहे हैं यानी एक घंटा आपको बोलते हुए हो गया है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, आप मुझे दस-पन्द्रह मिनट और बोलने के लिए दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपने 15 मिनट मांगे हैं तो 15 मिनट तक आप और बोल लें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, हमारी सरकार के वक्त स्टाम्प ड्यूटी 16 से 8 और 12 से 6 प्रतिशत की गयी थी। उस समय यह हमारी सरकार द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। स्पीकर साहब, इन्होंने भी स्टाम्प ड्यूटी घटायी लेकिन इसको अगर आप कम्पैरेटिव रूप से देखें तो इनके स्टाम्प ड्यूटी घटाने से हरियाणा प्रदेश के लोगों का नुकसान ज्यादा हुआ है। नुकसान कैसे हुआ है वह मैं बताता हूँ। एक तरफ तो इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी घटा दी वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कलैक्टर रेट और सर्कल रेट बढ़ा दिए। पहले तो लोगों को रजिस्ट्री करवाने में दस या पन्द्रह हजार रुपये ही देने पड़ते थे लेकिन अब कई-कई हजार रुपये देने पड़ रहे हैं। (विघ्न)

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर साहब, ये अपनी कही हुई बात को ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि बढ़ाना चाहिए और कभी ये कहते हैं कि बढ़ाना नहीं चाहिए। इनकी यह अच्छी बात नहीं है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, जो ये वाह-वाही लेने की बात कर रहे हैं मैं उस पर अपनी बात कह रहा हूँ। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैंने यह कहा है कि सबसे बड़ा कारण रैवेन्यू रिसीटस बढ़ने का स्टाम्प ड्यूटी रहा है। स्टाम्प ड्यूटी ही रैवेन्यू रिसीटस में आमदनी का जरिया बनी है। स्पीकर साहब, 2006-07 में स्टाम्प ड्यूटी से रैवेन्यू रिसीटस में एक हजार करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है और 2008-09 में यह अनुमानित 2100 करोड़ रुपये हो जाएगा यानी दुगुना हो जाएगा। स्पीकर साहब, सरकार स्टाम्प ड्यूटी और वैट से कमा तो रही है लेकिन खर्च नहीं कर रही है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : लेकिन हम आपकी तरह लोगों को पीट पीटकर तो नहीं ले रहे हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : आप पीट पीटकर न ले रहे हों लेकिन एक तरह से आपने भी लोगों को महंगाई से मारा ही है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जब इनका राज था और उस समय सरकार की ट्रैजरी में जो स्टाम्प ड्यूटी से आमदनी थी वह 560 करोड़ रुपये के लगभग थी और अब 2007-08 में यह 2200 करोड़ रुपये की हो गयी है यानी 400 परसैंट की इन्क्रीज है। यह तब है जब हमने महिलाओं के लिए 2 परसैंट की छूट भी दी है। वह छूट आपने नहीं दी थी। उस स्थिति में भी 400 परसैंट की इन्क्रीज हुई है। ये साथी जिस कलैक्टर रेट की बात कर रहे हैं। कलैक्टर रेट का बढ़ना रुटीन जॉब है। रुटीन में 6 महीने में या एक साल में देखा जाता है उस हिसाब से रेट फिक्स होते हैं। यह कोई मैंडेटरी नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम कलैक्टर को कहें कि रेट बढ़ाओ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों का कितना नुकसान कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि कुण्डली-मानेसर-पलवल एक ऐसी योजना है जिसके पूरा होने से हरियाणा प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से बहुत फायदा मिलता, विकास होता, हब बनते, विकास के प्रोजैक्ट तैयार किए जाते लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार जब आई उसके बाद से उस योजना को साइड लाइन कर दिया गया। उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। 500 करोड़ रुपये का दावा तो कर दिया गया कि हमने फायदा कर लिया लेकिन ये बताएं कि के०एम०पी० एक्सप्रैस कब पूरा कर देंगे। अब मैं स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय की बात करना चाहूँगा। मैंने अभी-अभी जीरो ऑवर में कहा कि लोकतंत्र में हर आदमी को अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करना जरूरी है और अपनी बात कहने के लिए वह प्रदर्शन कर सकता है। वह अपनी बैठक कर सकता है, सभाएं कर सकता है। रोहतक जिले में अनुसूचित जाति के वर्ग 'ए' के लोग (विघ्न) हमें 'ए' या 'बी' से कोई वो नहीं है, मैं तो सामाजिक न्याय की बात करता हूँ वे अपना आंदोलन कर रहे थे उन पर लाठियां बरसाई गईं। उन लोगों के नुमाइंदों को बुलाकर उनसे पूछा जाना चाहिए था कि आपकी समस्या क्या है?

श्री अध्यक्ष : आपको बताया गया था यह सब-ज्यूडिस मैटर है। यह मैटर कोर्ट में पैंडिंग है। यह बजट डिस्कशन का प्वायंट नहीं है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सब-ज्यूडिस मैटर होने के बावजूद भी सरकार उसमें कोई न कोई प्रावधान निकाल सकती है। पंजाब सरकार ने भी कहा है कि मजहबी सिखों को अलग से आरक्षण मिले।

श्री अध्यक्ष : आपको बता दिया गया है कि इस बारे में जो कोर्ट का फैसला आएगा वह लागू हो जाएगा। इससे ही यह बात खत्म हो जाती है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : कानून व्यवस्था के बारे में एक नहीं अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में मूर्तियों की चोरी हुई। थानेदार को पीट पीटकर मार दिया जाता है। चारों तरफ मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। संगठित क्राइम होते हैं जैसे किसी को उठा लिया जाता है और फिर उससे रिहाई के लिए फिरौती मांगी जाती है। ऐसी व्यवस्था अच्छी कानून व्यवस्था या अच्छे विकास की परिचायक नहीं है। (विघ्न)

प्रो० छतर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पिछले साढ़े पांच साल में जिन अपराधियों को जेलों में डालकर अपराध का ताना बाना चलाया हुआ था, अब उनमें से बहुत से लोग इनकी सरकार जाने के बाद अपना रास्ता बदल गए। बहुत सारे ऐनकाउंटर हो गए। अभी जो कुछेक बचे हुए हैं वे कहीं न कहीं वारदातों में संलिप्त होकर पुलिस की निगाहों से बचकर चले जाते हैं। अब पुलिस पूरी तरह उन पर शिकंजा खींच कर चल रही है। इन्दौरा साहब, आप थोड़ा ध्यान रखना, बचाव करके रखा करो। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया चलने लग रही है। आप लोगों को भी अब सांस लेना मुश्किल हो जायेगा अगर आप अपराध की प्रवृत्ति नहीं छोड़ोगे तो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हाँ, डॉक्टर सीता राम जी, आप क्या कह रहे थे।

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, इनका भी कुछ करो यह कुवांरा घूम रहा है सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। (हंसी)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि गोवा प्रदेश के बाद हरियाणा प्रदेश पर-कैपिटा इन्कम में सबसे आगे है। अच्छी बात है, लेकिन वही बात हमारे एक साथी अपने बजट अभिभाषण पर चर्चा के शुरुआत में कही थी, कह दिया कि प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से जब इनेलो की सरकार थी उस समय हमारा प्रदेश 13वें स्थान पर था। ये कहते हैं कि 13वें स्थान पर था। पर कैपिटा इन्कम की शुरुआत कब हुई थी और प्रदेश को अवार्ड कब मिला था, यह भी मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में बता दें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, पर कैपिटा इन्कम की बात नहीं बल्कि पर कैपिटा इन्वेस्टमैंट की बात कही थी और उस हिसाब से हम 13वें स्थान पर थे। ये लोग पढ़ते तो हैं नहीं, सुनते तो हैं नहीं, बोलते कुछ हैं, जवाब कुछ दे रहे हो, पर कैपिटा इन्कम नहीं, पर कैपिटा इन्वेस्टमैंट की बात कही थी जो हम 13वें स्थान पर थे जिसकी आप चर्चा कर रहे हो।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, 10.3.2008 को 3.10 बजे अभिभाषण पर चर्चा शुरू करते हुए यह बात कही गई थी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत उस समय कुमारी शारदा राठौर जी ने की थी माननीय सदस्य को लिंग-पुलिंग का कन्फ्यूशन है उसको ये दूर कर लें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैंने 'साथी' शब्द ही कहा है, मुझे लिंग-पुलिंग का अच्छी तरह से पता है। 10 तारीख को 3-10 बजे जब शारदा राठौर जी ने यह बात कही थी, हो सकता है उन्होंने गलती से कहा हो, इनके ध्यान में नहीं रहा हो, उस समय यह बात कही थी कि पर कैपिटा इन्कम के बारे में। (विघ्न) मैं तो टाईम भी बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप बजट पर बोलें। ठीक है, कह दिया होगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आप वित्तीय प्रबन्धन पर बोलिये।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, ग्रान्ट इन ऐड में विभिन्न संस्थाएं और केन्द्र की सरकार स्टेट की सरकारों को ग्रान्ट देती है कि सारे विभागों की मूलभूत सुविधाओं को पूरी करवा सके और अच्छे काम कर सकें। वर्ष 2007-2008 में ग्रान्ट इन ऐड 2828.96 करोड़ रुपये थी जो कि सरकार ने म्युनिस्पिल कारपोरेशन, बोर्डों और पंचायती राज को दी थी और वर्ष 2008-2009 में यह ग्रान्ट इन ऐड घटकर 2246.47 करोड़ रुपये रह गई है, इसका घटने का कारण क्या है। सरकार ग्रान्ट इन ऐड इसलिए देती है कि विकास के काम करें तो फिर यह वर्ष 2008-2009 में कम क्यों हो गई, पिछले साल ज्यादा थी अब क्या हो गया? जबकि सरकार ने विकास की बात तो बहुत की है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि जब वर्ष 2004-2005 में इनेलो की सरकार ने कार्यभार छोड़ा था उस समय म्यूनिस्पिल बॉडिज को कुल पैसा 80,78,75,000 रुपये दिये गये थे और इस साल 2007-2008 में माननीय वित्त मंत्री जी ने 169,78,83,000 रुपये दिये हैं जो कि 100 प्रतिशत से अधिक है। इन्दौरा जी, आप जरा अपने आंकड़े ठीक कर लीजिये।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, आंकड़ों की जैसी जादूगरी केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने की है वैसी ही आंकड़ों की जादूगरी करने में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी अच्छे खासे माहिर हैं। मैं कोई अर्थ-शास्त्री तो हूँ नहीं, मुझे जो जानकारी मिली मैं उन्हीं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ। कहीं गलती से लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप उसको ठीक कर देंगे क्योंकि यह तो हरियाणा के हित की बात है। मैं तो नहीं कहता कि मैं राजा हरिशचन्द्र हूँ। जहां तक सैलरीज और पेंशन के रेशो की बात है तो रिवैन्यू रिसीटस के हिसाब से आप देखें तो इन्होंने कर्मचारियों को अच्छा लाभ देने का प्रयास तो जरूर किया है लेकिन भविष्य में उसका परिणाम ठीक नहीं निकलेगा। अच्छा वित्तीय प्रबन्धन करके लाभ दिया जाए तो उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं लेकिन महंगाई के अनुसार पैंशन और सैलरीज़ बढ़ानी जरूरी है। इन्होंने अगले वेतन आयोग की भी सिफारिश कर दी लेकिन अच्छे वित्तीय प्रबन्धन की इंडीकेटर्ज क्या हैं? राजस्व प्राप्तियां जो हैं अगर ज्यादा भाग 65 से 70 प्रतिशत तक एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च किया जाए और 30 प्रतिशत सैलरीज और तनख्वाहों पर खर्च करें तो ज्यादा बढ़िया रहता है।

12.00 बजे

श्री अध्यक्ष : यह प्लान और नॉन प्लान बजट की बात तो आपने शुरू में भी बता दी थी you are repeating same thing again and again.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये कंफ्यूजन में बार-बार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे क्रिकेट के मैच में बैटसमैन को रनर की जरूरत होती है उसी तरह सीता राम जी इन्दौरा साहब के रनर का काम कर रहे हैं। इन्दौरा साहब डॉ० सीता राम जी के कागज लिए हुए हैं, इनसे पढ़े नहीं जाते इसलिए सीता राम जी बैठे-बैठे इनको आंकड़े पढ़कर बताते हैं और फिर ये बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपको बोलते हुए एक घंटा 16 मिनट हो गए है। आपने 15 मिनट मांगे थे वह मैंने दे दिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बैठने के लिए कहें तो मैं अभी बैठ जाता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनको 10 मिनट का समय और दे दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये जब तक बोलना चाहें बोल लें परन्तु मेरा निवेदन है कि ये वित्तीय प्रबन्धन पर बोलें, इधर उधर की बात न करें और बजट पर ही बोलें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो वित्तीय प्रबन्धन पर ही बोल रहा हूँ लेकिन ये मुझे दूसरी तरफ खींच लेते हैं, कभी कोई खींच लेता है और कभी कोई खींच लेता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, ये असल में सरकार की तारीफ करना चाहते हैं लेकिन इनको थोड़ा सा डर है। इनके पास सरकार की नीतियों को लेकर और बजट को लेकर बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सम्मानित सदस्य डरकर तारीफ नहीं करना चाहते हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, पेंशन और तनख्वाहों के खर्चों की प्रतिशतता बढ़ी है जो कि बढ़ कर 36.86 हो गई है। वित्त मंत्री जी, आपने अपने बजट में एक लाइन लिखी है कि वर्ष 2006-07 के बाद 2007-08 में यह खर्चा 36.86 हो गया है, यह ठीक इंडीकेटर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको इनके राज के आंकड़े बता रहा हूँ। 2004-05 में जब इनकी सरकार का लास्ट ईयर था तो उस वक्त यह रेशो 40.90 प्रतिशत था यानि लगभग 41 प्रतिशत इन चीजों पर ये लोग खर्च करते थे। हम सरकार में आने के बाद इसको 41 से 34 प्रतिशत पर लेकर आए और फिर 34 से 28 प्रतिशत पर लेकर आए और अब जो 36 का आंकड़ा ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बढ़ गया है तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि इन्होंने बजट को पढ़ा होगा उसमें 1550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है वह छठे वित्त आयोग की जो रिकमैंडेशंज आनी है उसके लिए रखा गया है। अगर 30-35 प्रतिशत सैलरीज बढ़ेंगी तो पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, वह प्रोवीजन हमने बजट में किया है और इसको ध्यान में रखते हुए किया है इसलिए इसके बढ़ने का हमें अफसोस नहीं है। हम हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छी सुविधा और अच्छे ग्रेड देंगे। क्या इसमें इनको कोई ऐतराज है?

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार अच्छे ग्रेड दे इसके लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 1999-2000 में जब आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी थी उस समय पेंशन और सैलरीज पर खर्च 49.34 प्रतिशत था उसके बाद हमारी सरकार उसको कम करके 2004-05 में 33.43 प्रतिशत पर ले आई थी उसके बाद 2005-06 के दौरान ये खर्चे 26.89 प्रतिशत पर आ गये थे। उसके बाद वर्ष 2007 के दौरान कम होकर 21.84 प्रतिशत हो गये, उसके बाद ये खर्चे बढ़कर 23.68 प्रतिशत हो गये और अब यह खर्च 2008-09 में बढ़कर 26.89 प्रतिशत होने की संभावना है। इस तरह के इंडीकेशन प्रदेश के लिए अच्छे नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों पर आधारित बात कर रहा हूँ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आपका बहुत-बहुत आभारी भी हूँ कि आपने विधान सभा को बहुत सुन्दर बनवाया है। कई मामलों में हम यहां लोकतंत्र की बात करते हैं और उसी लोकतंत्र के नाते मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि यह बहुत अच्छी बात है कि विधान सभा को रैनोवेट करके बहुत अच्छा बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपने विधान सभा को रैनोवेट करवाया है और उसके लिए हमारे उदार हृदय वित्त मंत्री जी ने पैसा दिया है। लेकिन क्या इन्होंने यह भी चैक किया है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। गड़बड़ी तो हमारे अंदर है जो हमें बोलने नहीं दिया जाता। अध्यक्ष महोदय, यदि हमें हरियाणा प्रदेश के लोगों की बात यहां नहीं कहने दी जायेगी तो इस विधान सभा को इतना सुन्दर बनाने का क्या फायदा है। सरकार के एक मंत्री ऐसे हैं जिनको प्रस्ताव लाने के अलावा कोई काम नहीं है और वह भी सिर्फ निंदा प्रस्ताव लेकर आते हैं। अगर प्रस्ताव ही लेकर आना है तो चण्डीगढ़ में हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बनाने का प्रस्ताव लेकर आओ, हरियाणा के पंचकूला शहर में अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली के स्तर पर बनाने का प्रस्ताव लेकर आओ, उसमें हम सरकार का साथ देंगे। इसके अतिरिक्त एस०वाई०एल० का प्रस्ताव लेकर आओ, हमारे जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं उनका प्रस्ताव लेकर आओ उसमें हम सरकार का पूरा साथ देंगे। ऐसी बातें सरकार के लिए अच्छी नहीं हैं कि सरकार का एक मंत्री जब देखो तब निंदा प्रस्ताव लेकर आये और भोले-भाले मुख्यमंत्री को बीच में लपेट ले। अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार प्रदेश हित में कोई प्रस्ताव लेकर आयेगी तो इसमें हम सरकार का साथ देंगे।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, क्या पानी के बराबर बंटवारे के प्रस्ताव का आप समर्थन करेंगे?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पानी के समान बंटवारे के बारे में पिछले 7 दिनों से चर्चा हो रही है और हम भी पानी के न्यायोचित बंटवारे के विरोध में नहीं हैं। (Interruption)

Mr. Speaker : Indora Ji, please carry on your speech.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले कुछ दिनों से अभ्यासी हो गया हूँ इसलिए बार-बार बैठ रहा हूँ। यहां पर यह परम्परा हो गई है कि जब विपक्ष का कोई सदस्य बोल रहा होता है तो उसको इन्टैप्ट करने के लिए उंगलियों से इशारे करके सत्तापक्ष के सदस्यों को प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा कर दिया जाता है। यही कारण है कि मेरे जैसा गरीब सदस्य बैठ जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय के वित्तीय प्रबन्धन की वजह से जो वित्त व्यवस्था

में सुधार हुआ था मुझे चिन्ता है कि आने वाले वक्त में कहीं वित्तीय अनुशासनहीनता और वित्तीय प्रबन्धन की घटती हुई मजबूती की वजह से हरियाणा प्रदेश के लोगों का नुकसान न हो जाये। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे थोड़ा गहराई में जायें। अगर आपने हांसी-बुटाना नहर के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है तो उसको आपको समय पर बनवाना चाहिए और इसी प्रकार से अगर आपने बिजली परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तो आपको उनको भी समय पर ही पूरा करवाना चाहिए। आज मुझे आपका कोई भी प्रोजैक्ट ऐसा नहीं दिखाई देता जो कि समय पर पूरा हो सके। आपने जो हरियाणा प्रदेश के लोगों को तीन साल के अन्दर पूरी बिजली देने का वायदा किया था मुझे नहीं लगता कि इस वायदे को आप तीन साल तो क्या जो अभी आपके दो साल रहते हैं उनमें भी पूरा कर पायेंगे। इसलिए ऐसा प्रबन्धन किया जाये जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों का हित हो। यहां पर पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। यहां मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के मुद्दे पर हम हर वक्त आपके साथ रहेंगे। यहां पर यही बात होनी चाहिए कि हम आपस में चर्चा करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को फायदा पहुँचा सकें। इसलिए ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि सभी मूलभूत सुविधाओं से हरियाणा प्रदेश सम्पन्न हो। आज हालत यह है कि कहीं पर सड़क ठीक नहीं है और कहीं पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। कल ही भिवानी के लोगों द्वारा रास्ता जाम करने की खबर को अखबार में बड़े-बड़े शब्दों में लिखा हुआ था। क्या इसलिए लोग सड़कों पर आते हैं कि उन्हें पानी ज्यादा दे दिया? नहीं, लोग इसलिए ही सड़कों पर आते हैं कि उन्हें पीने का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। लोग यह चाहते हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले। लोग यह कहते हैं कि हमें उचित कानून व्यवस्था मिले। इसलिए वित्त मंत्री जी ऐसा प्रबन्ध कीजिए कि सुशासन हो लेकिन मुझे पता है कि आप यह नहीं कर पायेंगे क्योंकि आप लोगों का तो आपस में ही कॉ-आर्डीनेशन नहीं है। आप लोग तो आपस में ही अपनी बात को नहीं समझा पाते। इसलिए यह चिन्ता का विषय है। हरियाणा प्रदेश के हितों के मामले में हम कहीं कोई विरोध नहीं करेंगे। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप कुछ करके दिखाईये, कोरी घोषणाओं से काम नहीं चलेगा और जो लोग ठीक आपके पीछे बैठे हैं उनसे बचकर रहना क्योंकि वे ही कभी न कभी आपकी पीठ में छुरा घोंपकर हरियाणा प्रदेश के लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० इन्दौरा, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पिछले सदन में आपके नेता ने यह बात कही थी कि "किसी ने किसी से कहा कि हलुआ बन रहा है तो उसने कहा कि सानु की।" तो उसने फिर कहा कि "आपके लिए बन रहा है तो उसने कहा कि तुहानू की।" तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आप इसकी चिन्ता न करें। इसके बारे में वे अपने आप देख लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डॉ० इन्दौरा, दूसरों की चिन्ता मत करो आपको अपनी चिन्ता करनी चाहिए। आप अपनी चिन्ता नहीं करते तभी तो पीछे बैठे हुए हो। मुझे अपनी चिन्ता है तभी तो आगे बैठा हूँ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह बात जगजाहिर है और मैं विधान सभा में भी इस बात को कहता हूँ कि मेरे आदरणीय नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला ने ही मुझे यहां पर बिठाने का काम किया है। इसलिए हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित की लड़ाई लड़ना भी मेरा

[डॉ० सुशील इन्दौरा]
कर्त्तव्य है। अगर हम अपनी आईडैंटिटी के साथ-साथ अपने नेता का भी आदर करते हैं तो फिर किरण चौधरी जी क्यों खड़ी हो जाती हैं जब मैं कहता हूँ कि 'हल रख दिया' ये क्यों खड़ी हुई?

वन राज्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा को हल भेंट करते हैं तो इससे इनको क्या तकलीफ है। इस बारे में इन्होंने यहां पर जो बातें कही हैं वे इनको शोभा नहीं देतीं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर ये पानी के समान बंटवारे की बात करते हैं तो इन्हें समान विकास की बात भी करनी चाहिए। अगर ये अपने डाटा को कम्पेयर करें तो इनको विकास के मामले में रोहतक, सोनीपत और सिरसा, भिवानी व हिसार में अन्तर का पता चल जायेगा। सड़कों को देखिए सड़कों का बहुत बुरा हाल है। कितनी सड़कें आपने बनाई हैं। आपने कितना रेवेन्यू कलैक्शन किया और उसमें से कितना प्रतिशत आपने सिरसा, भिवानी और हिसार में लगाया। मैं तो आपसे ज्यादा नहीं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मेरे एम०एल०ए० कोटे से कुतावड़ से लेकर रानियां तक घग्गर नदी पर एक पुल ही बना दें तो उसी से मैं समझूंगा कि सरकार ने विकास का कोई न कोई तो काम किया है। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कुतावड़ से लेकर रानियां तक ओटू नहर पर ही पुल बना दें।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, ओटू नहर नहीं ओटू झील है उसमें घग्घर का पानी आता है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, मैं कहना चाहता हूँ कि बजट की बातें तो मैं बता चुका हूँ बाकि जो जरूरी चीजें हैं चाहे वह कानून व्यवस्था की बात हो या आर्थिक विकास की बात हो वह भी आप कीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी के द्वारा 18 मार्च, 2008 को जो 2008-09 का बजट पेश किया गया है मैं उसका अनुमोदन करने के लिए और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं हमारी यू०पी०ए० की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी तथा हमारे प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने 2008-09 के केन्द्रीय बजट में देश के सभी छोटे किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किये। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ और बधाई देती हूँ कि उनकी मांग पर और उनके प्रयासों से ही ये कर्जे माफ किये जा सके। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य आई०जी० शेर सिंह पदासीन हुए)** पिछली सरकार की कोई दीर्घकालिक योजना न होने के कारण वे राज्य का खजाना खाली छोड़ गये थे। परिणामस्वरूप हमारी सरकार को अनेक कठिनाईयों से जूझना पड़ा। इसके उपरान्त भी गत 3 सालों में कृषि सैक्टर की तरफ ध्यान देना, उच्चकोटि की शिक्षा प्रदान करना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण पर बल देना और सुदृढ़ आधारभूत ढांचा तैयार करना हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। इन सबका हमारी सरकार ने रोड मैप तैयार किया

है और हमारी सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। हमारी सरकार जो कहती है वह कर दिखाती है। हमारी सरकार की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, वह पिछली सरकार की तरह झूठे नारे, झूठे वायदे और झूठे फाऊंडेशन स्टोन नहीं लगाती। मैं अपनी सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से गोवा के बाद हरियाणा दूसरे स्थान पर है। हरियाणा राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम को क्रियान्वित करने में अग्रणी है। एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के द्वारा राजस्व घाटा 2008-09 तक शून्य करना था किन्तु मैं अपने मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि हमारी सरकार ने 2005-06 में ही यानी दो साल पहले ही अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। इसीलिए हमारी सरकार भारत सरकार की तरफ से ऋण राहत और ब्याज राहत के रूप में दोहरे लाभ प्राप्त कर रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने खर्च की गुणवत्ता में सुधार किया है। पूंजीगत खर्च जो विकास दर को तेज करता है, जो कि 2004-05 में 1105 करोड़ रुपये था, वह 2008-09 के बजट अनुमानों में 3751 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव हमारे वित्त मंत्री जी ने रखा है। राज्य सरकार का शुद्ध ऋण जो कि 2003-04 में 2495.24 करोड़ रुपये था वह 2007-08 में केवल 46.62 करोड़ रुपये रह जाने की सम्भावना है। योजनागत खर्च जो पिछली सरकार के शासनकाल में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये पर अटका आ रहा था अब हमारी सरकार के 3 साल के शासनकाल में 3 गुणा से अधिक बढ़ गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी कांग्रेस की सरकार को अपने अनुसूचित जाति के भाई बहनों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, महिलाओं और बच्चों के प्रति गहरी चिन्ता है जबकि अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या ही 19.35 परसेंट है किन्तु उनके ऊपर खर्च होने वाली राशि 2008-09 के दौरान योजनागत परिव्यय की 21.55 प्रतिशत है। जिसके पास रहने के लिए आशियाना नहीं है जो बी०पी०एल० और अनुसूचित जाति के लोग हैं हमारी सरकार की हर उस व्यक्ति को आवासीय प्लॉट देने की योजना भी है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पहली बार नये कदम उठाए हैं और एक नई पहल की है उसके लिए भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारी यू०पी०ए० की अध्यक्षा की सलाह से किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे मुआफ करके 'जय जवान जय किसान' के नारे को बुलन्द किया है। हमारी सरकार ने बिजली की बचत करने वाली सी०एफ०एल० पर पिछले बजट में कर मुआफी दी थी और इस साल बजट में ट्यूब की चोक पर भी यह राहत देने का इरादा किया है। हमारी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 3510 रुपये कर दी है जो कि हमारी सरकार का एक सराहनीय कार्य है और पूरे देश में हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा दर पर न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। सभापति महोदय, इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को भी लाभ देने का प्रयास किया गया है। हमारी सरकार चाहती है कि सही मायने में कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण किया जाए। इसके लिए 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति शिक्षा प्रोत्साहन' नामक क्रान्तिकारी योजना हमारी सरकार ने शुरू की है। इस योजना के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के सभी बच्चों को प्रतिमास छात्रवृत्तियां दी जाएंगी और उन्हें यूनिफार्म, किताबें और स्कूल बैग्ज़ इत्यादि का खर्चा भी दिया जाएगा। सभापति महोदय, हमारी सरकार राज्य में बी०पी०एल० के परिवार की छात्राओं को भी यह सुविधा उपलब्ध करवायेगी। मैं सरकार को भी इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि राज्य में रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड सभी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 50% से अधिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सभापति महोदय,

[श्रीमती सुमिता सिंह]

हमारी सरकार ने एक और सराहनीय कदम उठाया है और वह है अनुसूचित जाति के सदस्यों को मकान के निर्माण के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देने की योजना। हम सभी जानते हैं कि पिछली सरकारों ने बिजली के उत्पादन के मामले में कोई कदम नहीं उठाये। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली के क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में उच्चकोटि की बिजली सप्लाई कराने की विकास नीति की अपेक्षा है। हमारी सरकार ने सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए नई पहल की है। यमुनानगर में 600 मेगावाट, हिसार के खेदड़ में 1200 मेगावाट का थर्मल पॉवर प्लांट, झज्जर में 1500 मेगावाट के थर्मल पॉवर प्लांट में हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार के प्रयासों से वर्ष 2009-2010 तक उत्पादन शुरू हो जाएगा और यमुनानगर की एक इकाई में तो उत्पादन शुरू भी हो गया है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ऊर्जा संरक्षण में विश्वास रखती है इसीलिए हरियाणा के 650 गांवों में सी०एफ०एल० लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री जी आज बिजली के उत्पादन के लिए ऊर्जा संरक्षण के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत से ऐरियाज ऐसे हैं जहां पर बिजली की चोरी की जाती है। बिजली की चोरी को रोकने के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि उन ऐरियाज में बिजली की तारों को अण्डर ग्राउण्ड किया जाए। हमारी सरकार ने प्रदेश में पानी के समान वितरण के लिए भाखड़ा मेन लाईन को हांसी बुटाना ब्रान्च से जोड़ने के लिए 109 किलो मीटर बहुउद्देशीय सम्पर्क नहर का निर्माण कार्य शुरू किया है जिसके चालू वित्त वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है। मैं अपनी सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के तहत अनुसूचित जाति व गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को गांवों में वर्ष 2009-2010 तक सभी को फ्री पानी की टंकी, टूटी तथा पानी के कनैक्शन्ज दिये जाएंगे। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एक और जो सराहनीय कदम उठाया है वह है सामान्य वर्ग के परिवारों को भी पानी के निजी कनेक्शन्ज के लिए गांवों में 500 रुपये तथा शहरों में 1000 रुपये कनैक्शन्ज फीस मुआफ करना। सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए बजट में 1237.44 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जो कि पिछले वर्ष से ज्यादा है। हमारी सरकार सड़कों और आर०ओ०बीज० के निर्माण पर भी विशेष ध्यान रख रही है। प्रदेश में आप कहीं पर भी चले जाएं नई सड़कें और आर०ओ०बीज० बड़ी तेजी से बनते नजर आएंगे। पानीपत का फ्लाईओवर जो बड़ी तेजी से बन रहा है शायद हिन्दुस्तान में इसके मुकाबले में कोई और इतना बड़ा फ्लाईओवर नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि करनाल में जो फ्लाईओवर बन रहा है, जिसका पिछली सरकार के वक्त में फाऊंडेशन स्टोन रखा गया था और उस सरकार ने उसको नहीं बनवाया था, मुख्यमंत्री जी, आज आपके प्रयासों के कारण उस फ्लाईओवर का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और वह जल्दी ही बनने जा रहा है। इस फ्लाईओवर के बनने के कारण वहां के लोगों को बहुत लाभ होगा। हमारी सरकार में वित्त मंत्री जी ने सड़क, परिवहन और नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 2008-09 के बजट में 1921.69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात की भी बधाई देती हूँ कि खराब मौसम के बावजूद सरकार द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति, ऋण सहायता, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इस सहायता से और हमारे किसानों की कड़ी मेहनत से प्रदेश में वर्ष 2007 में खरीफ खाद्यान्नों का 49.26 लाख क्विंटल का अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। हमारी सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है। इसी तरह से हमारी सरकार ने कृषि ऋणों

पर ब्याज की दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया है। हमारी सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की तरफ भी पूरी तरह से रहता है। फिलहाल जो राज्य सरकार ने नई स्कीम शुरू की हैं जिसका नाम 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति गांव उत्थान एवं मलिन बस्ती विकास योजना' है, इस स्कीम के तहत जिस गांव में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के लोग होंगे उन गांवों में 50 लाख रुपए खर्च करके उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का गांवों की सैनिटेशन की तरफ भी खास ध्यान रहता है इसलिए गांवों में सफाई का ध्यान रखते हुए 11,000 सफाई कर्मी नियुक्त किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप गांवों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं इसलिए मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरफ दिलाना चाहूँगी कि आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पंचायतों के पास जगह नहीं है, न ही पंचायत के पास पैसा है। वहां पर हमारी महिलाओं को और हमारी बहनों को शौचालय की बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वहां की पंचायत शौचालयों को नहीं बना पा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां पर ऐसा कोई प्रावधान करें जिससे हमारी बहनों को गांवों से बाहर शौचालय के लिए न जाना पड़े। सभापति महोदय, मैं गांवों के विकास के लिए वित्तमंत्री जी को बधाई दूंगी कि उन्होंने इस साल के बजट में 634.87 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। हमारी सरकार शहरों पर भी खास ध्यान दे रही है। सभापति महोदय, मैं यहां पर एक शहरी होने के नाते मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने जो शहरों में हाऊस टैक्स हटाया है यह इस सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। पिछली सरकार ने हाऊस टैक्स को 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा दिया था। इसकी वजह से उस वक्त शहरों के लोगों में हाहाकार मच गई थी और आम आदमी को अपने घर में रहने के लिए टैक्स देना पड़ता था।

श्री सभापति : मैडम जी, गांवों में चूल्हा टैक्स भी हटा दिया गया है।

श्रीमती सुमिता सिंह : मुख्यमंत्री जी, आप आज इतना कुछ शहरों के लिए कर रहे हैं इसलिए मैं आपका ध्यान शहरों में जो पार्क हैं उनकी तरफ भी दिलाना चाहूँगी। आज शहरों में पार्कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मुख्यमंत्री जी, हमारे करनाल में कर्णताल के नाम से एक ऐतिहासिक पार्क है। वहां पर राजा कर्ण बैठकर सोना दान किया करते थे। कृपा करके आप उस पार्क का भी विकास करवाएं। मुख्यमंत्री जी आपने गांवों में सफाईकर्मियों की भर्ती करके बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसी प्रकार से आप शहरों में भी सफाईकर्मियों की भर्ती करवाएं क्योंकि शहरों में भी सफाई कर्मचारियों की बड़ी भारी कमी है। मैं मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी को बधाई देती हूँ कि शहरों के विकास के लिए पिछले साल के बजट के मुकाबले में बढ़ौत्तरी करते हुए 2008-09 में 399.98 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

श्री सभापति : मैडम जी, आप अपनी स्पीच खत्म करने की कोशिश करें।

श्रीमती सुमिता सिंह : सभापति महोदय, शिक्षा के लिए इस साल के बजट में 3139.08 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है जबकि 2004-05 में शिक्षा के लिए सिर्फ 1450 करोड़ रुपए ही बजट में रखे गए थे। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार शिक्षा के लिए कितनी सीरियस है। इसी तरह से हमारी सरकार ने कॉलेजिज के लिए भी नए कोर्सिज शुरू किए हैं। जिससे आने वाले समय में हमारे नौजवान बच्चों को नए रोजगार मिलेंगे। कॉलेजिज में ऐजुसैट का विस्तार किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे करनाल के गवर्नमैंट कॉलेज

[श्रीमती सुमिता सिंह]

के स्टूडैंट्स की डिमांड है कि वहां पर एम०ए० इकोनोमिक्स की क्लासिज़ भी शुरू की जाएं। कृपा करके वहां पर आप एम०ए० इकोनोमिक्स की क्लासिज़ भी शुरू करवा दें। चेयरमैन सर, सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत से बच्चों को काफी फायदा हो रहा है किन्तु मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूँगी कि सर्व शिक्षा अभियान के कार्यों में साईंस टीचर्ज को अभी तक लगाया जाता रहा है वैसे ही साईंस टीचर्ज की स्कूलों में कमी है और साईंस टीचर्ज को सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यों में लगाने के कारण बच्चों का काफी नुकसान होता है इसलिए मेरा निवेदन है कि साईंस टीचर्ज के बजाए आर्ट फैक्ल्टी के टीचर्ज को इन कार्यों में लगाया जाए। इसी तरह से सरकार ने जो गैस्ट टीचर्ज लगाए हैं वह एक बहुत ही सराहनीय काम है क्योंकि इससे गांवों के नौजवानों को रोजगार मिलता है। मैं मुख्यमंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूँगी कि जो ड्राईंग टीचर्ज और पी०टी०आई० टीचर्ज की भर्ती पर अभी तक पाबंदी लगी हुई है उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए क्योंकि गांवों के बच्चों का ड्राईंग से माईंड डिवैल्प होता है। स्कूलों में पी०टी०आई० टीचर्ज की बहुत कमी है इससे हमारे गांवों की लड़कियां खेलने में पीछे रह जाती हैं। चेयरमैन साहब, हमारी सरकार ने खेलों पर भी बहुत ध्यान दिया है। अनेक गांवों में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं इनके बनने से गांवों के बच्चों को बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यहां भी एक प्रार्थना करना चाहूँगी कि जब आपने इतना कुछ गांवों के बच्चों के लिए किया है तो यह बात भी आप सुनिश्चित करें कि जो भी ग्रामीण स्टेडियम के लिए कोच आप नियुक्त करें वह ग्रामीण हल्कों का ही होना चाहिए। उसको इस शर्त के साथ रखा जाना चाहिए कि वह गांव में ही काम करेगा न कि शहरों में। चेयरमैन साहब, स्वास्थ्य के ऊपर भी हमारी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नये हॉस्पीटल्ज, पी०एच०सीज० और टी०बी० सैंटर्ज खोले जा रहे हैं। चेयरमैन साहब, मुख्यमंत्री जी का बड़ा दिल है इन्होंने करनाल में कल्पना चावला मैडीकल कॉलेज बनाने की घोषणा कर रखी है इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि इस साल के बजट में हमारे करनाल में यह मैडीकल कॉलेज खोलने का भी प्रावधान रखा जाए और इसको जल्दी से जल्दी बनवाया भी जाए। चेयरमैन साहब, हरियाणा सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं घोषित भी की हैं और उन्हें लागू भी किया है। मुख्यमंत्री जी ने और भी कई नयी स्कीम्ज इस वर्ष घोषित की हैं जोकि बहुत सराहनीय बात है। इसी तरह की एक स्कीम जिसमें 6 से 18 वर्ष की आयु वाले 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाएगी। इसी तरह से वृद्धों के लिए डे-केयर सैंटर्ज खोलने का भी उन्होंने जो निर्णय लिया है वह सराहनीय है। चेयरमैन साहब, मैं विधवा बहनों के लिए भी आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि जिन विधवा बहनों के बच्चे छोटे हैं या माईनर हैं उनको भी आरक्षण देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। हुडा द्वारा जो प्लाट्स दिए जाते हैं उनमें विधवाओं के लिए भी आरक्षण देने का प्रावधान रखा जाना चाहिए। चेयरमैन साहब, जिस तरह से सरकार ने किसानों के लोन माफ किए हैं उसी तरह से हमारी विधवा बहनों के हजबैंड की अगर डैथ हो जाती है तो उनको पहले से लिया हुआ लोन देना मुश्किल हो जाता है इसलिए इस तरह के लोन को भी माफ किया जाना चाहिए। चेयरमैन साहब, इसी तरह से हमारी सरकार ने तकनीकी शिक्षा के विस्तार पर भी अत्याधिक बल दिया है जिसके कारण अब हमारे नौजवानों को रोजगार के नये अवसर प्रदान हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि विमैन पोलेटैक्निक भी हरियाणा में जल्द से जल्द बनाया जाए। चेयरमैन साहब, उद्योग के बिना कोई भी प्रदेश तरक्की नहीं कर

सकता। जब से हमारी यह सरकार सत्ता में आयी है तब से 33 हजार करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश हरियाणा में हुआ है। राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 92 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें 2 लाख करोड़ रुपयों से अधिक का निवेश होगा और बीस लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। हमारी सरकार ने एन्वायर्नमैंट के लिए भी बहुत कुछ किया है। हर वर्ष बहुत ज्यादा तादाद में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि हरियाणा में एन्वायर्नमैंट को ठीक ठाक रखने के लिए और पोल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली की तर्ज पर सी०एन०जी० की बसिज को शुरू किया जाए। चेयरमैन साहब, करनाल में एक नया बस स्टैंड बनना था। यह बस स्टैंड पिछले तीन साल से पैंडिंग है। मुख्यमंत्री जी, कृपा करके इसको भी शीघ्र ही बनाया जाए। चेयरमैन साहब, हमारी सरकार के द्वारा जमीनों के अधिग्रहण होने पर उन जमीनों के लिए फ्लोर रेट्स फिक्स किए गए हैं उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगी कि पानीपत और करनाल में 25-30 किलोमीटर का फर्क है। पानीपत के एन०सी०आर० में आने के कारण वहां फ्लोर रेट करनाल से बहुत ज्यादा हैं। मैं तो आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि केन्द्रीय सरकार से सरकार अनुरोध करे कि मेरे हल्के को भी एन०सी०आर० में लायें या फिर जो करनाल का फ्लोर रेट है उसको बढ़ाया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करूंगी कि वे सैनिट्री नैपकिंस को वैट फ्री करने जा रहे हैं और उसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ वैट फ्री करने से काम चलने वाला नहीं है। गांव में जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वे इनको खरीद नहीं सकती हैं उनको ये फ्री में उपलब्ध कराए जाएं। डी०आर०डी०ए० के पास ऐसी बहुत सी स्कीम्ज के लिए पैसे होते हैं। इसके अलावा जो एन०जी०ओज गांवों में काम कर रहे हैं उनको भी इस काम में लगाया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करूंगी कि महिलाओं के लिए रजिस्ट्री में पहले से ही दो परसेंट की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी हुई थी, जिसे अब वर्ष 2008-09 के बजट में उसमें एक प्रतिशत का और इजाफा कर दिया है, सरकार ने यह बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी के नाम प्रोपर्टी करे तो जो गिफ्ट डीड है क्या उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी में माफी है। देखने में ऐसा भी आया है कि कुछ प्रोपर्टी डीलर्ज स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के चक्कर में महिलाओं के नाम पर प्रोपर्टी खरीदने और बेचने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आपने जो ऐक्साइज पॉलिसी लागू की है वह भी बहुत अच्छी है। गांव में भी ठेके खुल रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों और स्कूलों के आस पास ठेके न खुलें इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हरियाणा में ठेके खुलने का कोई समय नहीं है। मैं निवेदन करूंगी कि दिल्ली प्रदेश की तर्ज पर जैसे दिल्ली में सुबह दस बजे से रात 9 बजे तक ठेके खुलते हैं ऐसे ही हरियाणा में इनका समय निश्चित किया जाए। इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूँगी कि हरियाणा में बहुत ही कम वर्किंग विमैन होस्टल हैं और उनकी स्थिति आज अच्छी नहीं है। उनकी स्थिति भी ठीक कराई जाए। मैं अपनी सरकार से यह भी निवेदन करूंगी कि संविधान के 73-74 वें संशोधन में 11वें, 12वें शिड्यूल में जो सब्जैक्ट हैं उन्हें पंचायतों को देना चाहिए। महिलाओं को इम्पॉवरमैंट देने का राजीव गांधी जी का सपना था इसलिए उन्होंने 33 परसेंट महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा था और उसी के तहत सरपंच, पंच, जिला परिषद् के अध्यक्ष, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष महिलाओं को बनाया गया लेकिन जब हम यह देखते हैं कि मीटिंग्स में उनकी जगह उनके पति, उनके लड़के जाते हैं तो यह अच्छा नहीं लगता है।

[श्रीमती सुमिता सिंह]
मुख्यमंत्री जी, कृपा करके यह सुनिश्चित करें कि उनकी मीटिंग्स में उनके पतियों को या उनके लड़कों को न जाने दिया जाए।

श्री सभापति : आप उन महिलाओं को इस बारे में बोलें कि वे अपने साथ उनको मीटिंग्ज में लेकर न जाएं।

श्रीमती सुमिता सिंह : इसके लिए आप ऑफिसर्ज को हिदायत दें कि मीटिंग्ज में यदि इनका लड़का या इनके पति आएं तो उनको उन मीटिंग्ज में न आने दिया जाए। यदि फिर भी आएं तो उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए। महिला सशक्तीकरण के बारे में मैं यह भी कहना चाहूँगी कि गांव के अन्दर पुलिस स्टेशनों में महिला कांस्टेबल्ज, महिला नम्बरदार, महिला पटवारी लगाने पर विचार करें। इससे गांव में महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा। महिलाओं के लिए आपने बहुत कुछ किया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगी। साथ ही यह भी कहना चाहूँगी कि हमारे जो गांव की लड़कियां या बहनें गांव से शहर कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने आती हैं उन्हें जो भी ऑटो-रिक्शा मिले उसमें फंस कर बैठकर 20-25 किलोमीटर तक शहरों में जाना पड़ता है। इसके लिए जो हमारी सरकारी बसें हैं उनका टाईम इस हिसाब से फिक्स किया जाये कि जब लड़कियां स्कूल या कॉलेज में जाने के लिए गांव से शहर आती हैं और शहर से पढ़ने के बाद वापिस गांव जाती हैं उस समय पर जो बसें लगाई जाएं उनमें लड़कियों के बैठने की सीटों की संख्या बढ़ाई जाये। मैं माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को और वित्त मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने वर्ष 2008-09 का शानदार बजट प्रस्तुत किया है। जब से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश की सत्ता संभाली है तब से प्रदेश में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। प्रदेश का हर वर्ग खुश है, चारों तरफ खुशी का वातावरण है। सरकार से हर वर्ग चाहे वह नौजवान हो चाहे किसान हो सब खुश हैं।

श्री सभापति : मैडम, आप वाईड-अप कीजिए।

श्रीमती सुमिता सिंह : पिछले तीन सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकास के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य हरियाणा प्रदेश को हर क्षेत्र में नम्बर एक बनाना है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र चौधरी (पटौदी, अनुसूचित जाति) : चेयरमैन साहब, 18 मार्च, 2008 को वित्त मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने एक ऐतिहासिक बजट सदन में प्रस्तुत किया उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। यह सरकार का चौथा बजट है और मैं वित्त मंत्री जी को मुबारिकबाद देता हूँ कि लगातार चौथा बजट पेश करते हुए भी उन्होंने हरियाणा की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया बल्कि गृह कर, चूल्हा टैक्स इत्यादि अनेक कर माफ करके एक सराहनीय काम किया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत के वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम जी को जिनके द्वारा समस्त देश के छोटे और सीमान्त किसानों के ऋण माफ करके एक अभूतपूर्व साहसिक काम किया गया है। जिसमें हरियाणा के किसानों को भी काफी लाभ पहुँचेगा। इस बजट में कृषि क्षेत्र, शिक्षा, समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर बल देना व बिजली का उचित प्रबन्ध करना और सुदृढ़ आधारभूत ढांचा तैयार करना सरकार की विशेष प्राथमिकताएं रही हैं। वर्ष 2008-09 की वार्षिक

योजना के लिए 6650 करोड़ रुपये का आबंटन प्रस्तावित है। वर्ष 2006-07 में यह 3300 करोड़ रुपये था, वर्ष 2007-08 में यह 5300 करोड़ रुपये था और इसमें पिछले वर्ष से तकरीबन 26 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी हुई है और जब से हमारी सरकार आई है लगतार बजट में तीन गुणा बढ़ौत्तरी हुई है। हरियाणा राज्य वित्तीय अनुशासन लाने में और एफ०आर०बी०एम० अधिनियम लागू करने में देश में अग्रणी है। एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के मुताबिक राजस्व घाटे को वर्ष 2008-09 तक शून्य करना था, उसको भी पूरा कर लिया गया है। इससे राज्य को केन्द्र सरकार से काफी अच्छे ऋण मिलने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों की वृद्धि क्रमशः 9.4 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत है। हमें इस बात पर गर्व है कि हरियाणा में कुशल प्रशासन के कारण प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2007-08 में 56280 रुपये होने का अनुमान है जो देश में गोवा के बाद सबसे ज्यादा है। राज्य सरकार ने ऋण कम करने में भी अहम भूमिका निभाई है जो ऋण वर्ष 2003-04 में 2495.24 करोड़ रुपये था, वह अब वर्ष 2007-08 मे केवल 46.62 करोड़ रुपये रह गया है। कर-राजस्व में भी हरियाणा ने वर्ष 2006-07 में 20.37 प्रतिशत वृद्धि की है। इसके अलावा वर्ष 2008-09 में विश्वव्यापी मन्दी होने के बावजूद 16.68 प्रतिशत वृद्धि होना कुशल प्रशासन का प्रमाण है। वित्त मंत्री जी ने भूमि और सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टॉम्प शुल्क की दरें वर्ष 2004 में कम करके शहरों में 8 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 6 प्रतिशत कर दी थी। इन दरों में महिलाओं को जो 2 प्रतिशत की विशेष छूट थी उसमें एक प्रतिशत की कमी और की है जिससे कुशल प्रबन्धन की छवि उभरकर सामने आई है। योजनागत खर्चे पिछली सरकार के शासनकाल में 2000 करोड़ थे और ये तीन वर्षों में 3 गुना से भी अधिक बढ़ गए हैं। वित्त मंत्री जी का अनुमान है कि बिजली पर 867 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगें क्योंकि सरकार बिजली के मामले में बहुत गम्भीर है। बिजली वितरण में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। जिसमें उच्च वोल्टेज प्रणाली शुरू करने, कंडक्टर क्षमता को बढ़ाने जैसे अनेक कार्य प्रगति पर हैं। गत 3 वर्षों में 68 नए सब-स्टेशन स्थापित किए गए। 182 सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई। 37386 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये गए और 1138 किलोमीटर लम्बी नई सम्प्रेषण लाइनें बिछाई गई। सरकार ने सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई पहल की है। यमुनानगर में 300 मेगावाट, खेदड़ में 1200 मेगावाट व जिला झज्जर में 1500 मेगावाट के थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं जिससे पता चलता है कि सरकार बिजली के मामले में बहुत गम्भीर है।

सिंचाई क्षेत्र में कार्य करना भी सरकार की प्राथमिकता है। इन्होंने पानी का समान बंटवारा करके अपना चुनावी वायदा पूरा किया और इस बजट में सिंचाई पर 2007-08 में 790 करोड़ खर्च करने का अनुमान है। हांसी-बुटाना-लिंक नहर बनवाने जैसे कार्य प्रगति पर हैं और कुछ फीडरों की क्षमता बढ़ाने में भी सरकार गम्भीर है ताकि किसान को सिंचाई के लिए पानी के लिए तरसना न पड़े और प्रदेश खुशहाल हो।

गांवों में स्वच्छ जल पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार ने 2007-08 के बजट में 653 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को निःशुल्क पेयजल कनैक्शन दिए जा रहे हैं। 2007-08 में इस योजना के तहत 3.30 लाख परिवारों को कनैक्शन, 200 लीटर की टंकी व टूंटी मुफ्त देने

[श्री भूपेन्द्र चौधरी]

का प्रावधान है ताकि गरीब आदमी स्वच्छ पानी का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा 2008 तक 290 नलकूप लगाने का कार्य पूरा किया जायेगा जिससे 503 गांव लाभान्वित होंगे।

सड़कें एवं परिवहन क्षेत्र के लिए 766 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है क्योंकि सरकार यह सोचती है कि बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। वर्ष 2007-08 में 3200 किलोमीटर लम्बी सड़कों को सुधारा गया है। वर्ष 2008-09 में 4500 किलोमीटर सड़कों को सुधारा जाना प्रस्तावित है। इसी तरह 37 सड़क उपरिगामी (ROB) पुल बनाने का प्रस्ताव है जिनमें से 18 पुल निर्माणाधीन हैं। 2008-09 में 175 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 2008-09 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 880 किलोमीटर लम्बी सड़कों के सुधार पर 400 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है।

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास शहरी क्षेत्र की तर्ज पर करने के लिए सरकार वचनबद्ध है और इस पर भी सरकार काफी गम्भीर है। पिछले वर्ष इस पर 175 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के लिए सरकार ने 640 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान इस बजट में रखा है जो कि सरकार का सराहनीय कदम है। समाज के कमजोर वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार काफी गम्भीर है और इस बजट में इस समुदाय के कल्याण के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि सराहनीय कार्य है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए भी सरकार ने काफी स्कीम्ज चलाई हैं जैसे डॉ० अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना। शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2008-09 में शिक्षा के लिए 3139.08 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जो कि पिछले बजट से 14 प्रतिशत अधिक है। पहली से आठवीं कक्षा तक मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और वर्कबुक सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं और इस तरह की काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्कूलों को एजूसैट प्रणाली से जोड़ा गया है ताकि शिक्षा का स्तर ऊपर उठ सके।

खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक गांवों में ग्रामीण खेल स्टेडियम का भी निर्माण करवाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास के लिए भी इस बजट में 172 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों के विकास और उनके स्तर में सुधार के लिए अनेक योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं जिनमें लाडली योजना प्रमुख है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बजट में 164 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार लोगों को उच्चकोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयत्नशील है।

वर्ष 2008-09 में उद्योगों के लिए योजनागत तथा योजनेतर 231.52 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है जो पिछले वर्ष के मुकाबले तीन गुना है। सरकार औद्योगिकरण के लिए काफी पक्षधर है और जब से सरकार बनी है 3300 करोड़ रुपये के अभूतपूर्व निवेश हुए हैं और 66000 करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाएं विचाराधीन है। विशेष आर्थिक जोन की स्थापना से चार लाख लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। इनके अलावा भी काफी स्कीम्ज सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं जिनका बजट में खास ख्याल रखा गया है और मैं समझता हूँ कि यह बजट हर तरह से एक साफ बजट है। सभापति महोदय, बजट का समर्थन करने के साथ-साथ मैं सरकार

को कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा कि पिछले दिनों दिल्ली में स्पीड ट्रायल के बारे में मीटिंग हुई थी जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री जी०के० बालाकृष्णन भी मौजूद थे। उन्होंने उस मीटिंग में न्याय मिलने में देरी के लिए और लाखों केस कोर्ट में इकट्ठे होने के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा यदि अधिकारी सही, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्णय समय पर लें तो नागरिकों को मुकदमें लड़ने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि यह बात पूरी तरह सच है कि सरकार सबसे बड़ी मुकदमेंबाज हो गई है। आधे से अधिक मामलों में सरकार प्रतिवादी हैं। अधिकारियों के एकतरफा एवं गलत फैसलों के कारण लोग न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। कार्यपालिका मामले को लटकाने तथा अदालतों को गुमराह करने के भी हथकन्डे अपनाती हैं। न्यायालयों के आदेशों की अनुपालना नहीं होती और दोषी अधिकारियों को दण्डित नहीं किया जाता। सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चाहूँगा कि दो तीन विधायकों की एक कमेटी रिटायर्ड सैशन जज के साथ बनाई जाये जो इस तरह के केसिज को देखे। इसी तरह के दो तीन केसिज के बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि गुड़गांव के अंदर 1987 में किसी को एक प्लॉट अलाट हुआ था लेकिन उसको आज तक पोजैशन नहीं मिला है। वह आदमी सुप्रीम कोर्ट तक गया और दोषी अधिकारियों को सजा हुई लेकिन वे दोषी अधिकारी आज के दिन भी प्राईम पोस्टिंग पर लगे हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के जो दोषी अधिकारी हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाये और उनके खिलाफ प्रौपर कार्यवाही की जाये।

श्री सभापति : भूपेन्द्र जी, आप इस केस के बारे में संबंधित मंत्री को लिखकर भिजवा देना।

श्री भूपेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, अब मैं सड़कों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं वे सड़कें तीन महीने में टूट जाती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी सड़कें बननी हैं जिनके टैण्डर दो-दो साल से पैण्डिंग हैं जिसके कारण सरकार की छवि भी खराब हो रही है इसलिए जल्दी से जल्दी टैण्डर करवाकर ये सड़कें बनवाई जायें और सड़कों की रिपेयर का काम भी करवाया जाये। सभापति महोदय, मेरे हल्के पटौदी के अंदर कुछ गांवों में खारा पानी है जिसको जानवर भी नहीं पी सकते। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे हल्के के जिन गांवों में खारा पानी है उन गांवों की लिस्ट बनाई जाये और उनमें पीने के लिए मीठा पानी की व्यवस्था की जाये ताकि लोगों और पशुओं को पीने का अच्छा पानी मिल सके। सभापति महोदय, अन्त में मैं आपका धन्यवाद करते हुए बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : चेयरमैन साहब, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो वर्ष 2008-09 का बजट हरियाणा विधान सभा में प्रस्तुत किया है मैं इसके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने हरियाणा की सत्ता की बागडोर सम्भालते ही यह घोषणा की थी कि हम हरियाणा को नम्बर एक प्रदेश बनायेंगे। आज हमें इस बात की खुशी है कि आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अपनी घोषणा की तरफ पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अग्रसर हैं। यह हमारे इस वर्तमान बजट से ही पता चल रहा है। इस बजट में हर प्रकार से हर वर्ग के लोगों को पूरा-पूरा फायदा देने की पूरी कोशिश की गई है और मैं समझता हूँ कि जैसा बजट हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री की सलाह

[श्री अमीर चन्द मक्कड़]

से माननीय वित्त मंत्री द्वारा हरियाणा की विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है ऐसा बजट देश के किसी भी प्रदेश द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। यह बजट हर दृष्टि से काबिले तारीफ बजट है। इस बजट में कितने ही विकास कार्यों के लिए कितना बड़ा धन जुटाया गया है और विकास कार्यों के लिए जो धन बजट में रखा जाता है उसे हर साल बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ-साथ पूरे प्रदेश में विकास के कार्य भी बड़ी तेजी से चल रहे हैं। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे पीने के पानी का क्षेत्र हो, चाहे इरीगेशन का क्षेत्र हो और चाहे खेलों का क्षेत्र हो, हर प्रकार से हर तरफ जहां भी देखा जाये वहां विकास के कार्य चल रहे हैं। गांवों में जो जलापूर्ति के लिए इतना बड़ा प्रावधान बजट में किया गया है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। इस सम्बन्ध में मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि जहां सरकार द्वारा सारे हरियाणा में हर आदमी को पीने के लिए पूरा साफ और स्वच्छ पानी देने की घोषणा की जा रही है और उसकी तरफ वह सरकार पूरी तरह से अग्रसर भी है मैं चाहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हांसी में भी पीने के पानी की समस्या की ओर ध्यान दिया जाये। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते समय भी एक मांग की थी कि हांसी में एक दूसरा वाटर वर्क्स बनाया जाये ताकि हांसी के लोगों को भी पीने के पानी की कोई कमी न रहे और उनको भी पीने का पूरा पानी मिले। जिस प्रकार से सरकार ने गांवों में हरिजन बस्तियों में हरिजन परिवारों को पानी का कनैक्शन और पानी की टंकी मुफ्त दी है वह काबिले तारीफ है। इसी प्रकार से मेरे इलाके में भी 2-3 ऐसे हरिजन गांव हैं जिनमें पीने के पानी की बहुत कमी है उनमें से हजमपुर, खरखड़ा, जीतपुरा प्रमुख हैं। इन गांवों में पीने के पानी की बहुत कमी है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इस कमी को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाये जायें और इन गांवों के लिए एक अलग से नया वाटर वर्क्स स्थापित किया जाये। इसी प्रकार से मेरी कांस्टीच्युएंसी में 5 ढाणियां ऐसी हैं जिनमें पीने के की बहुत कमी है। इन ढाणियों के नाम हैं—ढाणी राजू, ढाणी गुजराल, ढाणी ठाकरी, ढाणी फुरिया, ढाणी सांकरी इनके लिए भी वाटर वर्क्स नहीं है। वहां पर भी एक वाटर वर्क्स स्थापित करने की सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा ताकि उन लोगों को भी पीने का साफ और स्वच्छ पानी मिल सके। वहां पर भूमिगत पानी खारा है। वहां पर पानी सप्लाई के लिए अगर कोई ट्यूबवैल लगाया जाता है तो साल दो साल बाद ही वह पानी खारा हो जाता है और वह पानी पीने लायक नहीं रह जाता। इस बारे में भी मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसके लिए भी जल्दी से जल्दी कोई वाटर वर्क्स स्थापित किया जाये। इसी प्रकार से सड़कों के विकास की बात है। सड़कों का बहुत बड़ा विकास हो रहा है और सड़कों के विकास पर करोड़ों रुपये खर्च करने का प्रावधान सरकार द्वारा इस बजट में किया गया है, इसके लिए सरकार की जितनी तारीफ की जाये वह कम है। इस बजट में सरकार ने 45 हजार किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण का प्रावधान किया है। मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे हल्के में ऐसी सड़कें हैं जो बिल्कुल कच्ची हैं। इससे पहले भी मैंने उनका नाम लिखवाया था। उन्हें पक्का किया जाना बहुत जरूरी है। इनमें ढाणी तेजामोड़ी की जो सड़क है जिसको बनाने की घोषणा माननीय मंत्री जी भी करके आये थे। इन्हीं सड़कों के लिए मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि कोशिश करके ये सड़कें जरूर बनाई जायें ताकि लोगों को कच्चे रास्ते से होने वाली परेशानी दूर हो सके। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे हरियाणा प्रदेश का जितना विकास कर रहे हैं उसकी जितनी तारीफ की जाये वह कम होगी। मैं चाहूँगा कि मेरे हल्के में भी आपको ध्यान देना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हांसी भी शहीदों और देशभक्तों का शहर है और आप स्वयं एक देशभक्त

परिवार से सम्बन्ध रखते हैं और शहीदों एवं देशभक्तों का पूरा आदर करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि हांसी के ऊपर भी आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। जहां सड़क पर शहीदों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी कि उस सड़क का रंग लाल हो गया था और इसी से उस सड़क का नाम लाल सड़क के नाम से मशहूर हो गया।

13.00 बजे

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : मक्कड़ साहब, आपका भी ध्यान रखेंगे और हांसी का भी ध्यान रखा जायेगा।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : सभापति महोदय, शहरी विकास और ग्रामीण विकास के लिए भी सरकार काफी कोशिश कर रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि हांसी शहर के विकास के लिए भी जरूर कोई न कोई फण्ड का प्रावधान किया जाये। गांवों के विकास के बारे में मेरा कहना है कि मेरे हल्के के गांव अभी थोड़ा-सा पीछे चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 10-10 लाख रुपये बहुत से गांवों को दिये भी हैं लेकिन अभी बहुत से गांवों की गलियों आदि का काम बाकी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कि कम से कम 50 करोड़ रुपये की घोषणा हमारे गांवों के कार्यों के लिए जरूर करें। हांसी शहर के लिए भी सड़कें बनाई जानी चाहिएं। शिक्षा के बारे में बहुत बड़ा ब्यान हरियाणा सरकार दे रही है। महिलाओं की शिक्षा, गरीब बच्चों की शिक्षा और हरिजन-बैकवर्ड बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन देकर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि हरियाणा के सभी लोग शिक्षित हो जाएं। इससे देश तरक्की करेगा और शिक्षा का विस्तार होगा और एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। कुछ बच्चे जो स्कूल छोड़ जाते थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वजीफे की घोषणा की है ताकि गरीब बच्चे भी शिक्षा से वंचित न रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हांसी शहर में कॉलेज को बढ़ाने का काम किया है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ लेकिन अगर बी०एड० और जे०बी०टी० की क्लासिज खोलने की भी मंजूरी प्रदान की जाये तो बहुत मेहरबानी होगी जिससे मेरे हलके की लड़कियाँ वहीं पर रह कर अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगी और उनको पढ़ने के लिए हिसार, भिवानी आदि शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। कृषि के विकास के बारे में मेरा कहना है कि कृषि के विकास के लिए सरकार इतने बड़े काम कर रही है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कितने बड़े प्रोत्साहन दे रही है, कर्ज माफी की घोषणा कर रही है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। केन्द्रीय सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये के किसानों के कर्ज माफ करके किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। विपक्ष के हमारे साथी पहले बहुत शोर करते थे कि कर्ज माफ करो लेकिन आज इनके पास मुखालफत करने का कोई बहाना नहीं बचा है। माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री से कह कर किसानों के ये कर्ज माफ करवाये। लेकिन ये फिर भी सदन से बाहर जाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। इनकी सरकार तो किसानों को गुमराह करने के लिए झूठे वायदे किया करती थी कि हमारी सरकार आयेगी तो बिजली के बिल माफ करेंगे लेकिन एक भी पैसा माफ नहीं किया जिसकी वजह से किसानों पर बहुत बोझ बढ़ गया। कई-कई लाख रुपये के उनके बिजली के बिल बकाया पड़े थे। यह काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। किसानों पर जो करोड़ों रुपये के बिजली के बिल बकाया थे उनको हुड्डा साहब ने एक ही कलम से माफ कर दिया।

[श्री अमीर चन्द मक्कड़]
किसानों की जमीनों के रेट भी हुड्डा साहब ने बढ़वाए ताकि किसान की जमीन का उचित रेट उसको मिले और वह अपना गुजारा ठीक ढंग से चला सके। जिस देश का किसान खुशहाल होगा वही देश तरक्की कर सकता है।

श्री सभापति : मक्कड़ साहब आप वाइंड-अप करें।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : इसके साथ ही साथ खेलों के बारे में भी सरकार इतना बड़ा प्रोत्साहन दे रही है, जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। खेलने वाले नौजवानों को खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने चाहिएं। सभापति महोदय, मैं यह चाहूँगा कि हांसी हल्के में भी खेलने के लिए एक बहुत बड़ा खेल मैदान होना चाहिए। हांसी के बारे में मैंने पहले भी प्रार्थना की थी कि मेरे हांसी शहर में कोई पार्क नहीं है। इतना बड़ा शहर होने के बावजूद वहां कोई पार्क नहीं है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वहां पर पार्क बनवाया जाए। वहां से 40 लाख रुपये के लगभग का ऐस्टिमेट बन कर आया हुआ है वह भी पास करवा कर भिजवाएं ताकि हांसी के लोगों को भी पार्क की सुविधा मिल सके। हांसी में शहीदों का एक पार्क है।

श्री सभापति : मक्कड़ साहब, यह बात आपने गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए कह दी थी अगर और कोई नई बात हो तो वह आप बता दें।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : सभापति महोदय, अंग्रेजों के समय में यहां पर बहुत से नौजवान शहीद हुए थे और उस समय मुसलमानों को जलाया गया था और हिन्दुओं को दफनाया गया था। हांसी में जो पार्क है उस पार्क की हालत बहुत ही बुरी है। सी०एम० साहब ने खुद उस पार्क की हालत को देखा है। सरकार से मेरी विनती है कि उस पार्क की हालत ठीक करने की कृपा करें। (विघ्न) सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी तथा माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया बजट प्रदेश को दिया है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : सभापति महोदय, जो बजट पेश किया गया है माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी समझदारी से यह बजट पेश किया है। माननीय फाईनैंस मिनिस्टर बहुत ही काबिल मिनिस्टर हैं। लेकिन कई बातें हैं जो कुछ पहले की हैं और कुछ बाद की हैं, कुछ कमियां पेशियां हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले छः दिनों से हाउस से गैरहाजिर था। 16 तारीख को रैली की वजह से मैं हाउस से गैरहाजिर था इसलिए मैं महामहिम गवर्नर के ऐड्रैस पर नहीं बोल पाया। अध्यक्ष महोदय, अभी एक भाई यहां पर जिक्र कर रहे थे लेकिन वे इस समय हाउस में नहीं है। उन्होंने कहा कि "दो साल के बाद यह जो आपका बजट है वह हमने ही पेश करना है।" देहात में एक मिसाल दिया करते हैं। * * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : गौतम जी ने जो यह बात कही है वह कार्यवाही से निकाल दी जाए।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, कई भाई बिना मतलब के सपने लेते थे। चौटाला जी तो आज भी हाउस में नहीं हैं जबकि उनको हाउस में होना चाहिए था क्योंकि वे विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता हैं। चौधरी भजन लाल जी और उन दोनों ने मिल कर 9 एम०एल०एज० बना लिये थे तो अब उनको हाउस को फेस करना चाहिए। स्पीकर सर, चौटाला जी का तो एक ही लक्ष्य था और वह था दुनियां का सबसे अमीर आदमी बनना। (विघ्न) उनकी एक ही नीति रही है जात-पात का जहर घोलना। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इस भाई से कहूँगा कि मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ ठीक बात ही कहूँगा कि वे इनकी पार्टी को छोड़ कर अगर इनकी सूट लगे तो हुड्डा साहब वाली पार्टी में रल लें या फिर हमारी वाली पार्टी में रल लें, क्यों ख्वाहमख्वाह दु:खी हो रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी सीट पर बैठें। चिड़ाना साहब, अगर आपने कोई बात बोलनी है तो आप प्वायंट ऑफ ऑर्डर लेकर खड़े हों। बिना परमिशन के बोलना ठीक नहीं है। आपके मैम्बर करीब डेढ़ घण्टा बोल कर चले गए लेकिन किसी ने उनको बीच में कुछ नहीं कहा। (विघ्न) गौतम साहब, आप अपनी बात कहें।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, न ही कोई नाजायज बात कहते हैं और न ही हम गलत बात बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस देश की यह बदकिस्मती है कि यहां पर कोई कायदा कानून नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यहां तो एक फार्मूला है कि जात-पात का जहर फैलाओ और भोले भाले गरीब आदमियों को जात-पात में बांट करके इस धरती से सारा माल और धन लूट लो। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला ने पॉलिटीकल पार्टी बनाई और उसका नाम इनैलो (इण्डियन नेशनल लोक दल) रख दिया। न इण्डियन, न नेशनल और न ही लोक दल है। (शोर एवं व्यवधान) बाबू और दो बेटे 2-2 क्विंटल के, वे केवल लूटपाट करना, जात-पात का जहर घोलना और बूथ कैप्चर करना जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान) जो भाई आज उसकी पार्टी में हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि उनका काम बूथ कैप्चर करना है और गरीबों पर जुल्म करना है। यह उनका मेन धन्धा है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां पर बात करते हुए शर्म आती है और अफसोस होता है। अध्यक्ष महोदय, ये जो भाई हैं ये बहुत काबिल हैं, इतने बढ़िया लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, वह 10,000 गरीब लोगों का बैकलॉग छोड़ गया है। अध्यक्ष महोदय, जब 1991 में मण्डल कमीशन की रिपोर्ट छपी थी तो उसने सारे हरियाणा में आग लगवा दी थी और सोनीपत का डिपो फूंका था। किसी गरीब, नाई, तेली, धोबी और छिप्पी के बालक को नौकरी न मिल जाए इसलिए गुरनाम सिंह कमीशन बना दिया था। अध्यक्ष महोदय, 11 बड़ी-बड़ी जातियां जिसमें राजपूत भी बैकवर्ड, जाट भी बैकवर्ड यहां तक कि हमारे वाले गौड़ भाई भी यूं बोले कि हम गौड़ ब्राह्मण भाई जाटों के गल्लै हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, रिजर्वेशन के लिए सुप्रीमकोर्ट में केस कर दिया था। इस पार्टी में गरीब वर्ग के भाई 36 बिरादरी का गला कटवाने के लिए एम०एल०ए० बनने के लिए शामिल हो जाएं तो मुझे इन भाईयों पर तरस आता है। ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कौन-सी पार्टी किस बात की पार्टी। अध्यक्ष महोदय, यह तो गिरोह है। (शोर एवं व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, हमारे बुजुर्गों को आज भी खूब याद है और आप भी उसी एज ग्रुप में हो। अध्यक्ष महोदय, पैप्सू के समय में गिरोह घूमा करते थे। (शोर एवं व्यवधान) कई किस्म के डाकूओं के गिरोह थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आपने इनको खुली छूट दे रखी है। ये जो चाहें वही बोले जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, यह बजट पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान) अगर इनको इतना ही शौक बोलने का है तो उधर जाकर बोलें। हमारे साथ क्यों बैठे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप जानबूझकर इनसे ऐसी बात करवा रहे हैं। इनका यह कोई तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यह बजट पर बोलें। अगर ये इस तरह से करेंगे तो हम हाउस को नहीं चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये भूमिका तैयार कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने इन भाईयों को कहना चाहूँगा कि मैं बजट पर पूरी तैयारी करके आया हूँ। (शोर एवं व्यवधान) मैं गवर्नर एड्रैस पर नहीं बोला था अब बजट पर बोल रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, पैप्सू के समय में गिरोह हुआ करते थे। उन्होंने ऊंटों पर बन्दूकें लगाई होती थी और बनियों में बैठ जाया करते थे। कोई भी शरीफ आदमी गांव से क्रास नहीं कर सकता था। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह वही गिरोह है। (शोर एवं व्यवधान)

सदस्य का नाम लेना

श्री बलवन्त सिंह : * * * * । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : * * * * । (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : * * * * । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये जो कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) Balwant Singh Ji, please take your seat. (Noise and Interruptions). Dr. Sahib, please take your seat. (Interruptions) Mr. Sadhaura, please take your seat. (Noise and Interruptions)

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर सर, * * * * *

Mr. Speaker : Mr. Sadhaura, I warn you. (Noise and Interruptions) अगर आपका एक साथी डेढ़ घंटा बोलकर चला गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप फ्री हैन्ड हैं। इनकी नेशनल लैवल की पार्टी है और ये बेचारे दो आदमी जीतकर आए हैं। वे बजट पर बोल रहे हैं इसलिए आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) Mr. Sadhaura, I warn you, please sit down.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Shri Balwant Singh : * * * * * * *

Mr. Speaker : Balwant Singh Ji, I warn you.

Shri Balwant Singh : * * * * * * (Noise and Interruptions).

Mr. Speaker : Balwant Singh Ji, please take your seat otherwise, I have to name you.

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर सर, * * * * *

Mr. Speaker : Balwant Singh, I name you. You may please leave the House.

(At this stage Shri Balwant Singh withdrew from the House)

वाक-आऊट

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ ये मेरे भाई हैं ये गलत रास्ते पर चले गए हैं। स्पीकर सर, ये मेरे भाई हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, * * * * * *

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, ये हमारे भाई हैं मुझे इनसे कोई गिला नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) मुझे इनसे कोई तकलीफ नहीं है। They are my younger brothers.

डॉ० सुशील इन्दौरा: स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या प्वायंट ऑफ ऑर्डर है? (शोर एवं व्यवधान) मि० चिढ़ाना, आपका एक साथी बोलने के लिए खड़ा है और आप अपनी सीट पर नहीं हैं। आपको पार्टी का कोई नोर्म तो होगा, आपका कोई सलीका तो होगा, कोई लिहाज तो होगी। आप बैठें।

डॉ० सुशील इन्दौरा: सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर यह है कि हमारे ये साथी बजट पर बोलते हुए बेवजह की बात कर रहे हैं और बेवजह हमारे एक साथी को नेम करके बाहर निकाला गया है। हम इसके विरोध में सदन से वाक-आऊट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, मैंने उनको पहले चार बार और फिर तीन बार वार्न किया था। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सभी माननीय सदस्यगण सदन से वाक-आऊट कर गए।)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, मुझे इनसे कोई गिला नहीं है। पुराने समय में खास तौर से देहात में ऐसा रिवाज था कि एक बार एक भाई, भाई तो क्या कहूं एक बुजुर्ग आदमी थे और मैं तो उस समय नौजवान बच्चा था।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : आप पैप्सू के समय की बात बताएं।

श्री राम कुमार गौतम : पैप्सू के समय की बात तो मैं सुना चुका हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ। स्पीकर सर, उस समय कुछ गिरोह होते थे वे ऊंटों पर बंदूक लाते थे, लूटपाट करते थे और कभी वे बनियों में खड़े हो जाते थे तथा वे कभी किसी जगह पर डाका डालते थे कभी किसी जगह पर डाका डालते थे, बहुत भारी आतंक का माहौल उस समय था। पैप्सू के समय में सैंटर की सरकार में एक मि० राव थे उनको ऐडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा था और उसके बाद ही ये डाकू मारे गए थे। स्पीकर सर, ये भी असलियत में डाकूओं का गिरोह ही है। स्पीकर सर, आप देखिए कि ये भाई वैसे ही चिल्ला रहे थे। इन्होंने तो नरेश शर्मा की लाश बना दी और नालियों में उसको मरा समझकर गिराकर चले गए। रामचन्द्र जांगड़ा को ये नंगा करके कत्ल कर रहे थे। उस समय किसी ने कहा कि फाईनल ऑर्डर पूछ लो उसके बाद ही उस बेचारे की जान बची। इसी तरह से अमीर सिंह हत्याकांड हुआ। स्पीकर सर, ये तो दोस्त को ही सबसे पहले मारते हैं दुश्मन तो इनके बस का नहीं है। दोस्ती करके खंजर घोंपना इनकी आदत में है। स्पीकर सर, अमीर सिंह चौधरी देवीलाल को अपने पिता से ज्यादा मानते थे लेकिन इन्होंने एक इलैक्शन पोस्टपोन करवाने के लिए उसकी हत्या करवा दी जबकि बापू बेटा दोनों एक घंटा पहले ही ये उसके यहां हलूवा-मंडा खाकर आए थे। बाद में उसकी लाश मुंढाल में मिली। इस देश में कोई कानून है नहीं। मुख्यमंत्री जी, आप भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। इनेलो वाले इस लायक ही नहीं हैं। पहले दिन जिस दिन आए थे, सैशन शुरू हुआ था उसी दिन इनका काम कर देना चाहिए था। इनकी जमीन जायदाद का सबको पता है। यह भी सबको पता है कि ये डाकू हैं। इन तीनों बापू बेटों को जेल में डाल देना चाहिए था। चलो खैर! दोस्ती करके धोखा देना तो इनके खून में है। हमारे साथ समझौता किया और उसके बाद हमारी पीठ में खंजर घौंप दिया। उसके बाद उन किसान भाइयों की पीठ में खंजर घौंपा जिन्होंने सारी जिन्दगी चौधरी देवी लाल जी को अपना माई बाप माना और उनके ऐसे बेटे जिसकी शक्ल देख लो तो रोटी अच्छी नहीं लगती उसको भी उन्होंने अपना नेता माना। कहां ये हमारे मार्शल हैं और कहां ये तैमूर लंग। कितनी बदकिस्मती की बात है। एक बार जब आदमी किसी के साथ दोस्ती में धोखा खा जाता है फिर भी वह दोबारा उसके साथ हो, ऐसा नहीं होता। उसमें इंसानियत होगी तो उसके घर भी नहीं जाएगा। हमारे किसी बड़े नेता की कुतिया को जुकाम हो जाए तो ये वहां उसका इलाज करने के लिए पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी नस्ल की कुतिया मेरे पास थी इसलिए इसका इलाज मैं करूंगा। हमारे एक नेता का जन्मदिन था और जब मैं वहां पहुँचा तो देखा कि खोपर वाला पहले से ही वहां बैठा पाया। जब हम आ लिए उसके बाद भी वहीं बैठा रहा। अगर इतना ही बी०जे०पी० से प्रेम था तो पीठ में खंजर घोंपने की क्या जरूरत थी। अब उसको अपने मारे हुए डाके याद आते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान! एक बार फिर इनकी बुद्धि मलिन कर दे। कभी आडवाणी जी के पास जाता है, कभी राजनाथ जी के पास जाता है। वाजपेयी जी का नाम लेकर कहता

है कि मैं तो इनका बेटा हूँ। इनका जाम्या हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, समझौता कोई असल का बीज होगा वह तो करेगा नहीं, नकली चाहे सौ बार करो। जो असल का बीज होगा वह दोबारा इस बात में धोखा नहीं खायेगा। अब मैं थोड़ा-सा जिक्र उन भाइयों का कर रहा हूँ। 1991 में कांग्रेस की हुकूमत थी उस समय हमारे जो बैकवर्ड क्लास के भाई थे, उन एस०सी०बी०सी० के भाइयों ने सारी जिंदगी कांग्रेस को अपना खून दिया। एक भी वोट एस०सी०बी०सी० के भाइयों का पाड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। जिस कांस्टीच्यूएंसी से आपके चीफ मिनिस्टर थे वहां लगभग 32 हजार वोट आपके बी०सी० भाइयों के हैं। जिनमें से 16 हजार के करीब अकेले कुम्हार भाई हैं। 1991 में मंडल कमीशन सारे देश में लागू हुआ। सारी सैंट्रल सर्विसेज में और सारी स्टेट सर्विसेज में जिन लोगों का खून पी के एम०एल०ए० बने, चीफ मिनिस्टर बने, उनका उन्होंने गला काट दिया। 1991 में मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की। 1995 में जब लोगों ने कहा कि चौधरी साहब क्या कर रहे हो। यह जो हरियाणा की नम्बर एक कौम जाट है यह तेरी कांस्टीच्यूएंसी में तेरे खिलाफ है अगर ये वोट बैंक तेरे खिलाफ हो गये तो तेरा नाश हो जायेगा और तू एम०एल०ए० नहीं बनेगा दोबारा से। मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो फौरन। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1995 में मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। उसमें दो कैटेगरी बनाई गई एक तो 16 बी०सी० 'ए' की और दूसरी बी०सी०बी० 11 की। जो ये दो कैटेगरीज बनाई गई 16 और 11 की उसमें केवल निचले दर्जे की नौकरियों में क्लास-III और क्लास-IV के लिए मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई। लेकिन क्लास-I और क्लास-II के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों में यह रिपोर्ट लागू नहीं की। इन्होंने तो सारा जीवन अपना खून पिलाया और इन्होंने तो उन बेचारों का बीज ही मार दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि इस चलते सैशन में क्योंकि सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है वर्ष 1995 से लेकर आज तक बी०सी० 'ए' को क्या मिला क्या कोई एक भी आफिसर उनका सरकारी नौकरी में लगा या नहीं यह सरकार बताये यानि 10 प्रतिशत नौकरी जो बी०सी० के नाम से पुरानी चली आ रही थी उनमें पांच जातियां बी०सी 'बी' की और डाल दी गई। उस समय बी०सी० 'ए' का एक भी एम०एल०ए० नहीं था जबकि वह अपने आप को नॉन जाट का नेता कहता था। अगर नॉन जाट का नेता था और नॉन जाट से प्यार करता था तो यह 27 प्रतिशत सरकारी नौकरियां सारी ही उन नॉन जाट के लोगों की थी और ये उन लोगों की थी जिन्होंने सारा जीवन उनको अपना खून पिलाया लेकिन उनके लिए उसको थोड़ी-सी भी मोहब्बत नहीं थी वह सिर्फ अपनी बिरादरी को प्यार करता था और सब से नफरत करता था। 10 प्रतिशत नौकरी उन जातियों के लिए आरक्षित थी उनके लिए मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करता। अगर बैकवर्ड लोगों का हितैषी बनता तो बी०सी 'ए' कैटेगरी के लिए दस की दस सीट यूं की यूं कंवारी छोड़ देता इन दस सीटों में तो कम से कम और फांसा नहीं फंसाता। दस प्रतिशत सीट में उन भाइयों को डाल दिया। फायदा था 27 प्रतिशत का और 27 प्रतिशत में से यूं के यूं क्लास-I और क्लास-II में भी बनाये लेकिन दस प्रतिशत हमारे यादव भाई हैं भगवान की मेर से 5-6 एम०एल०ए० हैं। उनमें से एक बड़ा मंत्री भी है एक छोटा मंत्री भी है उनमें से सैंटर में भी मंत्री हैं। इसी प्रकार हमारे गुर्जर भाई साधन-सम्पन्न हैं बैकवर्ड होने में मुझे कोई एतराज नहीं है। 5-6 एम०एल०ए० बना रखे हैं और ऊपर एक एम०पी० भी हैं और सैंटर में मिनिस्टर भी हैं ऊपर लॉबी थी है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेव भाइयों की बात है कांग्रेस पार्टी में अहमद पटेल है इनमें हमारे भाई एम०एल०ए० भी हैं और एक हमारे भाई डिप्टी स्पीकर भी हैं। ये पांच जातियां उसमें और डाल दी गई। अगर वह नॉन जाट का खैरख्वां था तो यूं की यूं भी करता तो

[श्री राम कुमार गौतम]

यह 16 और 11 की कैटेगरी बैकवर्ड क्लास की बनाई थी वह ऊपर भी करता और वर्ष 1991 में लागू करता। उसके बाद उन बेचारों का खेल खत्म हो गया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके खून में भी एक बात थी कि किस तरह से सारे हिन्दुस्तान में अपनी बिरादरी का नेता बन जाऊं। क्योंकि सारी दुनिया में तो बिश्नोई नहीं हैं हरियाणा में भी .66 प्रतिशत हैं जो 150 आदमियों में से एक बिश्नोई है। अपनी बिरादरी के गुरमेश बिश्नोई को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पहले मैम्बर बनाया और फिर उसे चेयरमैन बनाया। फिर नरमेश बिश्नोई को मैम्बर बनाया। लेकिन बैकवर्ड क्लास के आदमी फिर दिखाई ही नहीं दिए उनको कभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का मैम्बर नहीं बनाया। अपने आप में वह नॉन जाट का चैम्पियन कहलाता था। कोई ब्राह्मण टिकट मांगने चला गया तो कहता है कि दे तो दूं लेकिन जीतोगे नहीं। अरे, भले आदमी तेरी जहां कौम भी नहीं बसती वहां से तेरा एम०एल०ए० बेटा हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है आपकी पार्टी में एक भाई चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी और खुद भी एम०एल०ए० है।

श्री अध्यक्ष : पण्डित जी, आपको बोलते हुए 23 मिनट हो गए हैं। आपको बोलने के लिए कितना टाईम और चाहिए?

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मेरे टाईम के लिए तो मैंने यह कहा था कि अगर मुझे पहले बोलने देते, क्योंकि मलिक ने कहा कि मैं बोलना नहीं चाहता। उस वक्त अगर मुझे बुला देते तो सारी समस्या का समाधान हो जाता, मगर उस समय तो उस बेचारे का लोग जी सा लिए गये।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर बोलूंगा लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सारी जनता को बताना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, कोई ब्राह्मण टिकट मांगने चला गया तो वह कहता था कि तू जीत नहीं सकता। कोई बैकवर्ड टिकट मांगने चला गया तो वह कहता था कि तुझे टिकट कैसे दूं, बैकवर्ड जीत नहीं सकता। इसने बैकवर्ड एम०एल०ए० नहीं बनने दिया, कोई बैकवर्ड का लीडर नहीं पैदा होने दिया। ये कहता था कि मैं राजनीति का पी०एच०डी० हूँ, मैंने बड़े-बड़े सूरमा मार दिए। बाबू जगजीवन राम, चांद राम, डॉक्टर मंगल सैन, लाला बलवंत

राय तायल, पं० भगवत दयाल, चौ० रिजक राम और ठाकुर बीर सिंह भी इनके खेमे में थे लेकिन उसके साथ ज्यादा एम०एल०एज० थे, सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही उनका गला काट दिया, उनका हमेशा के लिए सफाया कर दिया। वह बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और 90 में से 85 सीट लूंगा, हमने कहा कि कहां से लेगा तो कहने लगा कि मैं नॉन जाट बिरादरी का नेता हूँ, नॉन जाट बिरादरी में जितने भी खागड़ थे मैंने सारे मार दिए। साथ ही कहता है कि पं० भगवत दयाल को मैंने मारा और उसके छोरे की पार्टी छुड़वा दी, बेचारा रोता लोकदल में चला गया। कहता है मैंने चिरंजीलाल जो करनाल से एम०पी० बनता था, उसकी भी सीट छीन ली और उसको पार्टी से निकाल दिया। मैंने हरिजनों में चौ० चांद राम और कृपाराम पुनिया को मारा और चौधरी दलबीर सिंह को भगवान ने मार दिया। फिर कहता है कि उसकी छोरी की मैंने 2 बार मुंडी रगड़ी और आज वह सिरसा से अम्बाला चली गई तब जाकर पैंडा छुड़वाया। कहता है कि बलवंतराय तायल अपने आप को सूरमा कहता था कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, फ्रीडम फाइटर हूँ। उसके बारे में ये कहता है कि मैंने उसको मारा और उसको टिकट नहीं लेने दिया। अध्यक्ष महोदय, वह कहता है कि मैं ओम प्रकाश जिंदल को मारना चाहता था लेकिन वह मेरी जफ्फी से बाहर निकल गया और फिर उसको भगवान ने मार दिया। कहता है कि बणियों में भी मैंने कोई लीडर नहीं छोड़ा। कहता है कि पंजाबियों का जो नेता था, जनसंघ का भी नेता था, डॉ० मंगल सैन, मैंने उसको धोखा देकर मारा। मैंने कोई नॉन जाट नेता नहीं छोड़ा। कहता है नेता सिर्फ मैं हूँ। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। किसी जमाने में कोई भाई खागड़ छोड़ा करते थे, मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, अब यह प्रथा खत्म हो गई है लेकिन वह कहता हैं कि ये खागड़ इस 35 बिरादरी के हैं और अगला मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। अध्यक्ष महोदय, किसी का बीज नहीं मरा, हर कौम में नेता है। जिस आदमी का खेल खत्म होता है या जब गीदड़ शहर की तरफ भागता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी काल यात्रा प्रारम्भ हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, आज का जो सीन था मैंने उस बारे में चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, पहले भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मैं सरकार की नीतियों के बारे में कुछ नहीं कह पाया था क्योंकि मैं उस समय हाउस में उपस्थित नहीं था। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी इजाजत से सरकार ने जो बजट पेश किया है उस पर कुछ जरूरी बातें कहना चाहता हूँ जिन पर सरकार को गौर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों कर्जा माफी की घोषणा हुई। कर्जा माफ जिन लोगों का किया गया है वह एक अच्छी बात है। हम इस पक्ष में नहीं हैं कि इसके बारे में कुछ और कहें लेकिन जो 31 जुलाई की कट आफ डेट है उससे उन लोगों में बड़ा भारी झटका लगा है जो रैगुलर पेयी हैं। जिन लोगों ने कर्जा लेकर कभी डिफाल्ट नहीं किया तो उसमें उनका क्या कसूर है इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने कर्ज लेकर रैगुलर पेमैंट की है उनको भी थोड़ा इन्सैंटिव मिलना चाहिए था। इसी प्रकार जब बिजली के बिल माफ हो रहे थे उस समय भी थोड़ी कमी रह गई थी, सरकार ने उन लोगों को कोई फैसीलिटी नहीं दी जो रैगूलर पेयी थे, उनको भी थोड़ा इन्सैंटिव देने का प्रोवीजन करना चाहिए था। जो डिफाल्टर भाई थे उनके बिल माफ किए गए उनके साथ-साथ जो रैगूलर पेयर थे उनको भी इन्सैंटिव दे दिया जाता तो अच्छी बात होती। अध्यक्ष महोदय, आन्ध्रा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसका ब्यान आया है कि बैकवर्ड निगम और मायनोरटी आदि निगमों ने जिन गरीब भाइयों को पैसा दिया हुआ है वह पैसा खेत्र ऑफ करेंगे। इसलिए मैं चाहूँता कि हमारे प्रदेश में भी जो लैंडलैस भाई हैं जिन्होंने हरिजन कल्याण निगम से, बैकवर्ड कल्याण निगम से दुकान आदि

[श्री राम कुमार गौतम]
के लिए लोन ले रखा है उसको मुख्यमंत्री जी माफ करें। मैं भी एक दो बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने हरिजन कल्याण निगम से लोन ले रखा है और पैसा नहीं दे पा रहे अगर इस तरह के लोन्ज को मुख्यमंत्री जी सदन में माफ करने की घोषणा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि जो लैंडलैस लोग हैं उनको कोई भी पैसे नहीं देता है। अगर वे किसी की जमीन पर खेती करते हैं और ओलावृष्टि आदि से फसल बरबाद हो जाती है तो मुआवजे के पैसे भी उनको नहीं मिलते क्योंकि जो जमीन के मालिक होते हैं वे उनके साथ बेईमानी कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहूँगा कि किसानों के ट्यूबवैल के लिए जहां 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है उसी तरह से आर्टिजन तबके के लोगों को भी 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जानी चाहिए जिन्हें अब 4.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने जो पैसा वेव ऑफ किया था उसमें बैकवर्ड निगम का पैसा भी वेव ऑफ किया गया था। उसमें जो नानें एग्रीकल्चरिस्ट छोटे दुकानदार और दूसरे भाई थे उनको भी रियायत दी गई थी। उसमें कोआपरेटिव बैंकस के तहत 1,060,17 लोगों ने लाभ उठाया था और 44.42 करोड़ रुपये की रियायत दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार गरीब हितैषी सरकार है, अगर गरीबों को और भी रियायत देने की जरूरत होगी तो वह हम देंगे।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं सदन का ध्यान उस खतरे की तरफ दिलाना चाहूँगा जो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। आज के दिन सभी जगहों पर रिलायंस फ्रैश, सुभिक्षा, गोदरेज आधार, 6-10 आदि कम्पनीज सब्जी और फ्रूट मार्केट में कूद पड़ी हैं। रिलायंस कम्पनी ने पंजाब का सारा धनियां खरीद लिया। ये कम्पनियां इसी तरह फैलती रही तो जो हमारे गरीब भाई हैं जिन्होंने किराये और सब्जी की छोटी-छोटी दुकानें कर रखी हैं वे कहां जायेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी ऐसा कानून बनायें कि बड़े-बड़े काम तो ये कम्पनियां करें और छोटे-छोटे काम हमारे गरीब भाईयों के लिए छोड़ दें ताकि वे भी अपना घर चला सकें। यदि ये बड़ी-बड़ी कम्पनियां छोटे-छोटे शहरों में आ जायेंगी तो छोटे दुकानदारों का खेल खत्म हो जायेगा। इसलिए इस तरफ सरकार ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी के बजट की जो पहली लाईन है उसमें लिखा है कि "It was our foremost duty to instill a sense of confidence in the people for providing clean and benevolent governance which would provide them relief from fear, intimidation and security."

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री जी से बड़ी आशाएं थीं कि मुख्यमंत्री जी करप्शन को रोकेंगे। लेकिन आज जितने भी अखबार पढ़ते हैं उनमें लिखा होता है कि फलां पटवारी रिश्वत लेते पकड़ा गया, नायब तहसीलदार भी एक आध ही पकड़े जाते हैं और वे भी वे होते हैं जिनका कोई माई बाप नहीं होता। इसके अतिरिक्त एच०सी०एस० अधिकारी और दूसरे जो बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं जिनमें बड़े अधिकारी और पॉल्टीशियन भी शामिल हैं उनकी तरफ सरकार ने हाथ नहीं बढ़ाया है। अगर मुख्यमंत्री जी करप्शन करने वालों की तरफ थोड़ा-सा ध्यान देते तो उनको पहला काम उन लोगों को पकड़कर करना चाहिए था जो करप्शन के माई बाप हैं और आज राज काज की लड़ाई लड़ने के बारे

में सोच रहे हैं। वे लोग कहीं सीन में नहीं थे और उनके खिलाफ कार्यवाही होती तो प्रदेश के लोग भी खुश होते कि उनका पैसा लूटने वाला जेलों के पीछे हैं।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, अब आप बैठें। आज आप 35 मिनट बोल चुके हैं और आप अपनी लैग्ज पर हैं, आप सोमवार को अपनी स्पीच कन्टीन्यू कर लेना।

श्री राम कुमार गौतम : ठीक है, सर। मैं सोमवार को बोल लूंगा।

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 20th March, 2008.

*13.40 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 20th March, 2008).

44394–H.V.S.—H.G.P., Chd.